जबलपुर, मंगलवार
दिनांक 24 फरवरी 2026
वर्ष 31 अंक 242
पृष्ठ 12
मूल्य ₹ 3.00
www.swatantramat.com

स्वतंत्र मत

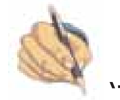

सुविचार

'शिक्षा की जड़ें भले ही कड़वी होती हैं लेकिन फल मीठा होता है'

2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने की ...
5 लूट गैंग का नया कारनामा...
7 गोवा नहीं...अब गंगा आरती है...
11 किसानों को लाभान्वित करने ...

ट्रेड डील के खिलाफ किसान महाचौपाल आज

भोपाल। 24 फरवरी को भोपाल में इंडो-यूएस ट्रेड डील के खिलाफ किसान महाचौपाल होगी। इस महाचौपाल में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे। राहुल गांधी दोपहर 1 बजे भोपाल पहुंचेंगे और दोपहर 2 बजे से कार्यक्रम होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भोपाल में राहुल गांधी से पहले पहुंचेंगे। एआईसीसी की ओर से एमपी कांग्रेस को दी गई जानकारी के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे दोपहर करीब 12 बजे भोपाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे।

डबल डेकर बस पलटी, 5 की मौत

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज में बड़ा हादसा हो गया। जौखंडी गांव में सोमवार शाम 4.30 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना में पांच लोगों की मौत हो गई व कई घायल हुए हैं। आठ यात्रियों की हालत गंभीर है उन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। हादसे के समय बस में 40 लोग सवार थे।

डिवाइडर से टकराकर पलटा पिकअप, 3 की मौत

नरसिंहपुर। नरसिंहपुर में निर्माणाधीन ब्रिज के डिवाइडर से टकराकर पिकअप वाहन पलट गया। हादसे में तीन मजदूरों की मौत हो गई जबकि 7 घायल हैं। 3 की हालत गंभीर है। सूआतला थाना पुलिस के अनुसार, हादसा सोमवार सुबह करीब 11.30 बजे बरमान चौकी क्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 पर हुआ। वाहन में कुल 10 मजदूर सवार थे। ये सभी छिंदवाड़ा जिले के सुरला खापा गांव निवासी बताए जा रहे हैं। वे नरसिंहपुर के राजमार्ग क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्य के लिए जा रहे थे। थाना प्रभारी प्रियंका केवट ने बताया कि शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

डॉक्टरों की योग्यता तय नहीं करती नीट-पीजी की परीक्षा

नई दिल्ली

नीट-पीजी 2025 के लिए क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल कम किए जाने के फैसले का बचाव करते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि नीट पीजी न्यूनतम क्लिनिकल क्षमता का प्रमाणन नहीं करता, बल्कि सीमित स्नातकोत्तर सीटों के आवंटन के लिए मेरिट सूची तैयार करने का माध्यम है। न्यूनतम योग्यता एमबीबीएस डिग्री से ही स्थापित हो जाती है। केंद्र द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि नीट पीजी स्कोर सापेक्ष प्रदर्शन और परीक्षा की संरचना पर आधारित होता है। इसे किसी उम्मीदवार की क्लिनिकल अक्षमता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी अभ्यर्थी लाइसेंस प्राप्त एमबीबीएस डॉक्टर हैं और स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस करने के पात्र हैं। रोगी सुरक्षा को लेकर उठाई गई चिंताओं को भ्रामक बताते हुए हलफनामे में कहा गया कि पोस्टग्रेजुएट प्रशिक्षण तीन वर्ष का संरचित कार्यक्रम है। प्रशिक्षण के दौरान उम्मीदवार वरिष्ठ संकाय और विशेषज्ञों की निगरानी में कार्य करते हैं। अंतिम क्षमता का आकलन एमडी/एमएस परीक्षा में होता है, जहां सिद्धांत और प्रैक्टिकल दोनों में अलग-अलग न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं।

पहले भी घटी है कटऑफ

केंद्र ने कहा कि 2017 में नीट पीजी शुरू होने के बाद से विशेष परिस्थितियों में पर्सेंटाइल में कमी की जाती रही है। वर्ष 2023 में भी सभी श्रेणियों के लिए क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल शून्य तक किया गया था, ताकि सीटें खाली न रहें। सरकार ने अदालत से कहा कि यह नीतिगत निर्णय है और जब तक यह स्पष्ट रूप से मनमाना या असंवैधानिक न हो, तब तक न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित होता है।

कितनी सीटें थीं खाली?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और नेशनल मेडिकल कमीशन ने अनुमानित रिक्त सीटों की बड़ी संख्या को देखते हुए कटऑफ घटाने का निर्णय लिया। हलफनामे के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2025-26 में लगभग 70,000 पीजी सीटें उपलब्ध थीं। 2,24,029 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। ऑल इंडिया कोटा की 31,742 सीटों में से दूसरे राउंड के बाद 9,621 सीटें खाली रहीं। इनमें से 5,213 सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में थीं। कटऑफ घटाने से अतिरिक्त 1,00,054 उम्मीदवार तीसरे राउंड के लिए पात्र हुए, जिससे कुल पात्र अभ्यर्थियों की संख्या 2,28,170 हो गई। तीसरे राउंड के बाद केवल 2,988 सीटें रिक्त रहीं।

शैक्षणिक मानकों से समझौता नहीं

हलफनामे में यह भी कहा गया कि पीजी सीटों पर भारी सार्वजनिक निवेश होता है। इन्हें खाली छोड़ना संसाधनों और प्रशिक्षण क्षमता की बर्बादी होगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर भी असर पड़ेगा। सरकार ने अंत में कहा कि पर्सेंटाइल में कमी एक अनुपातिक प्रशासनिक कदम है, जो सीटों की बर्बादी रोकने और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। सीट आवंटन अब भी मेरिट और उम्मीदवारों की वरीयता के आधार पर ही किया जाता है, इसलिए शैक्षणिक मानकों से कोई समझौता नहीं हुआ है।

यही तो है मोहब्बत की दुकान

राहुल गांधी से कोटद्वार के मोहम्मद दीपक ने की मुलाकात

नई दिल्ली/कोटद्वार। कोटद्वार के मोहम्मद दीपक ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी गर्मजोशी के साथ दीपक के गले लगे। कोटद्वार पटेल मार्ग पर एक कपड़े की दुकान के नाम को लेकर उभरे विवाद के बीच मोहम्मद दीपक चर्चा में आया था। मामले में तब और तूल पकड़ा जब राहुल गांधी ने इसे लेकर ट्वीट किया। दीपक ने नेता विपक्ष राहुल गांधी से आज नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संचार विभाग के सचिव वैभव वालिया के नेतृत्व में मुलाकात की। वालिया ने कहा कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोटद्वार के हमारे भाई दीपक कुमार को अपने आवास पर आमंत्रित कर उनसे आत्मीय मुलाकात की। दीपक कुमार जो अपने मानवीय कार्यों और इंसानियत की मिसाल के रूप में देशभर में पहचान बना चुके हैं, से राहुल गांधी ने स्नेहपूर्ण संवाद किया और उनका उत्साहवर्धन किया। यह मुलाकात केवल एक व्यक्ति का सम्मान नहीं, बल्कि समाज में मानवता, करुणा और सेवा भाव की भावना का सम्मान है। राहुल गांधी द्वारा दीपक कुमार जैसे प्रेरणास्रोत व्यक्तित्व को अपने घर पर आमंत्रित कर सम्मानित करना यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी सदैव उन लोगों के साथ खड़ी है जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य कर रहे हैं।

वॉट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

विज्ञापन कंपनियों से शेयर नहीं करेंगे डेटा

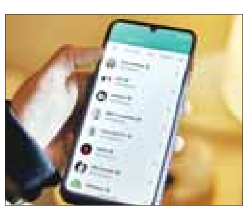

नई दिल्ली। ग्लोबल टेक कंपनियों मेटा और वॉट्सएप ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वे कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की प्राइवेसी और गाइडलाइंस को एडवरटाइजिंग से जुड़े डेटा शेयर करने के मामले में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के निर्देशों का पालन करेंगे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच पिछले साल दिसंबर में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के निर्देशों के खिलाफ इन टेक कंपनियों की अपील पर सुनवाई कर रही थी। सीजेआई की सख्ती के बाद वॉट्सएप और मेटा ने कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के आदेशों को स्वीकार कर लिया। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भरोसा दिया कि 16 मार्च 2026 तक प्राइवेसी पॉलिसी के सभी नियम लागू कर दिए जाएंगे। कंपनी ने इस संबंध में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ दायर अपनी अंतरिम अर्जी वापस ले ली। कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी है। अब यूजर को विज्ञापन कंपनियों को डेटा शेयर करने का ऑप्शन देना होगा।

दिल्ली-एनसीआर से हटेंगे कोयला आधारित उद्योग

300 किमी दायरे वाले प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों को कई अहम निर्देश दिए हैं और अलग-अलग मुद्दों पर जवाब तलब किया है। अदालत ने खास तौर पर कोयला आधारित उद्योगों, निर्माण और तोड़फोड़ के दौरान उड़ने वाली धूल और वाहनों के प्रदूषण को लेकर उठाए गए कदमों का ब्योरा मांगा है। नेशनल कैपिटल रीजन में लगातार वायु गुणवत्ता की दिक्कत से निपटने के लिए सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि वह कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के सुझावों के आधार पर 12 मार्च को गाड़ियों से होने वाले वायु प्रदूषण के मुद्दे की जांच करेगी। इसने भवन निर्माण और तोड़-फोड़ की वजह से होने वाली धूल से निपटने के लिए सीएक्यूएम के सुझाए गए तरीकों पर सभी स्टेकहोल्डर्स से भी जवाब मांगा। पीठ ने इस सुझाव पर भी केंद्र से जवाब मांगा कि दिल्ली से 300 किलोमीटर के दायरे में कोई नया कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित न किया जाए। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को सार्वजनिक नोटिस जारी कर एनसीआर में संचालित कोयला आधारित उद्योगों सहित सभी हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित करने का निर्देश दिया गया।इन नोटिसों को कोर्ट द्वारा भेजा गया नोटिस माना जाएगा और राज्यों को मिले फीडबैक की डिटेल देते हुए एक एक्शन टेकन प्लान जमा करने को कहा गया है। अदालत ने अब इस मामले की सुनवाई के लिए 12 मार्च की तारीख तय की है।

मेरे कोर्ट में बदतमीजी नहीं चलेगी

अंबानी का जिक्र करने पर वकील पर भड़के सीजेआई

नई दिल्ली। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत सोमवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान वकील की बात पर इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने वकील को लगभग डांटते हुए चेतावनी दे डाली कि उनकी कोर्ट में ये बदतमीजी नहीं चलेगी। दरअसल वरिष्ठ वकील मैथ्यूज नेदुम्पारा ने सीजेआई की पीठ के समक्ष कहा कि एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें न्यायपालिका के कॉलेजियम सिस्टम को चुनौती दी गई और जजों की नियुक्ति के लिए नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लागू करने की मांग की गई। जिस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ऐसी कोई याचिका रजिस्टर नहीं है। इस पर वकील नेदुम्पारा ने नाराजगी जाहिर की और कहा, अदाणी और अंबानी के लिए सांविधानिक पीठ गठित की जाती हैं और आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई ही नहीं होती। वकील की इस बात से सीजेआई नाराज हो गए और उन्होंने तुरंत वकील नेदुम्पारा को चेतावनी दी कि मिस्टर नेदुम्पारा, आप मेरी अदालत में जो कह रहे हैं, उसे सोच-समझकर बोलिए। आपने चंडीगढ़ में भी मुझे देखा है, दिल्ली में भी...। ये मत सोचिए कि जैसे आप दूसरी पीठ के साथ बदतमीजी करते रहे हैं, वैसे ही आप मेरी कोर्ट में भी बदतमीजी करेंगे। मैं आपको चेतावनी देता हूं।

भोजशाला: हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों से आपत्तियां-सुझाव मांगे

इंदौर

धार स्थित भोजशाला मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सभी याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की सर्वे रिपोर्ट पर दो सप्ताह के भीतर अपनी आपत्तियां, सुझाव और सिफारिशें प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि एएसआई की रिपोर्ट पहले ही खोली जा चुकी हैं और उसकी प्रतियां याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध करा दी गई हैं। ऐसे में रिपोर्ट को दोबारा कोर्ट के समक्ष अनसील करने की आवश्यकता नहीं है। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को निर्देशित किया कि वे एएसआई की 98 दिन तक चली वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट पर अपनी लिखित आपत्तियां और सुझाव अगली सुनवाई से पहले दाखिल करें। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से अधिवक्ता विनय जोशी ने कहा, कोर्ट के निर्देशानुसार हम दो सप्ताह के भीतर एएसआई रिपोर्ट पर अपनी आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत करेंगे। मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी।

पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल रॉय का निधन

कोलकाता (वार्ता)

पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ राजनेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं विधायक मुकुल रॉय का रविवार देर रात कोलकाता में निधन हो गया। वह 71 साल के थे। उनका लंबे समय से शहर के एक निजी अस्पताल में गुर्दे से जुड़ी दिक्कतों समेत कई बीमारियों का इलाज चल रहा था। मुकुल रॉय को इलाज के दौरान दिल का दौरा पड़ा था। उनके निधन से पूरे राजनीतिक माहौल में मातम छा गया है। मुकुल रॉय को अक्सर बंगाल राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। वह कई सालों से सेहत से जुड़ी दिक्कतों से जूझ रहे थे और अक्सर अस्पताल में भर्ती रहते थे। उनके हाल के सालों में राजनीतिक करियर में कई उतार-चढ़ाव आए। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने 2021 का विधानसभा चुनाव कृष्णानगर उत्तर से भाजपा के टिकट पर लड़ा और जीत हासिल की। बाद में वह तृणमूल कांग्रेस में लौट आए लेकिन उन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफ़ा नहीं दिया और रिकॉर्ड में भाजपा विधायक बने रहे। बाद में उन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। मुकुल रॉय की विधायकी को रद्द करने की कानूनी कार्रवाई अदालत तक पहुँची और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इसे रद्द करने का आदेश दिया था, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इस फैसले पर रोक लगा दी। मुकुल रॉय ने तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक सदस्य बनने से पहले कांग्रेस के साथ अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। उन्होंने राज्यसभा सदस्य के तौर पर काम किया और केंद्र में शिपिंग और बाद में रेलवे सहित अहम मंत्रालय संभाले थे।

हमले के लिए तैयार अमेरिका?

भारत ने अपने नागरिकों से कहा- तुरंत ईरान से निकलें

नई दिल्ली

भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों को किसी भी तरीके से तुरंत ईरान से निकलने की सलाह दी है। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने 14 जनवरी को भी एडवाइजरी जारी कर सभी नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दी थी। विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी में ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों से कहा कि वे सावधानी बरतें, प्रदर्शन वाली जगह जानें से बचें और भारतीय दूतावास के संपर्क में रहे। विदेश मंत्रालय ने ये भी कहा कि नागरिक अपने यात्रा और अप्रवासन संबंधी दस्तावेज जैसे पासपोर्ट और पहचान पत्र आदि अपने साथ रखें। नागरिकों को भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराने की सलाह भी दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि ईरान में रह रहे लोगों के परिजन भी दूतावास में अपने प्रियजनों के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। भारत की एडवाइजरी ऐसे समय सामने आई है, जब पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है। अमेरिका ने अपने दो युद्धपोत ईरान के आसपास तैनात किए हुए हैं और साथ ही अपने लड़ाकू विमानों को भी पश्चिम एशिया में तैनात किया है।

घाटी में कर दिया जैश का खात्मा!

326 दिनों तक चला हाई-एल्टीट्यूड ऑपरेशन

जम्मू।

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में 326 दिनों तक चले हाई-एल्टीट्यूड ऑपरेशन में सात खतरनाक आतंकवादी मारे गए हैं। भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर (16 कोर) ने सोमवार को यह जानकारी दी। व्हाइट नाइट कोर ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि किश्तवाड़ इलाके में 326 दिनों तक लगातार हाई-एल्टीट्यूड अभियान चलाए गए। सेना ने मुश्किल इलाकों में ठंडे, गीले और बर्फीले मौसम के बीच आतंकवादियों को ट्रैक किया। इस दौरान कई बार मुठभेड़ हुई। व्हाइट नाइट कोर की टुकड़ियों, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने खुफिया एजेंसियों के मजबूत खुफिया तंत्र के आधार पर आखिरकार किश्तवाड़ के चटरू क्षेत्र में सभी सात कुख्यात आतंकवादियों को मार गिराया। इनमें से एक 10 लाख का इनामी आतंकी कमांडर सैफुल्लाह के होने का संदेह है। अगर जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर सैफुल्ला है तो सुरक्षाबलों की ये सफलता जैश के नेटवर्क की कमर तोड़ने में अहम भूमिका निभाएगी। पोस्ट में आगे कहा गया, ऑपरेशन में मदद के लिए एफपीवी ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी, आरपीए/यूएवी और संचार साधनों के रूप में टेक्नोलॉजी का लगातार इस्तेमाल किया गया। हमारी सेनाओं की लगातार कोशिश और दृढ़ संकल्प, जिसका नतीजा सैफुल्लाह और उसके साथियों का खत्म होना था, यह साबित करता है कि हमारे जवानों और इंटेलिजेंस एजेंसियों के संकल्प, साहस और वीरता के सामने कुछ भी नहीं टिक सकता।

आतंकी नेटवर्क पर एक बड़ा प्रहार

भारतीय सेना ने कहा कि यह आतंकी नेटवर्क पर एक बड़ा प्रहार है। हम सेवा और सुरक्षा करते हैं। व्हाइट नाइट कोर ने मारे गए आतंकदियों की तस्वीर भी शेयर की है, जिसके ऊपर लाल रंग में क्रॉस लगे हुए हैं। इससे पहले, सेना ने एक संयुक्त अभियान में तीन आतंकवादियों को मार गिराया। ऑपरेशन त्रासी-1 के तहत किश्तवाड़ में इन आतंकियों को मारा गया। व्हाइट नाइट कोर ने जानकारी दी कि आतंकवादी के अवशेष और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। सेना ने कहा, स्थिरता को कमजोर करने वालों के लिए कोई जगह, कोई पनाहगाह नहीं है।

एक दर्जन से ज्यादा एनकाउंटर हुए

पिछले साल किश्तवाड़ के घने जंगल वाले चटरू इलाके में ज्वाइंट फोर्स और पाकिस्तानी जैश-ए-मोहम्मद (जैश) के आतंकवादियों के बीच एक दर्जन से ज्यादा एनकाउंटर हुए। भारतीय सेना आतंकवादियों को पीछा करती रही, लेकिन वह जम्मू डिवीजन के किश्तवाड़, डोडा, कठुआ और उधमपुर जिलों के बीच अपनी जगह बदलते रहे।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने की हाईकोर्ट के आदेशानुसार मानदेय वृद्धि और बकाया राशि भुगतान की मांग

डिंडौरी (स्वतंत्र मत)

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका संगठन बुलंद आवाज नारी शक्ति ने प्रदेश सरकार से उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश के पालन हेतु आवेदन किया है। संगठन की प्रांताध्यक्ष रामेश्वरी मेश्राम और जिलाध्यक्ष सुमन बघेल ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि 27 जून 2019 से पहले दिए गए मानदेय में अपनी हिस्सेदारी बहाल की जाए और बकाया राशि 6ल वार्षिक ब्याज दर के साथ 120 दिनों के भीतर भुगतान की जाए।

आवेदन में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में उचित वृद्धि की जाए, ताकि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन बिना किसी आर्थिक बाधा के कर सकें। संगठन ने यह भी उल्लेख किया कि सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली के आदेश और उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए नए आदेश छह महीनों के भीतर जारी किए जाएँ।

संगठन के अनुसार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएँ बच्चों की देखभाल, पोषण और शिक्षा में अहम भूमिका निभाती हैं। उनके कार्य की सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से अत्यधिक महत्ता है, लेकिन पिछले कई वर्षों से उनका मानदेय समय पर नहीं बढ़ाया गया और बकाया राशि लंबित रही।

प्रांताध्यक्ष रामेश्वरी मेश्राम ने कहा, हमारी मांग केवल आर्थिक नहीं बल्कि न्यायसंगत है। न्यायालय के आदेश का पालन कर सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हक और सम्मान को सुनिश्चित करे।

जिलाध्यक्ष सुमन बघेल ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राज्य के हर बच्चे की सुरक्षा और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, इसलिए उनके मेहनत का उचित मूल्य और समय पर भुगतान सुनिश्चित होना चाहिए।

आवेदन में मुख्यमंत्री महोदय से यह भी अनुरोध किया गया है कि आवेदन और न्यायालय के आदेशों की प्रमाणित प्रति स्वीकार की जाए और निर्देशित समय सीमा के भीतर नया आदेश जारी कर भुगतान प्रक्रिया शुरू की जाए।

संगठन ने आशा जताई कि सरकार उच्च न्यायालय के आदेश का शीघ्र पालन करेगी, जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और वे अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा से कर सकेंगी।

मीडिया सुर्खियों के बीच यातायात व्यवस्था को लेकर एसपी ने बदला कार्यभार

डिंडौरी (स्वतंत्र मत)

विगत दिनों डिंडौरी जिले में यातायात व्यवस्था को लेकर तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार खबरें प्रकाशित होती रही हैं, जिनमें शहर की अव्यवस्थित यातायात स्थिति को लेकर सवाल खड़े किए गए। इन खबरों में विशेष रूप से यातायात थाना प्रभारी सुभाष ऊईके की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे, जिससे मामला सुर्खियों में बना हुआ था।

इसी पृष्ठभूमि में पुलिस अधीक्षक जिला डिंडौरी (म.प्र.) श्रीमती वाहनी सिंह द्वारा वर्ष 2026 के अंतर्गत कार्य वितरण आदेश जारी करते हुए विवेक कुमार गौतम, अनु. अधि. पु. बजाग को यातायात डिण्डौरी के पर्यवेक्षण का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि वे अपने अनुभाग बजाग के कार्यों के साथ-साथ यातायात डिंडौरी के कार्यों का सतत पर्यवेक्षण करेंगे।

इसके साथ ही निरीक्षक संतोष धुर्वे, रक्षित केंद्र डिण्डौरी को सहायतार्थ नियुक्त किया गया है, जो सौंपे गए दायित्वों का विधिवत निर्वहन करेंगे। यह आदेश दिनांक 23 फरवरी 2026 को क्रमांक पुअ/डि/निस/49/2026 के तहत जारी किया गया है। आदेश की प्रतिलिपि समस्त राजपत्रित अधिकारियों, थाना-चौकी प्रभारियों एवं संबंधित शाखाओं को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भेजी गई है। माना जा रहा है कि हालिया मीडिया रिपोर्ट्स और जनचर्चा के बीच लिया गया यह निर्णय जिले की यातायात व्यवस्था को अधिक प्रभावी, अनुशासित एवं नियंत्रित करने की दिशा में एक अहम प्रशासनिक कदम है।

जिले में 24 अमृत सरोवर फेल, कलेक्टर ने बनाई सख्त जांच समिति, 7 दिनों में देना होगा जांच रिपोर्ट

डिंडौरी (स्वतंत्र मत)

जिले में 24 अमृत सरोवरों के निर्माण में असफलता की जानकारी मिलने के बाद जिला कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने तत्काल जांच दल गठित कर दिया है यह कार्रवाई ग्रामीण यांत्रिकी सेवा डिण्डौरी के कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर की गई है। बता दें कि जिला पंचायत डिण्डौरी ने 24 अप्रैल 2025 के आदेश के माध्यम से गठित पूर्व जांच समिति द्वारा समय पर रिपोर्ट न सौंपने के कारण पुनः जांच दल का गठन किया कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जांच दल सात दिन के भीतर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। वहीं जांच दल में शामिल सदस्य हैं, नारायण देशमुख अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन विभाग डिण्डौरी, प्रदीप शुक्ला परियोजना अधिकारी मनरेगा जिला पंचायत डिण्डौरी और स्टीफन एक्का परियोजना अधिकारी वाटर शेड जिला पंचायत डिण्डौरी । जांच दल को निर्देश दिया गया है कि वे संबंधित सभी दस्तावेज और जानकारी उपलब्ध कराएँ और जनपद पंचायत अमरपुर बजाग डिण्डौरी करंजिया सगनापुर और शहपुरा के मुख्य अधिकारियों से सहयोग लें कलेक्टर कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि यह कदम अमृत सरोवर योजना की गुणवत्ता समयबद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है जिले में अमृत सरोवर योजना के तहत पेयजल संकट को दूर करने के उद्देश्य से यह योजना महत्वपूर्ण मानी जाती है।

जिला में पेयजल संकट से नाराज ग्रामीणों ने किया सड़क जाम, धुर्रा तिराहा पर प्रदर्शन

डिंडौरी (स्वतंत्र मत)

जिला मुख्यालय के समीप ग्राम पंचायत धुर्रा में पेयजल की गंभीर समस्या को लेकर सोमवार दोपहर करीब 11 बजे ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। पानी नहीं मिलने से परेशान ग्रामीणों ने धुर्रा तिराहा सड़क पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे कुछ समय के लिए आवागमन प्रभावित रहा। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत धुर्रा में पिछले 4ङ्क5 दिनों से पेयजल आपूर्ति बाधित है। बताया गया कि हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में ऋ्रब्स विभाग द्वारा बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री लैब का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसी निर्माण के दौरान खुदाई में पानी की सप्लाई लाइन (पाइपलाइन) टूट गई, जिससे पूरे क्षेत्र में पानी की आपूर्ति ठप हो गई। लगातार पानी नहीं मिलने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजबूरी में ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया और प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग की। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने कहा कि कई बार शिकायत के बावजूद अब तक पाइपलाइन की मरम्मत नहीं की गई, जिससे हालात दिन-ब-दिन बिगड़ते जा रहे हैं। सूचना मिलने पर संबंधित विभाग व प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों को समझाइश देकर जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद स्थिति सामान्य हुई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र पेयजल आपूर्ति बहाल नहीं की गई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

नाबालिग बच्ची को दस्तयाब नहीं करने पर परिजनों ने पुलिस पर लगाया आरोप

ब्यौहारी (स्वतंत्रमत)। जिले के ब्यौहारी थाना अन्तर्ग 20 जनवरी को गोदावल मेला से एक 14 साल की नाबालिक लड़की मेले से गायब हो गयी थी। परिजनों की सूचना पर थाना ब्यौहारी मे 28 जनवरी को अज्ञात पर मामला दर्ज किया गया था किन्तु नाबालिक लड़की का दस्तयाब ब्यौहारी पुलिस द्वारा अभी तक नहीं किया गया है। लड़की के माँ बाप और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का आरोप है कि ब्यौहारी पुलिस लड़की की खोजबीन नही कर रही है। छतैनी निवासी फरियादी ने बताया कि मेरे तीन लड़की और 2 लडके है। 03 लडके बच्चों की शादी कर दिया हूँ। सबसे छोटी लड़की 14 वर्ष 8 माह की थी वह 20 जनवरी को अपने परिवार के साथ गोदावल मेला देखने गयी थी। वह दोपहर 2 बजे अचानक कंही चली गयी जिसकी पता तलास मेला मे किया गया नहीं मिली तब घर आकर आस पड़ोस, नात रिस्तेदारो से पूंछा किन्तु वंहा भी कोई पता नहीं चला।

संयुक्त सचिव भारत सरकार दीपक मिश्रा ने पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का किया निरीक्षण

शहडोल (स्वतंत्रमत)। भारत सरकार के संयुक्त सचिव दीपक मिश्रा एवं कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने पी.एम. श्री केंद्रीय विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों उपलब्ध स्टाफ तथा बच्चों की संख्या के संबंध में जानकारी प्राप्त की। प्राचार्य प्रीति मिश्रा ने बताया कि विद्यालय में स्वीकृत पद के अनुसार शिक्षक पदस्थ हैं, विद्यालय में कक्षाओं का संचालन स्मार्ट क्लास के माध्यम से किया जाता है। विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति अभिरुचि बढ़ाने हेतु शिक्षकों द्वारा नवाचार किए जाते हैं हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में विद्यार्थियों के लिए शिक्षा उपलब्ध है। छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति अभिरुचि बढ़ाने के लिए जादुई पिटारा के माध्यम से विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है। संयुक्त सचिव दीपक मिश्रा ने विद्यालय को मिलने वाले बजट तथा उसके उपयोग के संबंध में भी प्राचार्य से जानकारी प्राप्त की। प्राचार्य द्वारा बताया गया कि शत प्रतिशत बजट का उपयोग विद्यालय में कर लिया जाता है। विद्यालय में संचालित वार्षिक कैलेंडर सांस्कृतिक खेल-कूद गतिविधियों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की गई। कलेक्टर डॉ.केदार सिंह ने बताया कि विद्यालय में शैक्षणिक माहौल बहुत अच्छा है, गुणवत्ता युक्त शिक्षा दिए जाने से विद्यार्थियों में अनुशासन के साथ-साथ अन्य गतिविधियों में भी सफलता अर्जित की जा रही है। सभी शिक्षक ईमानदारी के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। शाला परिसर पहुंचने पर दीपक मिश्रा का परंपरागत रूप से फूल का पौधा भेंट कर स्वागत किया गया तत्पश्चात उन्होंने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तथा प्रतीक स्वरूप पौधारोपण भी किया।संयुक्त सचिव दीपक मिश्रा ने स्कूल परिसर का भ्रमण कर साफ सफाई, शैक्षणिक कक्षाओं, प्रायोगिक लैब का निरीक्षण भी किया।

पंडित शंभूनाथ शुक्ल विवि में भारतीय ज्ञान परंपरा का साकार रूप

25 फरवरी को होगा भव्य पंचम दीक्षांत समारोह

शहडोल (स्वतंत्रमत)। पंडित शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय केवल अकादमिक उत्कृष्टता का केंद्र ही नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा के व्यावहारिक क्रियान्वयन का सशक्त उदाहरण बनकर उभर रहा है।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यहाँ भारतीय ज्ञान-परंपरा को केवल सैद्धांतिक विमर्श तक सीमित न रखते हुए उसे शैक्षणिक एवं प्रशासनिक परिवेश में व्यवहारिक रूप से आत्मसात किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राएँ तथा समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ दैनिक जीवन में भारतीय चिंतन की मूल जीवन-दृष्टिकृसंयम, अनुशासन, आत्मचिंतन और समरसताकृको अपनाते हुए आत्मविकास की दिशा में अग्रसर हैं। सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से विद्यार्थियों और कर्मचारियों की मानसिक एवं बौद्धिक क्षमताओं के संवर्धन हेतु नियमित रूप से मेडिटेशन, बीज मंत्र साधना एवं हार्ट हीलिंग जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

इन कार्यक्रमों के सकारात्मक परिणाम स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहे हैंकृप्रतिभागियों में मानसिक संतुलन, आंतरिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और एकाग्रता में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। पर्यावरणीय चेतना के क्षेत्र में भी विश्वविद्यालय सतत सक्रिय है। नियमित वृक्षारोपण अभियान के माध्यम से छात्र-छात्राओं में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, संरक्षण और उत्तरदायित्व की भावना विकसित की जा रही है। विश्वविद्यालय परिसर हरित चेतना का जीवंत उदाहरण बनता जा रहा है। इसी कड़ी में विश्वविद्यालय का पंचम दीक्षांत समारोह आगामी 25 फरवरी को विश्वविद्यालय परिसर, नवापुर, शहडोल में भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा।

समारोह में भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का अनुपालन विशेष आकर्षण रहेगा। कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रगीत का गायन विश्वविद्यालय के संगीत विभाग के छात्र-छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जो समारोह की गरिमा और सांस्कृतिक वैभव को और अधिक समृद्ध करेगा। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 11.30 बजे माननीय कुलाधिपति के विश्वविद्यालय आगमन एवं पंडित शंभूनाथ शुक्ल की प्रतिमा पर माल्यार्पण से होगा। इसके पश्चात कार्यपरिषद की औपचारिक बैठक आयोजित की जाएगी। 11.41 बजे दीक्षांत शोभायात्रा अतिथि भवन से प्रस्थान कर समारोह स्थल पहुँचेगी।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा बैठक संपन्न लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश

डिंडौरी (स्वतंत्र मत)

कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में जिले में संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं, विकास कार्यों एवं जनहित से जुड़े प्रकरणों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की। बैठक में सीईओ जिला पंचायत, अतिरिक्त सीईओ जिला पंचायत, एसडीएम बजाग, एसडीएम डिंडौरी, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, लीड बैंक, आयुष अधिकारी, पीआईयू, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों की गहन समीक्षा करते हुए 50 से 100 दिवस से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का निराकरण दो दिवस के भीतर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शिकायतों के निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभाग समय-सीमा का कड़ाई से पालन करें।

जल जीवन मिशन एवं नल-जल योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को निर्देशित किया कि जिले की सभी ग्राम पंचायतों में पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो, ताकि आमजन को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। जिन ग्राम पंचायतों में योजना हस्तांतरित होने के बाद भी जल प्रदाय नहीं हो रहा है, वहां संबंधित सरपंच एवं सचिव के विरुद्ध एसडीएम एवं सीईओ जनपद द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए।

जबलपुर से अमरकंटक मार्ग के निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को ग्राम पंचायत गाड़ासरई में सड़क के दोनों ओर नाली निर्माण करने तथा ग्राम शक्का में पेयजल पाइपलाइन से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। निर्माण कार्यों के कारण आमजन को हो रही असुविधा पर गंभीरता बरतते हुए उन्होंने कहा कि समय पर कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

धन-धान्य योजना अंतर्गत कृषि, महिला एवं बाल विकास, मत्स्य, सहकारिता, एनआरएलएम एवं पशुपालन विभागों को कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने शुक्रवार तक सभी हितग्राही मूलक योजनाओं की सूची तैयार कर कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करने को कहा, ताकि योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जा सके।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला अधिकारी एवं कर्मचारियों को सम्मानित किए जाने के लिए सभी विभागों से नामों की सूची शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। शासन के निर्देशानुसार प्रारंभ होने वाली जनगणना की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने 26 एवं 27 फरवरी को आयोजित प्रशिक्षण में सभी संबंधित अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा।

खाद्य विभाग को ग्रामीण अंचलों में निवासरत पात्र हितग्राहियों के उवला गैस कनेक्शन एवं ई-केवाईसी पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही जिला चिकित्सालय को एएनसी पंजीयन, सिकल सेल जांच, समर्पण सेवा अभियान, यूडीआईडी, मेडिकल प्रमाण पत्र, उपकरण चिन्हांकन एवं वितरण तथा पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए, ताकि कोई भी दिव्यांगजन शासन की योजनाओं से वंचित न रहे।पीएम किसान कुसुम सौर ऊर्जा योजना के अंतर्गत जनपद स्तर पर क्लस्टर बनाकर नदी किनारे खेती करने वाले किसानों की सूची तैयार करने तथा 3, 5 एवं 7 एचपी के सौर ऊर्जा पंप उपलब्ध कराने की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश विद्युत विभाग को दिए गए। इसके अतिरिक्त न्यायालयीन प्रकरण, समग्र आईडी, ई-केवाईसी, सीपी ग्राम, पीएम जनमन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्कूलों में शौचालयों की साफ-सफाई, नगरीय निर्माण कार्यों की प्रगति तथा राजस्व प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने बंटवारा, सीमांकन, नामांतरण, फौतीनामा एवं राजस्व वसूली के मामलों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने को कहा। नीति आयोग के निर्देशानुसार जिले के तीन विकासखंडों में 28 जनवरी 2026 से 15 अप्रैल 2026 तक संचालित 'सम्पूर्णता अभियान' के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा की गई। कलेक्टर ने शिक्षा, महिला एवं बाल विकास तथा पशुपालन विभाग को अभियान को परिणामोन्मुखी ढंग से संचालित कर अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए।

बैठक के अंत में कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि यदि वे किसी अन्य कार्यक्रम में व्यस्त हों तो अपने स्थान पर अधिकृत अधिकारी को भेजें तथा अनुपस्थिति की सूचना पूर्व में अनिवार्य रूप से दें। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों द्वारा किए गए भूमिपूजन के निर्माण कार्यों को बरसात से पूर्व पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए गए।

कलेक्टर ने की सीएम हेल्पलाइन एवं समय-सीमा पत्रों की समीक्षा

लंबित शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निराकरण के दिए निर्देश

शहडोल (स्वतंत्रमत)। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह द्वारा कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में सीएम हेल्पलाइन एवं समय-सीमा के पत्रों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीएम हेल्पलाइन में 100 दिवस या उससे अधिक समय से लंबित शिकायतों का प्राथमिकता के साथ गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों का निराकरण केवल औपचारिक न होकर नागरिकों की संतुष्टि को ध्यान में रखते हुए किया जाए। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन की नियमित मॉनिटरिंग जिला स्तरीय अधिकारी स्वयं करें तथा शिकायतों के निराकरण से संबंधित जवाब एल-1 अधिकारियों के माध्यम से अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी शिकायत अनअटेंडेड न रहे, इसके लिए मैदानी अमले को भी जिम्मेदारी सौंपी जाए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जो विभाग सी या डी श्रेणी में हैं वे सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों के निराकरण में प्रगति लाएं तथा ए श्रेणी में आने के लिए रणनीति बनाकर कार्य करें। लगातार सी एवं डी श्रेणी में आने वाले विभागों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के भी उन्होंने निर्देश दिए। जिन विभागों में शिकायतों की संख्या कम है, वहां शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शिवम प्रजापति, अपर कलेक्टर सरोधन सिंह, डिप्टी कलेक्टर अन्तोनिआ एक्का, अर्चना मिश्रा, गैलेक्सी नागपुरे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

मां से सीखने को मिलती है प्रथम भाषा

अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर हितकारिणी महाविद्यालय देवताल में हुए विविध आयोजन

जबलपुर (स्वतंत्र मत)।

हितकारिणी विज्ञान वाणिज्य एवं कला महाविद्यालय, देवताल गढ़ा में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य मातृभाषाओं के संरक्षण, संवर्धन एवं उनके महत्व को जन-जन तक पहुंचाना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत मातृभाषा के महत्व पर विचार व्यक्त करते हुए महाविद्यालय के हिंदी विभाग की प्राध्यापिका डॉ. पुष्पा शुक्ला के उद्बोधन से हुई। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व की सभी मातृभाषाओं का सम्मान करना तथा भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि मातृभाषा वह प्रथम भाषा है जिसे हम अपनी मां से सीखते हैं। इसी भाषा में हम सपने देखते हैं, भावनाएँ व्यक्त करते हैं और जीवन के प्रारंभिक संस्कार ग्रहण करते हैं। मातृभाषा केवल संवाद का माध्यम ही नहीं, बल्कि हमारी पहचान, संस्कृति और परंपरा की आत्मा है। उन्होंने आगे कहा कि वैश्वीकरण के इस दौर में विदेशी भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है, किंतु अपनी मातृभाषा की उपेक्षा करना उचित नहीं है। जब कोई भाषा लुप्त होती है तो उसके साथ एक संपूर्ण संस्कृति, इतिहास और सभ्यता भी समाप्त हो जाती है। महान वैज्ञानिकों, साहित्यकारों और विचारकों ने अपनी मातृभाषा में सोचकर ही उच्च शिखर प्राप्त किए हैं। अत: हमें गर्व के साथ अपनी मातृभाषा को अपनाना और उसका अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। महाविद्यालय की उपप्राचार्य डॉ. ममता पाठक ने अपने उद्बोधन में विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपनी मातृभाषा का सम्मान करें, उसे सुरक्षित रखें और आने वाली पीढ़ियों तक सहेजकर पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि मातृभाषा व्यक्ति की पहचान, संस्कृति और भावनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। अपनी भाषा के माध्यम से ही हम अपने संस्कारों और परंपराओं को आगे बढ़ा सकते हैं।

भाषण, पोस्टर प्रतियोगिता का हुआ आयोजन

कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा कविता पाठ, भाषण, पोस्टर, निबंध तथा लोकभाषाओं से संबंधित प्रस्तुतियां दी गईं। प्रतिभागियों ने हिंदी सहित विभिन्न भाषाओं की सुंदरता और उपयोगिता पर अपने विचार साझा किए।

कार्यक्रम के समापन पर सभी ने मातृभाषा के सम्मान तथा दैनिक जीवन में उसके अधिकाधिक प्रयोग का संकल्प लिया। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉ. पुष्पा शुक्ला द्वारा किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकगण–डॉ. संगीता शुक्ला, डॉ. वर्षा दुबे, अंजना मिश्रा, डॉ. मीना बेन, सरिता शर्मा, अंकिता चंसोरिया, मोनिका पांडे, सौम्या शुक्ला, संदीप परिहार–एवं कर्मचारियों की उपस्थिति रही।

सड़क निर्माण में आ रही भ्रष्टाचार की बू: एमबीएम

शहपुरा रेलवे ओवरब्रिज का हिस्सा गिरने पर कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन

जबलपुर (स्वतंत्र मत)।

रविवार को शहपुरा रेलवे ओवरब्रिज का एक हिस्सा गिरने के मामले में मध्य भारत मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा अफसरों और ठेकेदार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए नकली नोटों से भरा बोरा लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया। मध्य भारत मोर्चा के अध्यक्ष सौरभ यादव ने बताया कि हाल ही में दिसंबर महीने में इस सड़क का हिस्सा टूट गया था। इसके बाद अब दोबारा सड़क का दूसरा हिस्सा टूट गया। ये कहीं न कहीं अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत है। जिन्होंने आपस में पैसा बांटकर सड़क को गुणवत्ताहीन बना दिया।

दोषी अधिकारियों पर हो कार्यवाही –अध्यक्ष सौरभ यादव ने कहा कि जितना जवाबदार ठेकेदार है उतना ही जवाब देह जिम्मेदार अधिकारी और इंजीनियर भी है जो सड़क की गुणवत्ता की जांच करते है उन अधिकारी पर भी एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि राज मार्ग से रोज हजारों लोगो का आवागमन होता है।

इस हादसे में किसी की जन हानि हो जाती तो किसी जवाब देही होती। मोर्चा के सदस्यों ने संयुक्त कलेक्टर को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंप कर दोषी अधिकारियों के ऊपर संवैधानिक कारवाही की मांग की।

इस दौरान दिलीप विश्वकर्मा, निहाल यादव, सोनू साहू, आकाश, राजा बाबा, जानू शर्मा, बल्लू पटेल, निक्की विश्वकर्मा, शोभित राजपूत, डीके, सुमित आदि उपस्थित रहे।

दमदार दांव-पेच प्रदर्शन के साथ इंदौर बना चैंपियनशिप विजेता

जबलपुर (स्वतंत्र मत)।

जिला एमेच्योर कुश्ती संघ के तत्वावधान में आयोजित अंडर-15 राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का समापन 23 फरवरी को पीएनटी ग्राउंड, रानीताल में उत्साहपूर्ण वातावरण में हुआ। तीन दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में प्रदेशभर से लगभग 150 बालक एवं बालिका पहलवानों ने विभिन्न भार वर्गों में अपने दमदार दांव-पेच का प्रदर्शन किया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जिला कार्यवाहक नंदकिशोर पटेल, मप्र हॉकी संघ के अध्यक्ष नितिन ढिमोले, डॉ. पुष्पराज पटेल, हेली पाजी, राहुल रोहाणी, अंकित चौधरी, राहुल जैन, एड अर्नव तिवारी, राजेश पहलवान, अमर पहलवान, विक्की सोनकर, सुबोध साहू, गोपाल पटेल सहित अनेक गणमान्यजन उपस्थित रहे। इस वर्ष की चैंपियनशिप इंदौर टीम ने जीती और उन्हें प्रतियोगिता की ट्रॉफी प्रदान की गई। आयोजन समिति के अध्यक्ष शिवम तिवारी का पगड़ी बंधन कर स्वागत किया गया। अध्यक्ष शिवम तिवारी ने सभी प्रतिभागियों, कोचों एवं सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने का सशक्त मंच प्रदान करती हैं। कार्यक्रम में अध्यक्ष उमाशंकर पटेल, सचिव राजेश राजपूत, प्रो रेसलिंग सीईओ राहुल तुषार सिंह, आयोजन समिति अध्यक्ष शिवम तिवारी, शेरू रैकवार आदि उपस्थित रहे।

सीजीएचएस की मासिक बैठक संपन्न

जबलपुर।

केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) डिस्पेंसरी क्रमांक 4 में मासिक बैठक का आयोजन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आरपी रावत की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में नगर के विभिन्न सीनियर सिटीज़न संगठनों के सलाहकार प्रतिनिधि अरविंद पटेल, अनिल शुक्ला, दिलीप कुंडे, किशन लाल एवं अर्जुन सिंह ने भाग लेकर स्वास्थ्य सेवाओं से लाभार्थियों को मिल रही बेसिक सुविधाएं जैसे शुद्ध पीने के पानी के लिए पानी टँकी, वाटर कूलर, एयर कूलर, फैनों की नियमित साफ सफाई कराना, अधिकृत अस्पतालों के स्पेसलिस्ट डॉक्टरों लिखी दवाइयों की उपलब्धता व परामर्श सेवाओं के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में डॉ एलिस सराफ, डॉ राजीव यादव, डॉ एसके राय, स्टाफ के प्रभारी मनोज कुमार, प्रदीप सिंह, लव डांगी आदि उपस्थित रहे।

घूसखोर पंडत के निर्देशक और नेटफ्लिक्स को न्यायालय ने जारी किया नोटिस

शीर्षक से जुड़ा मामला, जेएमएफसी में बयान हुए दर्ज

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। फिल्म घूसखोर पंडत के विवादित शीर्षक को लेकर ब्राह्मण समुदाय की भावनाएं आहत करने के आरोप में निर्माता-निर्देशक नीरज पांडे और ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के विदेश में निवासरत शीर्ष अधिकारियों रीड हेस्टिंग्स अध्यक्ष, नेटफ्लिक्स (यूएसए) ,टेड सरंदास -सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नेटफ्लिक्स (यूएसए) बेला बजरिया - मुख्य सामग्री अधिकारी, नेटफ्लिक्स (यूएसए) के सहित नेटफ्लिक्स की भारतीय वितरक मोनिका शेरगिल के विरुद्ध दायर आपराधिक मानहानि परिवाद में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) की अदालत ने सभी पांचों प्रस्तावित अभियुक्तों के विरुद्ध नोटिस जारी कर दिए हैं। न्यायालय ने परिवादी के बयान दर्ज करने के पश्चात प्रकरण में उक्त

आदेश पारित किया।

प्रचार-प्रसार से पहुंची क्षति

न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी पंकज सविता ने परिवादी पटकथा लेखक, फिल्मी कलाकार एवं ज्योतिषी व मप्र की सबसे प्राचीन विप्र संस्था मध्य प्रदेश प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा के सक्रिय सदस्य पं. वैभव पाठक के शपथ-पत्र एवं प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर प्राथमिक स्तर पर आपराधिक मानहानि के अपराध पर अभियुक्तों को तलब किया है। न्यायालय के समक्ष परिवादी के अधिवक्ताओं ने तर्क किया कि यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात फिल्म का शीर्षक परिवर्तित किया जा रहा है, किंतु उस शीर्षक के व्यापक प्रचार-प्रसार से समाज के एक बड़े वर्ग की प्रतिष्ठा को जो क्षति पहुंची है, वह अपरिवर्तनीय है और उसके लिए अभियुक्तों को विधि सम्मत उत्तरदायी होना होगा।

ब्राह्मण समुदाय की सामाजिक अस्मिता पर आघात

परिवादी की ओर से अधिवक्ता असीम त्रिवेदी, प्रशांत अवस्थी,पंकज तिवारी, प्रशांत सिरमोलिया, विनीत टेहेनगुनिया, रीतेश शर्मा, शुभम पाटकर एवं अरविंद सिंह चौहान ने तर्क प्रस्तुत किया कि पंडित शब्द भारतीय संस्कृति में विद्या, वैदुष्य और धार्मिक पवित्रता का पर्याय है। इसी शब्द के लोकभाषा प्रचलन पंडत को जानबूझकर घूसखोर जैसे कलंकपूर्ण विशेषण से जोड़ना सम्पूर्ण ब्राह्मण समुदाय की सामाजिक अस्मिता पर आघात है। यह केवल किसी काल्पनिक पात्र का चरित्र-चित्रण नहीं, वरन् एक पूरे वर्ग को बदनाम करने का सुनियोजित प्रयास है।

परिवादी पं. वैभव पाठक ने परिवाद में कहा है कि यह केवल एक फिल्म के शीर्षक का मामला नहीं है, यह हमारी सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक गरिमा का प्रश्न है। जिस पंडित शब्द को पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जैसी विभूतियों ने अपने व्यक्तित्व से गौरवान्वित किया, उसे घूसखोर की संज्ञा देना भारतीय संस्कृति और उसकी परंपराओं का अपमान है।

संत गाडगे की प्रतिमा स्थापित, जयंती पर विविध आयोजन

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। संत शिरोमणि गाडगे महाराज की जयंती के अवसर पर ग्राम पंचायत धनगवां में संत गाडगे महाराज और सोमवतीजी की प्रतिमा स्थापना की गई। जिसमें रजक समाज युवा जागृति विकास समिति धनगवां के सामाजिक बन्धुओं सहित क्षेत्र भर से लोगों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में विविध आयोजनों के बाद भंडारा आयोजित किया गया। अतिथियों में विनय असाटी राष्ट्रीय अध्यक्ष असाटी समाज महासभा शोभा भैया सेन, सरपंच उर्मिला शीवधार सेन, जनपद सदस्य डॉ विमल किशोर यादव आदि उपस्थित रहे। इसी प्रकार संयुक्त रजक समाज सभा मध्य प्रदेश द्वारा संयुक्त रजक समाज सभा गौरी घाट धर्मशाला में संत गाडगे महाराज की 150वीं जयंती बड़े धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाई गई।

कार्यक्रम में वरिष्ठजनों को सम्मानित कर भंडारा प्रसाद वितरण का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर संयुक्त रजक समाज सभा के संरक्षक बब्बल रजक, बृजलाल बाथरे, रामचरण रजक, अध्यक्ष रमेश रजक, नीरज रजक आदि उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने ली अधिकारियों की बैठक

जबलपुर। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से चलाये जा रहे संकल्प से समाधान अभियान के तहत क्लस्टर स्तर आयोजित किये जा रहे वाले शिविरों में नागरिकों से प्राप्त आवेदनों के त्वरित निराकरण करने और पात्र आवेदकों को मौके पर ही हितलाभों का वितरण करने के निर्देश सभी विभागों के जिला अधिकारियों को दिये हैं। समय सीमा प्रकरणों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई ।

एक हजार से अधिक नि:शुल्क चश्मों का हुआ पंजीयन

जबलपुर (स्वतंत्र मत)।

पूर्व विधानसभा क्षेत्र में चल रहे स्वास्थ्य शिविर के दूसरे दिन सोमवार को सिंधी धर्मशाला गोपाल होटल में शिविर को आयोजन किया गया। इस दौरान लगभग 1635 हितग्राहियों ने अपना परीक्षण कराया जिसमें 1047 हितग्राहियों का चश्मे के लिए पंजीयन किया गया। 126 हितग्राहियों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए पंजीयन किये गये।

लगभग 440 हितग्राहियों को दवाईयों का वितरण किया गया।

जनसेवा के इस पुनीत कार्य की क्षेत्रवासियों ने पूर्व मंत्री, विधायक लखन घनघोरिया की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। स्वास्थ्य शिविर में पार्षद जितेन्द्र सिंह ठाकुर, पार्षद राकेश पांडे, असित यादव रिंकू, मुन्ना शुक्ला, मुन्ना बेन, उमेश लोधी, रवि सैलानी आदि उपस्थित रहे।

टैक्स बकायादारों पर नगर निगम की ताबड़तोड़ कार्यवाही

जबलपुर (स्वतंत्र मत)।

निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा संभागवार एवं वार्डवार बकाया करों की वसूली के लिए प्रयास तेज कर दिये हैं। राजस्व विभाग की टीम द्वारा जिन करदाताओं को बार-बार सूचना देने के बाद भी बकाया करों की राशि जमा नहीं की जा रही है, उन सभी करदाताओं के विरूद्ध कुर्की, तालाबंदी एवं नल कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में नगर निगम की राजस्व टीम ने संभाग स्तरीय सदस्यों के सहयोग से संभाग क्रमांक 2 कछपुरा के मदन महल वार्ड

अंतर्गत सैयद माजिद अली पर 1 लाख 99 हजार 8 सौ 6 रूपये बकाया होने पर दुकान में तालाबंदी की कार्रवाई की गयी, राजू रजक/प्रेमलाल रजक पर 84 हजार 51, तेजिंदर पाल सिंह पर 60 हजार 1 सौ 96, एवं श्रीराम प्रकाश शर्मा पर 33 हजार 23 रूपये बकाया होने पर कुर्की एवं नल काटने की कार्रवाई की गयी। इसी प्रकार संभाग क्रमांक 8 भानतलैया के शीतलामाई वार्ड अंतर्गत राम दुलारे पर 55 हजार 89 रूपये, बाबूलाला कोरी पर 46 हजार 2 सौ 69 रूपये, आशीष, अशोक कुमार पर 71 हजार 8 सौ 15, मोतीलाल पर 79 हजार 9 सौ 3 रूपये, एवं राजेश कुमार पर 79 हजार 4 सौ 82 रूपये बकाया होने पर कुर्की की कार्रवाई की गयी, वहीं भगवती संदीप, सुदीप पिता रामेश्वर प्रसाद पर 1 लाख 17 हजार 1 सौ 49 रूपये बकाया होने पर मौके पर 25 हजार रूपये का चेक प्राप्त किया। संभाग क्रमांक 14 विजय नगर में मोतीलाल वार्ड 38 के अंतर्गत रोशन आरा का. इशरत अली पिता मकसूद अली पता-1203 चार खम्बा के पास बकाया 2 लाख 4 हजार 3 सौ 14 रूपये होने पर कुर्की की कार्यवाही की गई।

इस्तीफे की मांग पर रादुविवि कुलपति के खिलाफ एनएसयूआई ने किया जमकर प्रदर्शन

गाड़ी में बैठते समय कार्यकर्ताओं ने रोका जमकर की नारेबाजी

जबलपुर (स्वतंत्र मत)।

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. राजेश वर्मा की नियुक्ति और विश्वविद्यालय में परीक्षा न होने के कारण भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को एक बार फिर कुलगुरु का घेराव किया। कुलगुरु राजेश वर्मा जब ऑफिस से बाहर निकाल कर अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे, इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोक लिया, इसके बाद भी जब वह गाड़ी में बैठकर जाने लगे तो कार्यकर्ता उनके कार के सामने आकर खड़े हो गए। कुलगुरु पैदल ही विश्वविद्यालय से बाहर जाने लगे

तब भी कार्यकर्ताओं ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। प्रदर्शन के दौरान

एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष सचिन रजक ने आरोप लगाते हुए बताया कि कुलगुरु राजेश वर्मा की नियुक्ति पूरी तरह से अवैध है, जिसके चलते उन्हें इस्तीफा हर हाल में देना ही होगा। आगे कहा कि विश्वविद्यालय की पढ़ाई और परीक्षा में ध्यान देने की वजह कुलगुरु यहां पर सरकार का पैसा बचाने में लगे हुए हैं। छात्र परेशान हो रहे हैं ना परीक्षा हो रही है, और ना ही उन्हें डिग्रियां मिल रही हैं, इतना ही नहीं रिजल्ट भी घोषित नहीं हो रहे हैं।एनएसयूआई ने आज कुलगुरु को रोकते हुए जब उनसे इस्तीफा की मांग की तो वह बिना गाड़ी के ही जाने लगे तब कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेरा इसके बाद कुलगुरु अपने ऑफिस में चले गए, जहां पर भी पीछा करते हुए पहुंच गए।

पीछे से निकलने वाला दरवाजा किया बंद–एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष अमित मिश्रा और राष्ट्रीय सचिव करण ने बताया कि जब कुलगुरु से बात करने के लिए पहुंचे और वह गाड़ी में बैठ गए तो दोनों ही कार्यकर्ता उनके कार के सामने आकर बैठ गए। अमित मिश्रा का कहना है कि जब कभी भी एनएसयूआई के कार्यकर्ता उनसे बात करने या प्रदर्शन करने के लिए आते हैं तो वह है पीछे के दरवाजे से जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने उनके पीछे वाला दरवाजा भी बंद कर दिया था। प्रदर्शन के दौरान जिलाध्यक्ष सचिन रजक, राष्ट्रीय सचिव करन तामसेतवार, प्रदेश उपाध्यक्ष अमित मिश्रा, नीलेश माहर, अपूर्व केशरवानी, सक्षम यादव, यश, अभिनव मिश्रा, अभिषेक पटेल, पुष्पेन्द्र गौतम आदि उपस्थित रहे।

दलदला-नक्टाटोला सड़क का गुणवत्ताहीन निर्माण

सड़क बैगा परिवारों की वर्षों पुरानी पीड़ा का समाधान है, न कि ठेकेदार की जेब भरने का जरिया

बालाघाट(स्वतंत्र मत)।

जनपद पंचायत बैहर अंतर्गत ग्राम पंचायत दलदला से नकटाटोला-बैगाटोला तक प्रधानमंत्री जनमन ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही पक्की सड़क चर्चाओं में आ गई है। लगभग तीन किलोमीटर लंबी इस सड़क पर 171.52 लाख रुपये की लागत स्वीकृत है, लेकिन निर्माण शुरू होते ही ठेकेदार पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगने लगे हैं। यह निर्माण कार्य ठेकेदार मे. मनुसुमन इन्फ्रा बालाघाट के द्वारा किया जा रहा हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क बैगा बहुल क्षेत्र के लिए जीवनरेखा साबित होनी थी, लेकिन पहले ही चरण में गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है।

ग्रामीणों और स्थानीय सूत्रों के अनुसार सड़क के अर्थवर्क में निर्धारित 20 सीआर मुरूम की जगह खेतों की मिट्टी और छुई का उपयोग किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार जानबूझकर सस्ती सामग्री डालकर लागत बचा रहा है, जिससे सड़क की मजबूती पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश आते ही यह मिट्टी कीचड़ में बदल जाएगी और सड़क की नींव कमजोर होकर कुछ ही समय में ध्वस्त हो सकती है।

बारिश में सड़क को खतरे की आशंका...

ग्रामीणों का दावा हैं कि यदि इसी तरह से निर्माण कार्य जारी रहा तो बारिश के मौसम में सड़क के आसपास भारी कीचड़ बनेगा। मिट्टी और छुई के कारण पानी सड़क के नीचे जाकर उसे खोखला कर देगा। इससे सड़क कुछ ही समय में धंसने या टूटने की स्थिति में आ सकती है। ग्रामीणों का

कहना है कि इतनी बड़ी लागत से बन रही सड़क अगर एक-दो साल में ही खराब हो गई तो यह शासन की योजनाओं पर भी सवाल खड़े करेगा।

पुलिया निर्माण पर भी उठे सवाल...सड़क के साथ बनाई जा रही पुलियाओं की गुणवत्ता पर भी ग्रामीणों ने आरोप है कि पुलियाओं में लोहे का उपयोग नहीं किया जा रहा और सीमेंट की मात्रा भी बेहद कम रखी जा रही है। ऐसी पुलियाएं भारी बारिश और यातायात का भार नहीं सह पाएंगी। इससे भविष्य में दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहेगी।

मजदूरी और सामाजिक सरोकार...

निर्माण कार्य में स्थानीय बैगा समुदाय के लोगों को मजदूरी मिलना सकारात्मक पहल है, लेकिन मजदूरी दर को लेकर असंतोष हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बैगा मजदूरों को मात्र 200 रुपये प्रतिदिन दिए जा रहे हैं, जो वर्तमान मजदूरी दरों से कम है। उनका कहना है कि एक ओर सरकार आदिवासी क्षेत्रों के विकास की बात करती है, वहीं दूसरी ओर मजदूरी में भी कटौती की जा रही हैं।

पुरानी घटना और उम्मीदें...

यह वहीं सड़क है जो कुछ वर्ष पहले एक दर्दनाक घटना के कारण राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आई थी, जब एक गर्भवती बैगा महिला को खाट पर लिटाकर दो से तीन फीट कीचड़ से होकर अस्पताल पहुंचाना पड़ा था। उस घटना के बाद शासन-प्रशासन की नींद खुली और इस सड़क को मंजूरी मिली। अब ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह सड़क भी केवल कागजों में मजबूत और हकीकत में कमजोर बनेगी?

ग्रामीणों की मांग और चेतावनी...

ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि सड़क निर्माण की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। उनका कहना है कि यह सड़क बैगा समाज की वर्षों पुरानी पीड़ा का समाधान है, न कि किसी ठेकेदार की जेब भरने का जरिया। अब देखना यह है कि शासन-प्रशासन इन आरोपों को गंभीरता से लेकर जांच कराता है या फिर यह सड़क भी आरोप-प्रत्यारोप की धूल में दबकर रह बन जाती हैं।

आदिवासी समाज ने पुलिस के खिलाफ निकाला मोर्चा

पूछताछ के नाम पर मारपीट करने से जुड़ा मामला

कटंगी(स्वतंत्र मत)। पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी सोमवार की शाम 04 बजे यह नारे मायॅल नगरी तिरोड़ी में धन्यवाद चौक से लेकर थाना परिसर के बीच में गुंजते हुए सुनाई दिए। नारे लगा रहे थे आदिवासी समाज के गुस्साएं लोग। जिनका तिरोड़ी पुलिस पर आदिवासी समाज के लोगों के साथ बेरहमी से मारपीट करने का गंभीर आरोप है। हालाकिं इन आरोपों का एसडीओपी विवेक शर्मा ने खंडन किया और उन्होंने कहा कि अगर पुलिस की पूछताछ के दौरान किसी प्रकार की सख्ती बरती गई है तो मातहत अधिकारियों को समझाइश दी जाएगी। आदिवासी समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा और दो अलग-अलग प्रकरणों में निष्पक्ष बिना किसी को परेशान करे जांच करने की मांग रखी है।

दो अलग-अलग मामले- दरअसल, पूरा मामला 11 फरवरी 2026 को ग्राम पौनियां में रेखचंद राहंगडाले के खेत में पैरा के ढेर में मिली जली हुई लाश की जांच कार्रवाई और ग्राम बोलडोंगरी के गुम हुए आदिवासी अशोक पन्द्रे की गुमशुदगी से जुड़ा हुआ है। अशोक पन्द्रे 09 फरवरी को लापता हुए और उनके पुत्र दिलीप, रोहित, और आशीष ने विकास कोकोड़े, नितेश परते के साथ 17 फरवरी को थाने पहुंचकर गुमशुदगी की रपट दर्ज करवाई है। गुम इंसान दिलीप पन्द्रे के बेटों का कहना है कि पुलिस ने 18 फरवरी को उन्हें थाना बुलाकर उनके साथ बेरहमी से मारपीट की और पिता की हत्या कर जलाएं जाने का अपराध कबूल करने का दबाव बनाया गया। यहीं आरोप विकास और नितेश ने भी लगाया है। इन सभी का कहना है कि पुलिस ने 18 फरवरी से 21 फरवरी के बीच उनके साथ मारपीट की। सुबह 10 बजे सभी को थाने लाकर दिन भर मारपीट की जाती और रात्रि में 10 बजे के बाद छोड़ दिया जाता। इन सभी लोगों का कहना है कि पुलिस ने हत्या करना कबूल किए जाने पर 05 लाख रुपए दिए जाने का भी लालच दिया। जब लगातार पुलिस उनके साथ ऐसा करने लगी तो उन्होंने समाज के सामने पूरी बात को रखा और सोमवार 23 फरवरी की शाम 04 बजे आदिवासी समाज ने एकत्रित होकर पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।

यह रखी गई मांग-आदिवासी समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक के नाम एसडीओपी विवेक शर्मा को ज्ञापन सौंपकर दोनों ही मामलों की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग रखी है। आदिवासी समाज के लोगों का कहना है कि पौनियां में रेखचंद राहंगडाले के खेत में मिली जली हुई लाश किसकी है पुलिस इसका भी पता करें और बोलड़ोगरी निवासी लापता अशोक पन्द्रे का भी पुलिस पता लगाएं लेकिन पूछताछ के नाम पर गरीब आदिवासियों को प्रताड़ित ना किया जाए। पौनियां की सरपंच, जनपद सदस्य और आदिवासी समाज का नेतृत्व करने वाले लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वहीं किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो इसे ध्यान में रखते हुए तिरोड़ी थाने को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। कटंगी का पुलिस बल भी तिरोड़ी थाने में डयूटी पर तैनात था।

बालाघाट-भोपाल-इंदौर बस किराया निर्धारित

अधिक वसूली पर सख्त कार्रवाईः श्री गढ़पाले

बालाघाट(स्वतंत्र मत)।

त्यौहारों के सीजन में बालाघाट से भोपाल एवं इंदौर की बसो में आने जाने वाले यात्रियों से अधिक किराया लिये जाने एवं किराया दो से तीन गुना तक बढाकर लिये जाने शिकायते प्राप्त होती है। कलेक्टर मृणाल मीना के निर्देश पर जिला परिवहन अधिकारी द्वारा बस संचालकों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे यात्रियों से निर्धारित किराया ही ले। निर्धारित से अधिक किराया लिये जाने पर जुर्माने के साथ ही बस का परमिट निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है। यात्रियों से भी अपील की गई है कि अधिक किराया लिये जाने पर परिवहन विभाग द्वारा दिये गए मोबाईल नम्बरों पर सूचना दे।

जिला परिवहन अधिकारी श्री गढ़पाल ने बताया कि लंबी दूरी की बसों में निर्धारित से अधिक किराया लिए जाने पर यात्री जिला परिवहन कार्यालय बालाघाट में शिकायत कर सकते हैं, उनकी शिकायत पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि बालाघाट से भोपाल सुपर लग्जरी एसी बस का किराया 1120 रुपये, बालाघाट से इंदौर सुपर लग्जरी एसी बस का किराया 1583 रुपए, बालाघाट से भोपाल स्लीपर बस का किराया 896 रुपये एवं बालाघाट से इंदौर स्लीपर बस का किराया 1267 रुपये निर्धारित है। इससे अधिक किराया लिए जाने पर बस संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।बालाघाट से प्रदेश की राजधानी भोपाल एवं आर्थिक राजधानी इंदौर के लिए संचालित एसी, नॉन एसी, सुपर लग्जरी एवं स्लीपर बसों का किराया निर्धारित हैं। बालाघाट से भोपाल 488 किलोमीटर के लिए एसी सुपर लग्जरी बस का किराया 1120 रुपये निर्धारित किया गया है। इसी तरह बालाघाट से इंदौर 862 किलोमीटर के लिए एसी सुपर लग्जरी बस का किराया 1583 रुपये निर्धारित किया गया है। नॉन एसी स्लीपर बसों की बात करें तो बालाघाट से भोपाल के लिए किराया 896 रुपये तय किया गया है तथा बालाघाट से इंदौर के लिए नॉन एसी स्लीपर बस का किराया 1267 रुपये तय हुआ है। इनमें स्लीपर चार्ज एवं जीएसटी की राशि भी शामिल है। जिला परिवहन अधिकारी श्री गढपाल ने आमजन से अपील की है कि बालाघाट से भोपाल-इंदौर की यात्रा करने पर परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लिये जाने पर वे प्रमोद कुमार उइके 9301990393, जीतेन्द्र कटरे 8871700936, भूपेंद्र नारनौरे 7489530837 के नम्बर पर संपर्क कर सकते है। निर्धारित किराये दर से अधिक की राशि वसूलने पर जिम्मेदार के विरूद्ध कडी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

सहायक कलेक्टर आकाश अग्रवाल को किरनापुर एसडीएम का प्रभार

डिप्टी कलेक्टर आदित्य तिवारी को बिरसा तहसील का प्रभार

बालाघाट(स्वतंत्र मत)। कलेक्टर मृणाल मीना ने प्रशासनिक कार्य व्यवस्था की दृष्टि से अधिकारियों के बीच पूर्व में किये गए कार्य विभाजन में आंशिक संसोधन किया है। जिसके फलस्वरूप भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारी सहायक कलेक्टर आकाश अग्रवाल को आगामी आदेश तक के लिए किरनापुर एसडीएम का सम्पूर्ण प्रभार सौंपा गया है। किरनापुर में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का प्रभार संभाल रहे श्री मायाराम कौल को संयुक्त कलेक्टर के पद पर कलेक्ट्रेट कार्यालय बालाघाट में पदस्थ किया गया है।

इसी प्रकार परिवीक्षाधीन डिप्टी कलेक्टर आदित्य नारायण तिवारी को प्रशिक्षण अवधि में तहसीलदार बिरसा का आहरण एवं संवितरण सहित सम्पूर्ण प्रभार सौंपा गया है। जिसके फलस्वरूप सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख एवं प्रभारी तहसीलदार बिरसा राजूलाल नामदेव को आगामी आदेश तक कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैहर में पदस्थ किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावी हो गया है।

सड़क दुर्घटना में घायलों को त्वरित अस्पताल पहुंचाने के संजीवनी-108 टीम को किया गया सम्मानित

बालाघाट(स्वतंत्र मत)। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को त्वरित उपचार दिलाकर उसकी जान बचाने में अहम भूमिका निभाने वाली संजीवनी 108 आपातकालीन सेवा की टीम को 23 फरवरी को वारासिवनी एसडीओपी अभिषेक चौधरी के निर्देश पर वारासिवनी थाने में सम्मानित किया गया। उप थाना प्रभारी दीपक गौतम द्वारा संजीवनी-108 के ईएमटी (सहायक चिकित्सक) डॉ. गौरी शंकर पटले एवं पायलट जयेश चौहान को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मनित किया गया और उनके द्वारा पीडित मानवता की सेवा के लिए किये जा रहे कार्यों की सराहना की गई। हाल ही में हुई एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। सूचना मिलते ही संजीवनी 108 आपातकालीन सेवा की टीम मौके पर पहुंची। ईएमटी डॉ. पटले ने प्राथमिक उपचार देते हुए घायल की स्थिति को स्थिर किया, वहीं पायलट जयेश चौहान ने सूझबूझ और तत्परता दिखाते हुए एंबुलेंस को तेज़ी से अस्पताल तक पहुंचाया। समय पर इलाज

मिलने से घायल की जान बचाई जा सकी। संजीवनी-108 सेवा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों की गर्भवती माताओं को प्रसव के लिए सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने में भी सराहनीय भूमिका निभा रही है।

सम्मान समारोह के दौरान उप थाना प्रभारी दीपक गौतम ने कहा किआपातकालीन परिस्थितियों में 108 सेवा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। डॉ. पटले और जयेश चौहान ने कर्तव्यनिष्ठा और मानवता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि दुर्घटना की स्थिति में तुरंत 108 सेवा को सूचित करें और घायलों की मदद के लिए आगे आएं। यह सम्मान न केवल 108 टीम के मनोबल को बढ़ाएगा, बल्कि समाज में सेवा और तत्परता की भावना को भी मजबूत करेगा।

बांधवगढ़ में जंगल सफारी पर नियमों के उल्लंघन पर कार्यवाही

उमरिया (स्वतंत्रमत) - जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के दौरान नियमों का उल्लंघन और श्बधीरा ऐपश् में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए 27 गाइडों के जंगल प्रवेश पर 28 फरवरी तक प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि तीन वाहन चालकों और तीन गाइडों पर जुर्माना लगाया गया है।पर्यटन अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सफारी के दौरान उपयोग होने वाला बधीरा ऐप जिप्सी के निर्धारित मार्ग, गति और भ्रमण क्षेत्र की निगरानी करता है। जांच में पाया गया कि कई मामलों में सफारी का वास्तविक ट्रैक रिकॉर्ड नहीं हुआ, जिससे ऐप के साथ छेड़छाड़ की आशंका बनी। इसे गंभीर लापरवाही माना गया है। इस उल्लंघन के बाद, संबंधित 27 गाइडों के जंगल प्रवेश पर अस्थायी रोक लगाई गई है। इसके अतिरिक्त, तीन वाहन चालकों और तीन गाइडों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना

भी लगाया गया है।

इन गाइडों पर लगा प्रतिबंध-प्रतिबंधित गाइडों में अतुल कुमार गुप्ता, राजेश कुमार साहू, भारती शुक्ला, गजेंद्र यादव, सत्यकांत शुक्ला, देवराज सिंह, शुभम सिंह, लवकेश कुमार बैगा, शिवशंकर नामदेव, राजकुमार सिंह, राकेश सिंह, अवनीश सिंह, रामदीन बैगा, सफल सिंह, संत कुमार प्रजापति, राजेश साहू, मनजीत सिंह, मुकेश यादव, रामलखन सिंह, प्रवीण मिश्रा, उमादत्त सिंह, धर्मराज सिंह, अनसूइया बैगा, शशिधर यादव सहित कुल 27 गाइड शामिल हैं।

जिप्सी चालकों पर लगा जुर्माना-वाहन चालक अल्विन डिसूजा, मुकेश शुक्ला तथा एक अन्य चालक और गाइड गोवर्धन विश्वकर्मा, हरि सिंह, गजेन्द्र यादव पर भी जुर्माना लगाया गया है। प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि सफारी नियमों के उल्लंघन और डिजिटल मॉनिटरिंग प्रणाली में छेड़छाड़ को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

कलेक्टर की अध्यक्षता में समय सीमा की बैठक संपन्न

उमरिया (स्वतंत्रमत)। कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन कि अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में समय सीमा की साप्ताहिक बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए कहा कि सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों का शत प्रतिशत निराकरण करते हुए ए ग्रेड मे आना सुनिश्चित करें। बैठक में उन्होंने मुख्यमंत्री निवास से प्राप्त आवेदनों, आयुक्त शहडोल संभाग कार्यालय से प्राप्त आवेदनो तथा जनसुनवाई, न्यायालयीन प्रकरणों, मानवाधिकार के पत्रों,फैक्ट न्यूज आदि की समीक्षा करते हुए जिला प्रमुख अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी दायित्वों का निर्वहन समय सीमा में अनिवार्य रूप से करें। उन्होने कहा कि समस्त एसडीएम फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में प्रगति लाना सुनिश्चित करें। इस कार्य में तहसीलदार एवं पटवारी को फील्ड पर उपस्थित रह कर फॉर्मर रजिस्ट्री के कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि संकल्प से समाधान के तहत आयोजित किए जा रहे शिविरों में खंड स्तरीय अधिकारी एवं जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।तथा प्राप्त हो रहे आवेदनों का निराकरण करना सुनिश्चित करें।उन्होंने कहा कि वन अधिकार पट्टे के लंबित प्रकरणों का निराकरण करें तथा जो प्रकरण निरस्त योग्य है उसे जांच के उपरांत निरस्त करने की कार्यवाही करें। लोक सेवा प्रदाय अधिनियम के तहत आम जनो को समय सीमा मे सेवाओं का प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करें। प्रकरण समय सीमा के बाह्य होने पर अनुशासनात्मक एवं अर्थदंड की कार्यवाही की जाएगी ।

रेल ट्रैक पर मिला युवक का शव, हादसे की आशंका

उमरिया (स्वतंत्रमत)। कोतवाली थाना अंतर्गत चपहा के समीप रेल हादसे की खबर है,इस हादसे में एक अज्ञात युवक के जान जाने की भी खबर है।सूत्रों की माने तो युवक का शव रेलवे ट्रैक पर रेल पोल क्रम 975/6 के करीब मौजूद है।घटना किन कारणों से हुई है,फिलहाल साफ नही है, ।हादसे की खबर पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची थी,पर युवक के मृत होने के संदेह पर सम्बंधित पुलिस अधिकारियों को जानकारी दी गई, जिसके बाद घटना स्थल पर पुलिस पहुंची है,और शिनाख्ती के प्रयास में जुटी है।घटना किन कारणों से कारित हुआ है फिलहाल साफ़ नही है, इस हादसे में यह भी पुष्टि नही हो पाई है कि मृतक स्थानीय है या यात्री ट्रेन से गिरने की वजह से हादसा कारित हुआ है।

अधिवक्ता संघ ने दिवंगत एड. संतोष भट्ट को दी श्रद्धांजलि

उमरिया (स्वतंत्रमत) - जिला अधिवक्ता संघ उमरिया ने सोमवार 23 फरवरी को न्यायालय परिसर में उमरिया जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष कुमार निधन पर परंपरागत तरीके से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अधिवक्ता संघ उमरिया ने ,अधिवक्ता अधिवक्ता संघ के पूर्व सचिव शपथ आयुक्त श्री संतोष कुमार भट्ट के निधन पर न्यायालय परिसर में परंपरागत तरीके से 2 मिनट का मौन रखकर दिवगंत आत्मा की शांति के लिए बार व बेंच ने प्रार्थना की एवं उनके परिवार को असीम कष्ट सहने की क्षमता प्रदान करें इसके लिए अपने ईश्वर से कामना की। शोक सभा कार्यक्रम के अवसर पर श्री प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय श्री अरुण कुमार सिंह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अहमद राजा मुख्य मजिस्ट्रेट दीपक अग्रवाल नायक मजिस्ट्रेट श्रीमती मीना खाकको,आशीष धुर्वे सरफराज अहमद, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष पुष्पराज सिंह उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह सचिन सुखबद महोबिया, शाह सचिन राजीव सिंह, कोषाध्यक्ष रामकृष्ण उपाध्याय सहित वरिष्ठ अधिवक्ता जयलाल राय दिनेश त्रिपाठी ओपी मिश्रालाल की के सिंह मुकेश अग्रवाल रवि शंकर शर्मा भारत अग्रवाल रिजवान अहमद श्रीमती रचना गौतम श्रीमती वैजयंती माला श्रीमती उषा गुप्ता श्रीमती अर्चना भट्ट विजय राय सुरेश अमित रानी अशोक तिवारी सूर्य प्रकाश गुप्तआजा यश कुमार सोनी विनोद तिवारी सतीश पांडे राजकुमार यादव वेंकटेश पुरी विवेक तिवारी, राकेश गुप्ता, शिवम रजक प्रवीण पाण्डेय राजकुमार सिंह चौहान राजाराम हरवानी, अभिषेक खट्टर एवं सागर से पहुंचे अधिवक्ता श्री राजेश कुमार पांडे विशेष रूप से उपस्थित रहे।

हाथी मानव द्वंद न्यूनीकरण विषय पर बांधवगढ़ में कार्यशाला संपन्न

उमरिया (स्वतंत्रमत)। क्षेत्र संचालक बांधवगढ टाईगर रिजर्व ने बताया कि ईको सेंटर, ताला में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एवं उमरिया वन मंडल के संयुक्त मार्गदर्शन में हाथी मानव द्वंद विषय पर जिला पंचायत अनूपपुर के अधिकारियों तथा जन प्रतिनिधियों के जागरूकता हेतू कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयोजन में उप संचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व तथा वनमण्डल अधिकारी उमरिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही।कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में हाथियों की गतिविधियों के दौरान उत्पन्न मानव वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम, सुरक्षा उपायों,समन्वित कार्ययोजना एवं विभागीय रणनीति पर चर्चा है।कार्यक्रम के दौरान वनविभाग के अधिकारियों द्वारा हाथियों की निगरानी, सुरक्षा प्रोटोकॉल,गज रक्षक ऐप, त्वरित सूचना प्रणाली तथा प्रभावी प्रबंधन के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई।इस अवसर पर जिला पंचायत अनूपपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अध्यक्ष एवं सदस्यगण विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने तथा हाथी मानव द्वंद की घटनाओं को कम करने हेतु प्रभावी योजनाओं के क्रियान्वयन पर बल दिया। कार्यशाला में विभागीय अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा विषय पर विस्तार से चर्चा करते हुए आवश्यक सुझाव प्रस्तुत किए गए। अंत में सभी उपस्थित अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों ने समन्वित प्रयासों के माध्यम से हाथी मानव द्वंद की घटनाओं को न्यूनतम करने का संकल्प लिया।

सीईओ ने किया निरीक्षण

मण्डला(स्वतंत्र मत)। सीईओ जिला पंचायत शाश्वत सिंह मीना द्वारा जनपद पंचायत मोहगांव अंतर्गत ग्राम पंचायत चौगान का दौरा किया गया। इस दौरान उन्होंने नर्मदा पथ आश्रय स्थल पर पौधरोपण किया तथा स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में दल बादल महल, चिमनी रानी महल एवं संचालित होम स्टे का भी अवलोकन किया गया। अधिकारियों को पर्यटन स्थलों के रख-रखाव, स्वच्छता एवं आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किए गए।

बच्चों की पढ़ाई में भूमिका

मण्डला(स्वतंत्र मत)। विगत दिनों अखिल भारतीय हिंदी सेवा समिति एवं राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के संयुक्त तत्वाधान में बच्चों की पढ़ाई में हमारा योगदान विषय पर आधारित ऑनलाइन मासिक गोष्ठी का आयोजन डॉ मनोरमा गुप्ता पूर्व प्राचार्य आदित्य महाविद्यालय जबलपुर के मुख्य आतिथ्य, डॉ रश्मि बाजपेई पूर्व प्राचार्य डाइट के विशिष्ट आतिथ्य एवं डॉ. संध्या शुक्ल मृदुल जिला संयोजक मप्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति मंडला व प्रदेशाध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदी सेवा समिति की अध्यक्षता में हुआ।

पागल कुत्तों का आतंक

मण्डला/मोहगांव(स्वतंत्र मत)। मोहगांव क्षेत्र में इन दिनों पागल कुत्तों का खतरा तेजी से बढ़ता दिख रहा है। जितेंद्र झरिया की बेटी सौम्या झरिया, सचिन नंदा तथा दो गायों को कुत्तों ने काट लिया। बताया जा रहा है कि ये कुत्ते पूरे गांव में घूम रहे हैं जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन और पशु चिकित्सा विभाग से तत्काल कार्रवाई मांग की है। प्रभावित लोगों का समय पर उपचार हो सके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एंटी-रेबीज इंजेक्शन की कमी मोहगांव में पागल कुत्तों के हमले के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था की कमी भी सामने आई है। जानकारी के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एंटी-रेबीज इंजेक्शन की भारी कमी पाई गई जहां केवल एक ही इंजेक्शन उपलब्ध था। यह इंजेक्शन घायल सौम्या झरिया को लगाया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दूसरे घायल सचिन नंदा को इंजेक्शन लगवाने के लिए घुघरी के लिए रवाना होना पड़ा।

राजश्री गुटखा की कालाबाजारी

मण्डला(स्वतंत्र मत)। राजश्री गुटखा पाऊच की कालाबाजारी जमकर चल रही हैं नगर के चिन्हित व्यवसायी हर दिन रेट बढ़ा रहे हैं बीते दिनों बजट में तम्बाखू से बनें उत्पादों की कीमत बढ़ाने का ऐलान होने के बाद यह स्थिति दिखाई देने लगी है। 5 वाली राजश्री 8 रूपए में बिक रहा है 20 वाला राजश्री 25 रूपए में बिक रहा है 40 वाला राजश्री 50 रूपए में खुलेआम बेची जा रही है। यह सिर्फ नशा नहीं गरीब जनता की खुली जेब काटने का संगठित खेल है। एजेंसी संचालक बड़े सप्लायर और थोक दुकानदार मुनाफाखोरी में लगे हैं और खुदरा दुकानदार ओवररेट वसूल कर खुली लूट कर रहे हैं। सब जानते हैं यह जहर कैंसर, टीबी, दिल और पेट की बीमारियों की जड़ है। फिर भी हर दिन करोड़ों का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल जब एमआरपी से ज्यादा रेट पर बिक्री अपराध है तो संबंधित विभाग और जिम्मेदार अधिकारी आंख बंद करके तमाशा क्यों देख रहे हैं।

25 तक आवेदन आमंत्रित

मण्डला(स्वतंत्र मत)। कार्यालय जिला पंचायत मंडला ग्रामोद्योग एवं माटीकला द्वारा हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योग क्षेत्र से जुड़े हितग्राहियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। हस्तशिल्प एवं तकनीकी विकास योजना 2021 अंतर्गत मंडला जिले के बुनकरों एवं शिल्पियों, स्व-सहायता समूहों बुनकर सहकारी समितियों तथा मास्टर उद्यमियों से वर्ष 2025-26 के लिए हस्तकला प्रशिक्षण, कच्चे एवं हस्तशिल्प उपकरण प्राप्त करने के लिए 25 फरवरी तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।

ऊर्जा विभाग को प्रदेश में प्रथम स्थान

मण्डला(स्वतंत्र मत)। ऊर्जा विभाग मंडला द्वारा सी.एम. हेल्पलाईन में प्राप्त शिकायतों के निराकरण में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। माह अक्टूबर 2024 से दिसंबर 2025 तक लगातार सोलह महीनों में विभाग ने उपभोक्ताओं की वोल्टेज संबंधी मीटर संबंधी खंभे एवं तार से जुड़ी शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण किया। साथ ही त्रुटिपूर्ण विद्युत बिलों में सुधार कर आवश्यक अनुमोदन प्रदान करते हुए शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया गया। माह जनवरी 2026 में ऊर्जा विभाग मंडला ने सीएम हेल्पलाईन में 100 प्रतिशत स्कोर प्राप्त कर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया। इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर पूर्व में कलेक्टर द्वारा अति. मुख्य अभियंता (संचा-संधा) मंडला मो. अयूब खान को सम्मानित भी किया जा चुका है।

समिति की बैठक कल

मण्डला(स्वतंत्र मत)। कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडल संभाग मंडला द्वारा विभागीय संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित किए जाने की सूचना जारी की गई है। जारी पत्र के अनुसार यह बैठक 25 फरवरी को दोपहर 3 बजे कार्यालय परिसर में आयोजित की जाएगी। कार्यपालन यंत्री द्वारा जारी पत्र में विभिन्न अधिकारी एवं कर्मचारी संगठनों के जिला शाखा अध्यक्षों को बैठक में निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होने का अनुरोध किया गया है। बैठक में विभागीय विषयों पर चर्चा एवं आवश्यक निर्णय लिए जाने की संभावना है।

लूट गैंग का नया कारनामा : न फर्म का पता और न टेंडर का पीएमश्री स्कूल आए निशाने में, घटिया सामग्री की सप्लाई

मण्डला(स्वतंत्र मत)

सरकारी छात्रावासों मे मची लूट के बाद अब पीएमश्री स्कूल निशाने में बताए जा रहे हैं। इन स्कूलों में उपयोगी सामग्री के साथ छात्रों के लिए खरीदी जाने वाली सामग्री में नगर के दो युवाओं का नाम काफी तेजी से सामने आ रहा है। ये दोनो युवा समाजसेवा की आड़ में इन दिनों जमकर पीएम श्री स्कूल को टारगेट कर रहे हैं। कहीं-कहीं तो सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों का हवाला दिया जा रहा है तो कहीं पर वरिष्ठ अधिकारियों का नाम बताकर फर्जी बिल लगाने के साथ घटिया सामग्री की सप्लाई भी की जा रही है। पदस्थ शिक्षकों में दबाव बनाकर कागजी खानापूर्ति की जा रही है। वहीं उन दोनो युवाओं की फर्मो पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। लोकल बाजार से सामग्री लाकर महंगे दामों पर सप्लाई की जा रही हैं। टेंडर कब हुए कितने फर्मो ने भागीदारी की कुछ भी पता नही चल पा रहा है लेकिन पीएम श्री स्कूल से जुड़े सूत्रों का कहना है कि यह बच्चों के साथ नाइनसाफी है जीवन भर शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए काम करने वाले शिक्षकों में जमकर रोष है बता दें कि मंडला जिले में एमएमश्री के 18 स्कूल संचालित हैं जो कि बिछिया, बीजादांडी, घुघरी, मंडला, मवई, मोहगांव, नैनपुर, नारायणगंज, निवास में संचालित हैं। जहां पर नर्सरी से लेकर 12वीं तक के बच्चें अध्ययनरत बताए जाते हैं। देश में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और सरकारी विद्यालयों को आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित करने के उद्देश्य से शुरू की गई पीएम श्री योजना को एक क्रांतिकारी पहल के रूप में प्रचारित किया गया था। इस योजना का उद्देश्य देशभर के चुनिंदा सरकारी विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करना है जहां बच्चों को निजी स्कूलों जैसी सुविधाएं डिजिटल शिक्षा आधुनिक प्रयोगशालाएं और समग्र विकास का वातावरण मिल सके। लेकिन आदिवासी बाहुल्य मंडला जिले में इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। जिले के कई चयनित विद्यालयों में अभिभावकों ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों ने भारी अनियमितताओं अपारदर्शिता और अधूरे कार्यों के आरोप लगाए हैं। सवाल यह है कि जिन स्कूलों को पीएम श्री का दर्जा देकर उदाहरण प्रस्तुत करने की बात कही गई क्या वे वास्तव में उस स्तर तक पहुंच पाए हैं। बता दें वर्ष 2022 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत मंडला जिले में 18 से अधिक स्कूलों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास, डिजिटल बोर्ड, अत्याधुनिक विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, खेल सुविधाएं, हरित परिसर, स्वच्छ पेयजल, बालिका अनुकूल शौचालय और दिव्यांगजन के लिए विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जानी थीं। योजना का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप समग्र और कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करना है। दावा है कि इन स्कूलों को पर्याप्त बजट और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि वे अन्य सरकारी विद्यालयों के लिए प्रेरणा बन सकें। मंडला जिले में 18 विद्यालयों को इस योजना के तहत चयनित किया गया है। चयन प्रक्रिया को लेकर ही प्रारंभिक असंतोष सामने आया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिन स्कूलों की स्थिति पहले से अपेक्षाकृत बेहतर थी उन्हीं को प्राथमिकता दी गई जबकि दूरस्थ और जरूरतमंद ग्रामीण स्कूलों को नजरअंदाज कर दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि चयन में पारदर्शिता का अभाव रहा। यदि उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा स्तर सुधारना था तो प्राथमिकता उन स्कूलों को मिलनी चाहिए थी जहां बुनियादी सुविधाओं की कमी है। स्मार्ट क्लास के नाम पर केवल एक टीवी या प्रोजेक्टर लगा दिया गया है। डिजिटल बोर्ड या इंटरनेट कनेक्टिविटी सुचारु नहीं है। विज्ञान प्रयोगशालाओं में उपकरणों की कमी बताई जा रही है। पुस्तकालयों में नई किताबों का अभाव है। खेल मैदानों का समुचित विकास नहीं हुआ। कुछ विद्यालयों में रंग-रोगन और बाहरी सजावट तो कर दी गई, लेकिन मूलभूत संरचनात्मक सुधार नहीं हुए। स्थानीय अभिभावकों का कहना है कि नाम बदल देने से स्कूल मॉडल नहीं बन जाता। पीएम श्री विद्यालयों के लिए करोड़ों रुपये के बजट स्वीकृत होने की जानकारी सार्वजनिक है। लेकिन खर्च की विस्तृत जानकारी आम जनता तक नहीं पहुंची। ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मांग है कि प्रत्येक विद्यालय में प्राप्त राशि खर्च की मद और प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। कई स्थानों पर आरोप हैं कि सामग्री की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है। निर्माण कार्य में देरी और ठेकेदारों की भूमिका पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। यदि योजना का उद्देश्य पारदर्शिता और गुणवत्ता था तो फिर जानकारी सार्वजनिक करने में हिचक क्यों? विद्यालयों में शिक्षकों की कमी भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। कुछ पीएम श्री स्कूलों में पद स्वीकृत होने के बावजूद सभी पदों पर नियुक्ति नहीं हुई। परिणामस्वरूप, एक ही शिक्षक को कई कक्षाओं का भार संभालना पड़ रहा है।

इनका कहना

जिला शिक्षा समिति की बैठक में इस मुद्दे को लेकर चर्चा की गई थी। पीएमश्री स्कूलों में घटिया सामग्री भेजी जा रही है। चिन्हित लोगों के द्वारा सप्लाई की जा रही है मामले की उच्च स्तरीय शिकायत भोपाल स्तर पर की जा जाएगी। सप्लायर पहले भी फर्जी सप्लाई के मामले में फंस चुकें हैं।

कमलेश तेकाम, अध्यक्ष
जिला शिक्षा समिति मंडला

गौठान भूमि पर कब्जा का खेल

मण्डला(स्वतंत्र मत)

शहर में शासकीय जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण अब महज लापरवाही का मामला नहीं रह गया है बल्कि यह संगठित कब्जा तंत्र का रूप लेता जा रहा है। नजूल राजस्व और नगरपालिका की निष्क्रियता ने अतिक्रमणकारियों को खुली छूट दे दी है। हालात यह हैं कि शिकायत के बाद भी कार्यवाही नहीं हो रही है और कब्जाधारी झोपड़ी से पक्के निर्माण तक पहुंच जाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने आम नागरिकों में आक्रोश पैदा कर दिया है। महाराजपुर के ज्वाला जी वार्ड स्थित खसरा नंबर 128 की गौठान भूमि इसका ताजा उदाहरण है। किए गए पौधारोपण और सुरक्षा के लिए लगाई गई फेंसिंग को तोड़कर पहले हरियाली उजाड़ी गई और अब उसी जमीन पर झोपड़ी खड़ी कर कब्जे की पटकथा लिखी जा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी बार-बार नगरपालिका नजूल शाखा और राजस्व अधिकारियों को दी गई लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ चुप्पी साध ली गई। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि यह सिर्फ उदासीनता नहीं बल्कि सुनियोजित खेल है पहले कब्जा होने दिया जाता है फिर वर्षों का हाउस टैक्स लेकर रसीद थमा दी जाती है और बाद में वही दस्तावेज न्यायालय में पट्टे की दावेदारी का आधार बन जाते हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर बिना निर्माण अनुमति और शासकीय भूमि पर कब्जे के बाद टैक्स वसूली किस नियम के तहत की जाती है? जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है।

भागवत पुराण में श्रीकृष्ण लीलाओं का वर्णन

मण्डला(स्वतंत्र मत)

चंदन कॉलोनी इन दिनों भक्ति श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। यहां चल रहे श्रीमद् भागवत पुराण ज्ञान यज्ञ में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रृद्धालु पहुंचकर भगवान श्रीकृष्ण की दिव्य लीलाओं का रसास्वादन कर रहे हैं। कथा के दौरान वातावरण इतना आध्यात्मिक हो जाता है कि पूरा पंडाल राधे-राधे और जय श्रीकृष्ण के जयकारों से गूंज उठता है। कथा वाचक पंडित राजेश प्यासी के मुखारविंद से जब भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं का वर्णन प्रारंभ होता है तो श्रोतागण भाव-विभोर हो उठते हैं। उन्होंने कंस वध का प्रसंग अत्यंत ओजस्वी और प्रभावी शैली में प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि जब अधर्म और अत्याचार अपनी सीमाएं पार कर जाते हैं तब धर्म की स्थापना के लिए स्वयं भगवान अवतार लेते हैं। कंस के अत्याचारों से त्रस्त मथुरा की प्रजा की पुकार सुनकर श्रीकृष्ण ने उसका अंत कर धर्म की पुनर्स्थापना की। इस प्रसंग के दौरान श्रद्धालुओं ने तालियों और जयकारों से पंडाल गुंजायमान कर दिया। वहीं श्रीकृष्ण-रुक्मिणी विवाह का प्रसंग अत्यंत मार्मिक और भावनात्मक रहा। पंडित प्यासी ने बताया कि रुक्मिणी जी ने श्रीकृष्ण को अपना सर्वस्व मानते हुए मन ही मन उन्हें पति रूप में स्वीकार कर लिया था। जब उनका विवाह शिशुपाल से तय किया गया, तब उन्होंने श्रीकृष्ण को पत्र लिखकर अपने प्रेम और समर्पण का संदेश भेजा। भगवान श्रीकृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर धर्म और प्रेम की विजय का संदेश दिया। श्रीमद् भागवत कथा का यह पावन आयोजन महाराजपुर की चंदन कॉलोनी में भक्ति और सामाजिक एकता का प्रतीक बन गया है जहां भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं के माध्यम से धर्म, प्रेम और समर्पण का संदेश जन-जन तक पहुंचाया जा रहा है।

मातृभाषा हमारी संस्कृति की वाहक होती है : प्रो.देवप्रकाश उईके

नैनपुर (स्वतंत्र मत)

शासकीय स्नातक महाविद्यालय नैनपुर में स्वामी विवेकानंद मार्गदर्शन प्रकोष्ठ एवं हिंदी विभाग एवं भारतीय ज्ञान परंपरा के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर सोमवार 23 फरवरी 2026 को व्याख्यान एवं शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के प्रभारी देवप्रकाश उईके के ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मातृभाषा हमारी संस्कृति की वाहक होती है यह हमारी संवेदनाओं और भावनाओं को व्यक्त करती है हम चिंतन करते है ,विचार करते हैं उसे व्यक्त करने के लिए जिस भाषा को उपयोग करते हैं वही हमारी मातृभाषा है मातृभाषा हमें सामाजिक एवं पारिवारिक रूप से जोड़ने का कार्य करती है हमें हर हाल में अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए जिससे हमारी संस्कृति की रक्षा हो सके । इस अवसर पर उपस्थित अध्यापकों एवं छात्र-छात्राओं द्वारा शपथ ली गई कि वह मातृभाषा का सम्मान करते हुए अधिक से अधिक उसका प्रयोग करेंगे एवं मातृभाषा की रक्षा एवं उसके सम्मान के लिए लोगों को जागरूक करेंगे । इस अवसर पर संस्था प्रभारी प्राचार्य डॉ. जी सी मेश्राम, डॉ. एमके बघेल, डॉ. ज्योति सिंह , डॉ. जे एस उर्वेति, डॉ. प्रियंका चक्रवर्ती , डॉ रविन चौहान, डा अकांक्षा मरावी, डॉ. कुलभूषण रजक, गिरवर सिंह राजपूत , डॉ. रवि यादव, डॉ. नरेंद्र राहंगडाले, डॉ. संजीव सिंह, अमित सेन एवं राहुल विश्वकर्मा सहित महाविद्यालय के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।

संत निरंकारी मिशन ने चकोर नदी में की सफाई

स्वच्छ जल स्वच्छ मन के तहत दिया स्वच्छता का संदेश

नैनपुर (स्वतंत्र मत)

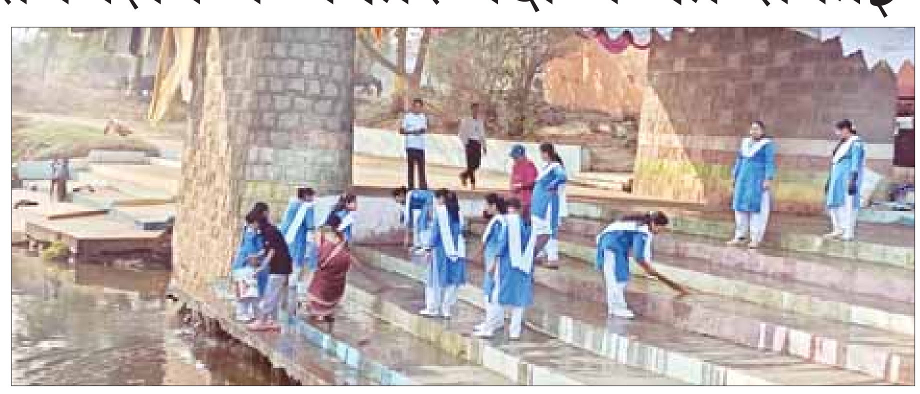

मानव सेवा और लोक कल्याण की दिव्य चेतना को साकार रूप प्रदान करने हेतु संत निरंकारी मिशन द्वारा 'प्रोजेक्ट अमृत' के अंतर्गत 'स्वच्छ जल, स्वच्छ मन' अभियान शुरू किया गया है। जिसके चौथे चरण का शुभारंभ 22 फरवरी को नैनपुर में चकोर नदी में सफाई के साथ किया गया। परम श्रद्धेय सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के निर्देशानुसार यह वृहत अभियान समूचे भारत मे चलाया जा रहा है। इस पहल का मूल उद्देश्य समाज को यह अनुभूति कराना है कि जल केवल संसाधन नहीं, जीवन का आधार और ईश्वर की अमूल्य देन है, जिसकी रक्षा करना प्रत्येक मानव का नैतिक कर्तव्य है। संत निरंकारी मिशन ने बाबा हरदेव सिंह जी की प्रेरणास्पद शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए वर्ष 2023 में संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से 'प्रोजेक्ट अमृत' का सूत्रपात किया था। जिसमे प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण का संकल्प लिया गया। नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं एवं झरनों जैसे प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण और संवर्धन हेतु समर्पित इस जनआंदोलन ने अपने प्रथम तीन चरणों में सेवा, समर्पण और सहभागिता की अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की है। इन्हीं उपलब्धियों से प्रेरित होकर इस चौथे चरण में संत निरंकारी मिशन के अनुयायी सुबह चकोर नदी के तट पर पहुंचे। जहां सभी ने मिलकर सामूहिक रूप से चकोर नदी के घाटों में सफाई अभियान चलाया । जिसमे महिला पुरुष और युवक युवतियों ने बढ़ चढ़ कर अपनी सहभागिता रखी। संत निरंकारी मंडल ब्रांच नैनपुर से कैलाश कटियार ने बताया कि यह विशाल अभियान देशभर में 1500 से अधिक स्थानों में एक साथ आयोजित किया गया जो जल संरक्षण तथा स्वच्छता के संदेश को समाज के प्रत्येक वर्ग तक प्रभावशाली रूप से पहुंचाया । ब्रांच नैनपुर द्वारा भी चकोर नदी में साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया गया, जिसमें ब्रांच नैनपुर की सर्व साध संगत, सेवादल के भाई बहन, नगरपालिका अध्यक्ष व नगरपालिका कर्मचारियों की विशेष उपस्थित रही ।

सेंट्रल बैक का रिटेल मेगा कार्यक्रम

मण्डला(स्वतंत्र मत)

सेंट्रल बैक ऑफ इंडिया ने रिटेल मेगा क्रेडिट आउटरीच अभियान का आयोजन किया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य बैंक के रिटेल ऋण उत्पादों को बढ़ावा देना एवं ग्राहकों को सुलभ तथा किफायती वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना रहा। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित ग्राहकों को बैंक की विभिन्न रिटेल ऋण योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। इनमें 7.10 प्रतिशत से प्रारंभिक आकर्षक ब्याज दर, शून्य प्रोसेसिंग शुल्क एवं 30 वर्ष तक की अवधि वाला होम लोन 7.60 प्रतिशत से प्रारंभिक ब्याज दर, 2 करोड़ रुपये तक की ऋण सीमा एवं लचीली ईएमआई सुविधा वाला वाहन लोन, त्वरित स्वीकृति, शून्य प्रोसेसिंग शुल्क एवं 40 लाख रुपये तक की सीमा वाला गोल्ड लोन प्रमुख रहे। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को ब्याज सब्सिडी सहित अन्य लाभों की जानकारी दी गई।

कार्यालय नगर परिषद, भुआ बिछिया, जिला-मण्डला
E-mail : cmobichhiya@gmail.com website : bhuabichhiya.mp-np.in
Cmo.bichhiya15@gmail.com दूरभाष क्रमांक 07648299402

क्रमांक/न.परि.2026/961 भुआ बिछिया, दिनांक 18/02/2026

(आवासीय भूमि का पट्टा वितरण हेतु अंतिम सूची का प्रकाशन)

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि म.प्र. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा राजस्व विभागः मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र.क्र. 4209/2025/18-3 भोपाल दिनांक 17/11/2025 के अनुक्रम में नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदाय किये जाना) अधिनियम 1984 के अंतर्गत आवासीय भूमि के पट्टे दिये जाने हेतु नगर परिषद भुआ बिछिया के सर्वेक्षण दल द्वारा किये गये सर्वेक्षण अनुसार पात्र/अपात्र हितग्राहियों के प्रारंभिक सूची का प्रकाशन में कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी भुआ बिछिया को कार्यालयीन समय पर प्राप्त दावा/आपत्तियों का न्यायालय में विधिवत सुनावाई एवं जांच उपरांत 24 पात्र हितग्राहियों की सूची कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व बिछिया एवं नगर परिषद कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं विभागीय वेबसाईड w.w.w.mpurban.gov.in में देखी जा सकती हैं।
(सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नगर परिषद भुआ बिछिया, जिला मंडला

कार्यालय नगर पालिका परिषद, नैनपुर, जिला मण्डला

क्रमांक / न.पा. परि0 / 2026 / नैनपुर, दिनांक 18/02/2026

(आवासीय भूमि का पट्टा वितरण हेतु अंतिम सूची का प्रकाशन)

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि म.प्र. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र.क्र. 4209/2025/18-3 भोपाल दिनांक 17/11/2025 के अनुक्रम में नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदाय किये जाना) अधिनिय 1984 के अंतर्गत आवासीय भूमि के पट्टे दिये जाने हेतु नगर पालिका परिषद नैनपुर के सर्वेक्षण दल द्वारा किये गये सर्वेक्षण अनुसार पात्र / अपात्र हितग्राहियों के प्रारंभिक सूची का प्रकाशन में कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी नैनपुर को कार्यालयीन समय पर प्राप्त दावा / आपत्तियों का न्यायालय में विधिवत सुनवाई एवं जाँच उपरांत 33 पात्र हितग्राहियों की सूची कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व नैनपुर एवं नगर पालिका परिषद कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं विभागीय वेबसाईड www.mpurban.gov.in में देखी जा सकती हैं।

(सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, नैनपुर

संपादकीय

कारोबारी अनिश्चितता

सर्वोच्च अदालत के फैसले से तिलमिलाए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों से आयात पर आधारभूत शुल्क 15 प्रतिशत करने की घोषणा की है। ट्रंप ने पिछले वर्ष आपातकालीन शक्तियों संबंधी एक कानून के तहत व्यापक शुल्क लगाए थे, लेकिन अदालत ने कहा कि यह कानून उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देता। फैसले के बाद ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की आलोचना करते हुए डेमोक्रेटिक जजों को 'राष्ट्र के लिए शर्म' बताया। उन्होंने कुछ रूढ़िवादी जजों के फैसले पर भी नाराजगी जताई। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आपातकालीन शक्तियों का सहारा लिया था, लेकिन अब उनके पास अन्य कानूनी विकल्प भी हैं, हालांकि उनमें अधिक समय लगेगा। अदालत के फैसले के तुरंत बाद 10 प्रतिशत का वैश्विक आधार शुल्क एक अन्य कानूनी प्रावधान के तहत लागू किया गया था। अब इसे बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। यह प्रावधान अधिकतम 150 दिनों के लिए 15 प्रतिशत तक शुल्क लगाने की अनुमति देता है।

इस अवधि के दौरान ट्रंप प्रशासन अन्य कानूनी विकल्पों की समीक्षा करेगा। प्रशासन व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 301 के उपयोग पर विचार कर रहा है। इसके तहत उन देशों पर शुल्क लगाया जा सकता है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों का उल्लंघन करते हैं या अमेरिकी व्यापार के साथ अनुचित व्यवहार करते हैं। हालांकि, इस प्रक्रिया में औपचारिक जांच और संबंधित देशों से परामर्श आवश्यक है, जिससे इसे लागू करने में लंबा समय लग सकता है। एक अन्य विकल्प व्यापार विस्तार अधिनियम 1962 की धारा 232 है, जिसका उपयोग 2018 में स्टील और एल्युमीनियम पर शुल्क लगाने के लिए किया गया था। लेकिन यह प्रावधान उत्पाद-विशिष्ट है और राष्ट्रीय सुरक्षा जांच की मांग करता है, इसलिए सभी आयातों पर व्यापक शुल्क लागू करने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का एक बड़ा असर शुल्क वापसी के मुद्दे पर भी पड़ा है। अदालत ने आपात शक्तियों के तहत वसूले गए शुल्क को अवैध ठहराया है। यदि इनकी वापसी होती है तो लगभग 175 अरब अमेरिकी डॉलर लौटाने पड़ सकते हैं। इस संबंध में आगे की कार्यवाही अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी अमेरिकी अदालत में हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य देशों के लिए 15 प्रतिशत की दर प्रतिस्पर्धा की स्थिति को बदल सकती है। हालांकि बीफ, महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा उत्पाद और दवाओं जैसे कुछ क्षेत्रों को छूट दी गई है। बहरहाल, शुल्क बढ़ोतरी के बावजूद वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता बनी हुई है। ट्रंप ने इसे स्थिरता की दिशा में कदम बताया है, लेकिन कानूनी और आर्थिक चुनौतियां अभी समाप्त नहीं हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में, पहले लागू 10 प्रतिशत की दर अन्य देशों की तुलना में कम थी, लेकिन अब 15 प्रतिशत की समान दर से प्रतिस्पर्धा का स्तर कुछ हद तक बराबर हो गया है। माना जा रहा है कि शुल्क बढ़ोतरी के बावजूद वैश्विक व्यापार पर अनिश्चितता बनी हुई है। ट्रंप ने दावा किया कि इससे महान स्थिरता वापस आई है, लेकिन विश्लेषक मानते हैं कि व्यापारिक और कानूनी चुनौतियां अभी समाप्त नहीं हुई हैं।

कल्पना नहीं, हकीकत है एआई की भारतीय दौड़

दिल्ली में गलगोटिया विवि के 'रोबोटिक डॉग' और 'ड्रोन सॉकर एरीना' के कारण हुई फज़ीहत के बाद कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत वास्तव में क्या कुछ कर भी पाएगा? हमारे पास उसके लिए पर्याप्त तकनीकी आधार और टेलेंट है भी या नहीं? बहरहाल, इस घटना ने सरकार समर्थित टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्मों पर स्वदेशी नवाचार की गलत व्याख्या की ओर देश का ध्यान आकर्षित किया है। सोशल-मीडिया के लिए ऐसी घटनाएं चटपटे मसाले की तरह होती हैं, कुछ समय तक याद रहती हैं और फिर बिसरा दी जाती हैं। बहरहाल, इस घटना ने हमें इसकी उपयोगिता और अपनी उपलब्धियों पर विचार करने की सलाह दी है। इसके पहले जनवरी में दावोस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा की इस टिप्पणी को लेकर भी विवाद हुआ था कि भारत 'सेकंड-टियर' एआई पॉवर है। राजनीति-शास्त्री आयन ब्रेमर ने भी इस बात का हवाला देते हुए कहा था कि नए उभरते देशों को अमेरिका या चीन के साथ तालमेल बिठाना चाहिए। इन दोनों बातों का तीखा जवाब देते हुए भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत एआई देशों की 'साफ पहली कतार' में है। उन्होंने एआई आर्किटेक्चर की पांच परतों के रूप में वर्णित भारत की प्रगति का विवरण दिया = एप्लिकेशन, मॉडल, चिप, बुनियादी ढांचे और ऊर्जा के सभी पांच स्तरों पर 'भारत अच्छी प्रगति' कर रहा है। उन्होंने स्टैनफर्ड विवि की एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें भारत को एआई प्रवेश और तैयारियों में तीसरे स्थान पर और वैश्विक स्तर पर एआई प्रतिभा में दूसरे स्थान पर रखा गया है। बाद में आईएमएफ की अधिकारी ने इस विवाद को ठंडा करते हुए कहा कि संगठन भारत की एआई प्रगति के लिए भारी प्रशंसा करता है। उन्होंने इस गलतफहमी के लिए मॉडरेटर को दोषी ठहराया। अंतरिक्ष-विज्ञान, कंप्यूटिंग-सॉफ्टवेयर, बायोटेक्नोलॉजी, सेमी कंडक्टर, एआई और डेटा साइंस जैसी तकनीकों को 'हाईटेक' माना जाता है। इनका इस्तेमाल चिकित्सा, विनिर्माण और अनुसंधान के अलावा रक्षा-तकनीक और अंतरिक्ष-विज्ञान जैसे क्षेत्रों में प्रमुखता से होता है। स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी की 2025 ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी रैंकिंग में भारत को अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर रखा गया है, जो लंबी छलांग है। नवंबर में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत एक साल में ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और जापान को पीछे छोड़ते हुए, चार पायदान ऊपर चढ़ गया है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नीति और शासन श्रेणी में भारत पांच पायदान फिसला भी है, जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। भारत का 2023 में सातवें से तीसरे स्थान पर पहुंचना वैश्विक एआई दौड़ में तेज गति को रेखांकित करता है। सरकार का अनुमान है कि भारत में अगले दो वर्षों में 200 अरब डॉलर से ज्यादा का पूंजी निवेश एआई पर ही आएगा। अमेरिका और चीन के भारी पूंजी निवेश को देखते हुए यह प्रगति प्रशंसनीय है। रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि दुनिया भर की सरकारें एआई निवेश बढ़ा रही हैं = कनाडा ने 2.4 अरब डॉलर, चीन ने 47.5 अरब डॉलर का सेमीकंडक्टर फंड लॉन्च किया है, फ्रांस ने 109 अरब यूरो का वादा किया है, भारत ने 1.25 अरब डॉलर की घोषणा की है, और सऊदी अरब का प्रोजेक्ट ट्रांसेंडेंस 100 अरब डॉलर के व्यापक प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। इन देशों के निवेश का कुछ हिस्सा भारत भी आएगा, क्योंकि भारत एआई के बड़े बाज़ार के रूप में विकसित हो रहा है। इसकी एक झलक दिल्ली में हुए एआई शिखर सम्मेलन में देखने को मिली, जिसमें 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष, 60 मंत्री और 500 वैश्विक एआई लीडर शामिल हुए हैं।

ग्लोबल साउथ में यह पहला वैश्विक एआई सम्मेलन है। इनमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ पेरेज़-कास्टेजोन और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के अलावा ओपनएआई के सीईओ सैम अल्टमैन, गूगल डीपमाइंड के सीईओ डेमिस हसाबिस और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, मुकेश अंबानी और माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ जैसे बड़े औद्योगिक पदाधिकारी शामिल थे। इससे पहले ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और फ्रांस में ऐसे सम्मेलन हो चुके हैं। बेशक भारत के पास अभी एआई की उन्नत विनिर्माण-सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि उसके लिए आवश्यक चिप्स का उत्पादन हमारे यहां अभी नहीं हो रहा है, पर देश का सेमीकंडक्टर मिशन बहुत तेजी से गति पकड़ रहा है, जो चिप्स उपलब्ध कराएगा। एआई का मतलब केवल चिप्स निर्माण नहीं है। टेक्नोलॉजी का निर्माण करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, जो अपना समय लेगी। अलबत्ता उसका इस्तेमाल करने वालों और उससे जुड़े इंजीनियरों और डेटा सेंटरों की संख्या हमारी प्रगति को बता रही है। एआई शोधकर्ताओं की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। इसकी प्रदर्शनी में उद्योग जगत के लीडरों, स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी प्रतिनिधियों और युवाओं की जैसी भीड़ आई, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उत्सुकता का स्तर क्या है। हाल के वर्षों में देश की व्यवस्था में डिजिटाइज़ेशन ने भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के दरवाज़े खोले हैं।

इस बात को समझने की ज़रूरत है कि एआई केवल रोबोटिक्स या गेमिंग नहीं है। उसकी भूमिका चिकित्सकीय और वैज्ञानिक अनुसंधान में है, प्रशासनिक कार्यों में है, खेती-किसानी में है। भारत में 90 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जो प्रतिदिन औसतन सात घंटे ऑनलाइन बिताते हैं। एनवीडिया, ओपन एआई, एंथ्रॉपिक और गूगल जैसी कंपनियां भारत में पैर जमाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। भारत सरकार प्रशासनिक और न्याय-व्यवस्थाओं को तेजी से प्रभावशाली बनाना चाहती है, जिसके लिए 'एआई-गवर्नेंस' के मॉडल सामने आ रहे हैं, वैसे ही जैसे देश ने 'डिजिटल-गवर्नेंस' को सफल बनाया। भारत में एकसाथ कई भाषाओं में तत्काल अनुवाद करने वाले एआई मॉडल की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। बेंगलुरु स्थित सर्वम एआई ने 18 फरवरी को दिल्ली में शिखर सम्मेलन के दौरान, चैटजीपीटी और डीपसीक जैसे अपने स्वयं के बड़े भाषा मॉडल विक्रम का अनावरण करके इस काम को पूरा कर दिखाया है। विदेशी मॉडलों के साथ भारतीय भाषाओं का मेल नहीं बैठ पाता है। टी-20 क्रिकेट विश्व कप के टीवी प्रसारण के दौरान चैटजीपीटी के विज्ञापन स्लॉट के पीछे की व्यावसायिक-योजना पर शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। कई लोगों की अच्छे स्कूलों तक पहुंच नहीं है, एआई उनकी मदद करेगा। भारत के जुगाड़-विशेषज्ञ बहुत जल्द इनके किफायती और आसान तरीके निकाल लेंगे। इंडिया एआई मिशन के तहत सरकार ने 38,000 जीपीयू को तैनात करने की योजना बनाई है, जो राष्ट्रीय स्तर पर साझा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी। इस साल एआई मिशन 2.0 के तहत 20,000 अतिरिक्त जीपीयू जोड़े जा रहे हैं, जिससे कुल क्षमता 58,000 जीपीयू हो जाएगी। जीपीयू या ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट शक्तिशाली कंप्यूटर चिप है जो मशीनों को तेज़ी से सोचने, छवियों को प्रोसेस करने, एआई प्रोग्राम चलाने, और जटिल कार्यों को सामान्य प्रोसेसर की तुलना में अधिक कुशलता से संभालने में मदद करता है। यह मिशन स्वास्थ्य, कृषि और सस्टेनेबल शहरों जैसे क्षेत्रों में एआई इनोवेशन को बढ़ावा दे रहा है। भारत में एआई टैलेंट पूल 2027 तक 6 लाख से बढ़कर 12.5 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन कंप्यूट पावर और फ्रंटियर मॉडल्स में अभी पीछे है। फिर भी, देश की विशाल जनसंख्या से उत्पन्न डेटा और युवा इंजीनियरिंग टैलेंट इस एआई रेस में हमें आगे रखेंगे।

– **प्रमोद जोशी**

एक बार साफ-साफ बतला दो करोगे कि नहीं...

प्रदेश में निगमों, मंडलों आयोगों प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियां का एक अंतहीन सिलसिला चल रहा है अपने को तो ये मालूम था कि हर चीज का अंत हो जाता है लेकिन ये नहीं मालूम था कि अपने ही प्रदेश में निगमों, मंडलों आयोगों, प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियों का अंत कभी नहीं होगा। कितने सावन, कितने फागुन, कितने माघ, कितने पूस, कितने जेठ, कितने बैसाख, और भी न जाने कितने मौसम निकल गए, गर्मी निकल गई, बरसात निकल गई, ठंड निकल गई अब फिर गर्मी आने वाली है लेकिन नियुक्तियों का नियुक्ति पत्र अभी तक किसी भी नेता के पास नहीं पहुंचा। पहले बिहार चुनाव की फांस, फिर मुख्यमंत्री का लफड़ा, फिर महाराष्ट्र निकाय निकायों के चुनाव, फिर महापौरों की झंझट, फिर पुराना साल, फिर नया साल, फिर मकर संक्रांति, फिर गणतंत्र दिवस, फिर बड़ा दिन, फिर बताया गया कि नहीं अब फरवरी के फर्स्ट वीक में तो किसी भी परिस्थिति में ये तमाम नियुक्तियां कर ही दी जाएंगी, वे तमाम नेता जो बेचारे पिछले तीन साल से इंतजार कर रहे थे खुश हो गए कि अब तो सारे कंटक दूर हो चुके हैं नियुक्तियां हो ही जाएंगी,लेकिन फिर एक खबर आई कि नहीं नहीं अभी इसकी आशा मत करो क्योंकि अभी प्रदेश सरकार का बजट आने वाला है अब जब बजट आ गया है तो उसका क्या रिपरकेशन जनता पर पड़ता है उसके बाद ही इस बारे में विचार किया जाएगा। 18 तारीख को प्रदेश का बजट भी आ गया नेताओं ने बजट के तारीफों के पुल भी बांध दिए बता दिया कि आज तक ऐसा बजट आया ही नहीं। अब तो नियुक्ति दे दो भैया लेकिन चार दिन तो बीत गए अभी तक नियुक्तियों की कोई खबर है नहीं। जो नेता मंडलों निगमों, प्राधिकरणों आयोगों में नियुक्ति की राह देख रहे हैं उनके कुर्ते पजामे का कलफ टूट गया, सफेद कुर्ते पैजामे मैले हो गए लेकिन कोई खबर नहीं आई। अपने को तो समझ में नहीं आता कि यदि हाई कमान को इन में नियुक्ति नहीं करना है तो एक बार साफ-साफ उन उम्मीदवारों को बता क्यों नहीं दिया जाता कि तुम लोग बेवजह परेशान मत हो और ना ही आशा करो, हम लोग कोई नियुक्तियां नहीं करेंगे एक बार साफ-साफ बता दोगे तो कम से कम रोज-रोज की झंझट और रोज के इंतजार से तो उन तमाम नेताओं को मुक्ति मिल जाएगी जो पिछले तीन साल से अपनी आंखों में आशा का दीप जलाए बैठे हैं ,लेकिन कहते हैं ना कि आशा से आसमान टंगा है इसलिए वे भी आशा नहीं छोड़ रहे उनका एक ही गीत है 'कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई नियुक्ति आदेश तो आएगा कुर्सी पर मुझे बिठाएगा' अब देखना ये है कि हाई कमान जीतता है या इन नेताओं की आशा।

लूट सके तो लूट

'राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट अंत काल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट' ये बड़ा पुराना दोहा है लेकिन इस दोहे को देशभर के बैंकों ने अपना लिया है। एक खबर आई है कि तमाम बैंकों ने 'मिनिमम बैलेंस' के नाम पर अपने खातेदारों से ग्यारह हजार करोड़ रूपया कमा लिया जिन-जिन के खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं था और जैसे ही उनका बैलेंस आया उसमें से उन्होंने उनका पैसा काट लिया और देखते-देखते यह राशि ग्यारह हजार करोड रुपए तक पहुंच गई, अभी अभी तो ये सिर्फ सरकारी बैंकों का मसला सामने आया है प्राइवेट बैंकों ने कितना माल लूट लिया है इसके आंकड़े तो तो अभी सामने आए ही नहीं हैं। आदमी बैंक में पैसा इसलिए रखता है कि जब जरूरत होगी तब निकाल लेगा एक तरफ सरकार जीरो बैलेंस पर खाता खुला रही है और इधर बेचारा मध्यम वर्गीय आदमी यदि मिनिमम बैलेंस नहीं रख पा रहा तो उसके पैसे बैंक वाले काटे पड़े हैं। अपने को तो लगता है कि ये तमाम बैंक वाले अपने कर्मचारियों की तनख्वाह इसी मिनिमम बैलेंस के नाम पर काटी गई राशि से बांट रहे हैं हर बैंक ने अपनी अपनी मिनिमम राशि तय कर दी है लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। वैसे इसमें बैंकों का कोई दोष नहीं है जब हर सरकारी दफ्तर में रिश्वत के नाम पर लूट मची हुई है तो फिर बैंक भला क्यों पीछे रहे, बैंकों में रिश्वत का कोई ज्यादा स्कोप होता नहीं है तो उन्होंने सोचा कि मिनिमम बैलेंस के नाम पर माल कमा लो। लोग बाग मांग कर रहे हैं कि ये मिनिमम बैलेंस वाला लफड़ा खत्म करो लेकिन अपने को मालूम है कि बैंक वाले फ्री फोकट में मिलने वाली करोड़ों की राशि छोड़ने के लिए कैसे तैयार होंगे अपनी तो लोगों को यही सलाह है कि भैया अपना पैसा अपने घर में रखो मिनिमम भी रहेगा तो कोई काटने वाला तो है नहीं, इनके चक्कर में पड़ोगे तो जितना जमा नहीं करोगे उससे ज्यादा वे काट लेंगे।

दारुखोरों की चांदी

सुना है कि 31 मार्च को प्रदेश के शराब के ठेके खत्म हो जाएंगे और नए ठेकों की शुरुआत होगी इसलिए स्टॉक का क्लीयरेंस करना बहुत जरूरी हो गया है शराब ठेकेदारों के लिए, इसलिए शराब ठेकेदारों ने अपनी शराब की कीमतों में तीस से लेकर पचास फीसदी की कमी कर दी है इस बात को लेकर दारुखोर सोसायटी में भारी खुशी और उल्लास का वातावरण है जो एक पाव पी रहा था वह अद्धा सुलटा रहा है जो आधा पाव पीता था वो पूरी बोतल गुटक रहा है और क्यों न पिए जब आधे दाम में माल मिल रहा है तो फिर पीने का मजा तो अपने आप बढ़ जाता है। कई जमाखोर तो अभी से दारू की बोतल खरीदें पड़े हैं क्योंकि दारू की कोई 'एक्सपायरी डेट' तो होती नहीं, कहा तो ये जाता है कि जो दारू जितनी पुरानी होती है उसका नशा उतना ही जबरदस्त होता है इधर ठेकेदार भी सोच रहा है कि स्टॉक क्लीयरेंस तो करना ही है ले जाने दो जिसको जितनी ले जानी है अपने माल की तो खपत तो हो रही है सरकार भी दारू पीने वालों के लिए बड़ी मेहरबान रहती है क्योंकि उसका खजाना भी तो यही दारू प्रेमी भरते हैं दारू न होगी तो खजाने में माल कैसे आएगा इसलिए हर साल नए ठेके देती है प्रदेश के कई शहरों में पचास फीसदी छूट के साथ शराब मिल रही है इसलिए उस शहर के आसपास के लोग उस शहर में जाकर माल इकठ्ठा करके अपने शहर वापस आ रहे हैं चलो किसी ने तो इन रिंदों का ध्यान रखा यही क्या कम है।

सुपर हिट ऑफ द वीक

प्रेम में असफल अपने दोस्त को श्रीमान जी ने ज्ञान देते हुए कहा

'अगर कोई लड़की आपको घास नहीं डालती तो निराश मत होइए क्योंकि आप गधे नहीं इंसान हो।'

कबीर के तीनों हाथों में लड्डू

पहुंचा हुआ ज्ञानी वह होता है जो ज्ञानवान होने के साथ-साथ कालखंड के हिसाब से अपने विचार में आवश्यकतानुसार परिवर्तन लाए। कबीर जी के साथ भी ऐसा ही है। समय के साथ-साथ उनकी सोच में परिवर्तन आया। पहले उन्हें जाने क्या होता था कि वह चलती चक्की के दो पाट देखकर रो देते थे।

कबीर दास जी के नश्वर संसार से देह त्यागने के बाद उनके चेले-चपाटी उनके इस रोने के दर्शन की गहराई में उतरे और उतरते ही चले गए। जब वह डूबने लगे तो बड़ी मुश्किल से जान बचाकर बाहर आए। बाहर खड़े अनुयायियों ने जब पूछा तो इज्जत बचाने के लिए बोले कि वह चक्की के दो पाट का दर्शन अच्छे से समझ गए हैं।

वास्तव में चलती चाकी का भेद वे 'एआई टूल' से समझे। समझते ही उनके ज्ञान चक्षु खटाक से खुल गए। और वह इनका महत्व भलीभांति समझ गए। वे समझ गए कि यह पाट और कुछ नहीं बल्कि पक्ष व विपक्ष के हैं। इसलिए अब वह चलती चाकी देखकर रोते नहीं, आंसू नहीं टपकाते बल्कि फुलझड़ी जैसे हंस रहे होते हैं।

कबीर दास जी के साथ पहले भी समस्या यह थी कि वह किस संप्रदाय के पक्ष में हैं, किस धर्म का समर्थन करते हैं। यह स्पष्ट नहीं हो पाता था। समय बदल गया परंतु यह बात अभी भी नहीं बदली। अभी भी लोगों के मन में जिज्ञासा है कि कबीर जी किस पार्टी के साथ हैं।

आज कबीर होते तो लोग कहते हैं आप पार्टी 'अ' के हैं। उनसे आपकी विचारधारा मेल खाती है। उनके लिए काम कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि आप 'ब' पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उनके एजेंट के रूप में काम करते हैं।

ज्ञानी लोगों की एक खूबी यह भी होती है कि वह कम बोलते हैं और मुस्कुराते ज्यादा हैं। मेरी अज्ञानता देखकर वह मंद-मंद मुस्कुराते।

हो सकता पत्रकार पूछते, 'अब तो आपने स्वयं की तीसरी पार्टी बना ली है।' कुछ लोग कह रहे हैं आप बीच के हैं। न इधर के न उधर के। कुछ लोग आपको लोटे की संज्ञा भी दे रहे हैं।

यह सुनकर कबीर जी जोर-जोर से हंसने लगते।

अर्थ पूछने पर दया कर वह 'ऑफ द कैमरा' बस इतना-सा बोलते- मेरे तो तीनों हाथों में लड्डू हैं। कहकर फिर से मौन धारण कर लेते।

हम जैसे उनकी गूढ़ बात की सतह पर ही तैर रहे होते। गहराई में उतरने में खुद को असहाय महसूस करते।

– **आलोक पुराणिक**

साइबर बदमाश का एपीआई पर प्रहार देगा आपको ऑनलाइन धोखाधड़ी का उपहार

भारत में डिजिटल भुगतान का विस्तार अभूतपूर्व है और यह विकसित भारत @2047 के लिए सशक्त आधारशिला भी है। मोबाइल ऐप्स, क्यूआर कोड और नेट बैंकिंग ने लेन-देन को सरल और तेज़ बना दिया है। लेकिन इसी सुविधा के साथ एक गंभीर खतरा भी जुड़ा है- साइबर अपराधियों द्वारा एपीआई (Application Programming Interface) का दुरुपयोग। हाल ही में भोपाल में हुई एक घटना इस खतरे को उजागर करती है जिससे ज्ञान चक्षु खुलना अनिवार्य है।

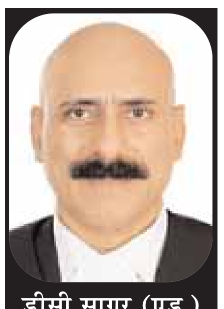

डीसी सागर (एड.)

पूर्व विशेष पुलिस महानिदेशक

घटना का विवरण- एक ग्राहक ने सड़क किनारे कैप बेचने वाले विक्रेता से QR कोड स्कैन कर भुगतान करने की कोशिश की। भुगतान असफल रहा। विक्रेता ने ग्राहक से मोबाइल जांचने के लिए मांगा। ग्राहक ने कुछ सेकंड के लिए फोन सौंप दिया। इन्हीं कुछ सेकंडों में विक्रेता ने मोबाइल के API और डेटा से छेड़छाड़ कर 3 लाख की राशि ग्राहक के बैंक खातों से निकाल ली। आश्चर्यजनक रूप से किसी भी लेन-देन से पहले ग्राहक को OTP तक नहीं मिला। यह घटना बताती है कि अपराधी अब केवल पासवर्ड या OTP चुराने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे सीधे API स्तर पर हमला कर रहे हैं।

OTP न आने पर बैंक की जिम्मेदारी

यदि किसी ग्राहक को OTP प्राप्त नहीं हुआ और फिर भी बैंक खाते से राशि डेबिट होकर धोखेबाज़ के खाते में चली गई, तो यह सिस्टम की विफलता (systemic failure) और बैंकिंग सुरक्षा व्यवस्था का टूटना है। ऐसे मामलों में ग्राहक दोषी नहीं माना जाएगा। RBI के उपभोक्ता संरक्षण नियमों के अनुसार, बैंक ही जिम्मेदार होगा और उसे ग्राहक को मुआवज़ा देना होगा। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि OTP सुरक्षा तंत्र का असफल होना बैंक की जवाबदेही को जन्म देता है।

API अटैक: तकनीकी दृष्टि से

API मोबाइल ऐप्स और बैंकिंग सर्वरों को जोड़ने वाली रीढ़ की हड्डी है। जब इनकी निगरानी नहीं होती, तो ये अपराधियों के लिए हाईवे बन जाते हैं। इस मामले में संभवतः

- API सत्र हाईजैक कर चुपचाप ट्रांज़ैक्शन किया गया।
- मैलिशियस रिक्वेस्ट इंजेक्ट कर बैंकिंग ऐप्स को धोखा दिया गया।
- कमज़ोर ऑथेंटिकेशन का फायदा उठाकर OTP सुरक्षा को दरकिनार किया गया।
- स्टोर किए गए टोकन/क्रेडेंशियल्स का दुरुपयोग कर कई खातों तक पहुंच बनाई गई।

वैश्विक उदाहरण और सबक

- Uber (2022) – MFA को बायपास कर हार्डकोडेड क्रेडेंशियल्स से सिस्टम तक पहुंच।
- T-Mobile (2023) – शैडो API से 37 मिलियन ग्राहकों का डेटा लीक।
- Twitter/X (2019) – API खामी से 1.7 करोड़ फोन नंबर खातों से जुड़े।
- Slack (सफल उदाहरण) – लेयर्ड सिक्योरिटी, RBAC और ज़ीरो-ट्रस्ट से API सुरक्षित।

सटीक सबक- केवल एक खामी नहीं, बल्कि निगरानी की कमी और अनियंत्रित एक्सेस ही सबसे बड़ा खतरा है।

साइबर अपराध के आँकड़े

- CERT-In के अनुसार भारत में साइबर घटनाएँ 2022 में 10.29 लाख से बढ़कर 2024 में 22.68 लाख हो गईं।
- RBI वार्षिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार बैंकों ने FY25 में 13,516 धोखाधड़ी मामलों की रिपोर्ट की, जिनमें ?520 करोड़ शामिल थे।

ये आँकड़े बताते हैं कि खतरा कितना बड़ा है और सतर्कता कितनी ज़रूरी है।

RBI दिशानिर्देश: ग्राहक की सुरक्षा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट सुरक्षा नियंत्रण (2024) में निर्देश दिए हैं=

- सभी डिजिटल भुगतान में मजबूत ऑथेंटिकेशन।
- रियल-टाइम फ्रॉड डिटेक्शन और अलर्ट।
- यदि ग्राहक दोषी नहीं है, तो उसकी लायबिलिटी सीमित होगी।

इस मामले में OTP साझा नहीं किया गया, इसलिए ग्राहक दोषी नहीं है। बैंक को जांच कर मुआवज़ा देना होगा।

IT Act और कानूनी उपाय

- धारा 43A – डेटा सुरक्षा में विफलता पर मुआवज़ा।
- धारा 66C, 66D – पहचान की चोरी और कंप्यूटर संसाधन से धोखाधड़ी पर सज़ा।
- धारा 72 – गोपनीयता का उल्लंघन करने पर दंड।
- Jan Vishwas Act 2023 – IT Act में संशोधन कर कई अपराधों को सिविल पेनल्टी में बदला गया।
- DPDP Act 2023 – व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा पर विशेष प्रावधान।

शासन द्वारा प्रदत्त संसाधन

- हेल्पलाइन 1930 – वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग।
- राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in) – ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।
- Cyber Dost (आईटी मंत्रालय) – साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान।

नागरिकों के लिए सुरक्षा रणनीति

- कभी भी अपना मोबाइल किसी अजनबी को न दें।
- बैंकिंग ऐप्स में बायोमेट्रिक लॉक लगाएँ।
- ऐप परमिशन नियमित रूप से जाँचें।
- ऐप्स को अपडेट रखें।
- धोखाधड़ी होते ही बैंक और 1930 पर रिपोर्ट करें।
- परिवार को जागरूक करें- अपराधी अक्सर बुजुर्गों को निशाना बनाते हैं।

त्वरित RBI शिकायत प्रक्रिया

1. तुरंत बैंक को सूचित करें और लिखित शिकायत दर्ज करें।
2. 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करें।
3. cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।
4. RBI उपभोक्ता संरक्षण नियमों का हवाला दें।
5. यदि समाधान न मिले, तो RBI Ombudsman से संपर्क करें।

निष्कर्ष

यह घटना स्पष्ट करती है कि डिजिटल सुविधा के साथ डिजिटल सतर्कता भी ज़रूरी है। यदि OTP नहीं आया और फिर भी राशि डेबिट हो गई, तो यह बैंकिंग सुरक्षा का टूटना है और बैंक ही जिम्मेदार है। API हमारी ऑनलाइन बैंकिंग की रीढ़ है, लेकिन यदि इन्हें सुरक्षित न रखा जाए तो यह राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। नागरिकों को सतर्क रहना होगा, बैंकों को RBI के निर्देशों का पालन करना होगा और सरकार की जागरूकता पहल जैसे Cyber Dost हर घर तक पहुँचनी

नीता भूषण पोलैंड में भारत की राजदूत बनीं

नई दिल्ली (वार्ता)। भारतीय विदेश सेवा की वरिष्ठ अधिकारी नीता भूषण को पोलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि भारतीय विदेश सेवा की 1994 बैच की अधिकारी नीता भूषण को पोलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। सुश्री भूषण अभी न्यूज़ीलैंड में भारत की उच्चायुक्त हैं। मंत्रालय ने कहा है कि सुश्री भूषण जल्द ही अपना कार्यभार संभालेंगी।

सेना ने सबसे बड़े ड्रग माफिया को मारा

मेक्सिको सिटी। मेक्सिको में सेना ने रविवार को एक ऑपरेशन चलाकर देश के सबसे बड़े ड्रग माफिया सरगना एल मेंचो को मार गिराया। इसके बाद देशभर में आगजनी और हिंसा शुरू हो गई है। मेंचो के समर्थकों ने बदला लेने के लिए हाईवे को जाम कर दिया है और गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। तलपला शहर में सेना के ऑपरेशन के दौरान वह घायल हो गया था। उसे एयरलिफ्ट कर मेक्सिको सिटी ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। इस ऑपरेशन में मेंचो के अलावा कम से कम और 9 अपराधी भी मारे गए हैं।

आर्मी पब्लिक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी

नई दिल्ली। दिल्ली कैंट स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल को सोमवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं हैं। सूचना मिलते ही स्कूल परिसर खाली करा लिया गया और तलाशी अभियान शुरू किया गया। दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वायड और दमकल विभाग की टीमें मौके पर मौजूद हैं। पुलिस के अनुसार, अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। ईमेल के सोर्स का पता लगाने के लिए साइबर सेल को जांच सौंपी गई है।

1492 मकानों में चला नगर निगम का बुलडोजर

राजकोट। गुजरात के राजकोट में नगर निगम ने शहर के जंगलेश्वर इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की है। इस कार्रवाई के तहत करीब 1492 मकानों को गिराए जाने का नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन के अनुसार कई निवासियों ने नोटिस मिलने के बाद अपने मकान स्वयं ही तोड़ दिए, जबकि बाकी मकानों को निगम की टीम हटा रही है।

कर्नाटक में दलित जोड़े को मंदिर जाने से रोका

तुमाकुरू। कर्नाटक के तुमाकुरू जिले में दलित जोड़े को मंदिर में एंट्री से रोका गया। युवक-युवती की हाल ही में शादी हुई थी। जैसे ही दोनों मंदिर पहुंचे नारायणप्पा नाम के व्यक्ति उन्हें रोक दिया। उसने कपल से कहा कि दलितों लोगों को घर पर ही पूजा करनी चाहिए, मंदिर नहीं आना चाहिए। घटना 21 फरवरी को तुमकुरु गांव के अरसम्मा मंदिर में हुई। पीड़ित जोड़े ने 5 लोगों के खिलाफ पुलिस शिकायत की। उनके मुताबिक आरोपी नारायणप्पा से सरेआम धमकाया था। मंदिर में मौजूद अन्य लोगों ने उसका समर्थन किया था। शिकायत के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी नारायणप्पा को गिरफ्तार किया। अन्य आरोपी फरार हैं।

गोवा नहीं...अब गंगा आरती है युवाओं की पहली पसंद

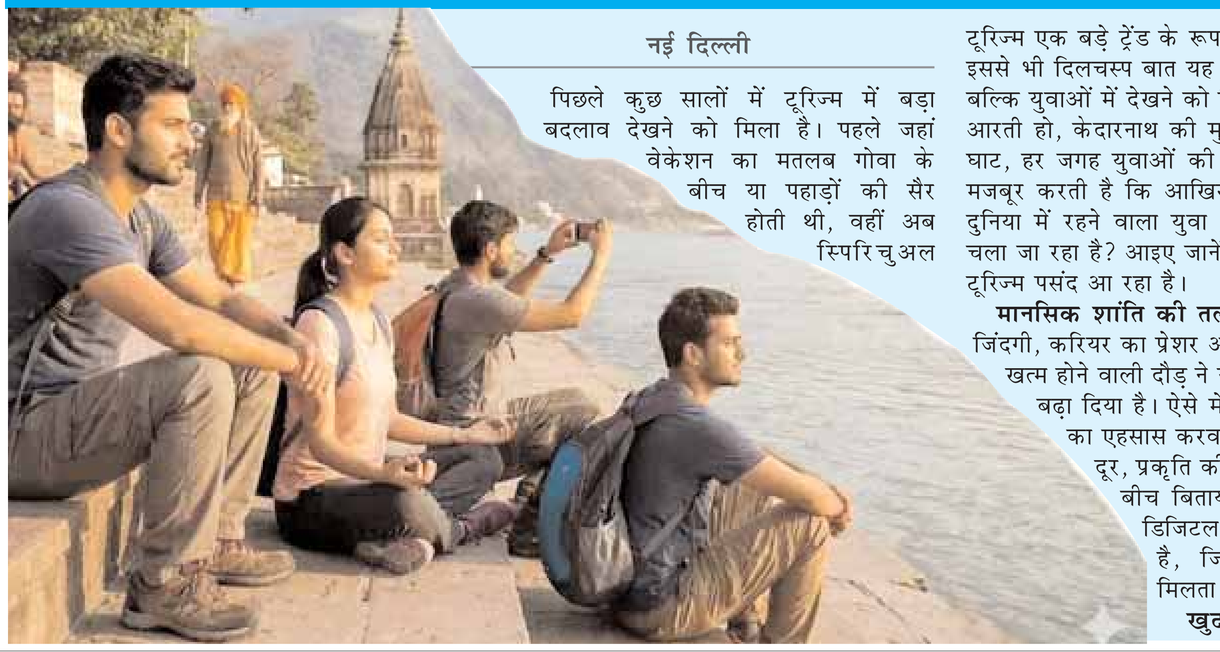

नई दिल्ली

पिछले कुछ सालों में टूरिज्म में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पहले जहां वेकेशन का मतलब गोवा के बीच या पहाड़ों की सैर होती थी, वहीं अब स्पिरिचुअल टूरिज्म एक बड़े ट्रेंड के रूप में ऊभर कर सामने आया है। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि यह ट्रेंड बुजुर्गों में नहीं, बल्कि युवाओं में देखने को मिल रहा है। ऋषिकेश की गंगा आरती हो, केदारनाथ की मुश्किल चढ़ाई या वाराणसी के घाट, हर जगह युवाओं की भारी मौजूदगी यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर तकनीक और चकाचौंध की दुनिया में रहने वाला युवा अध्यात्म की ओर क्यों खिंचा चला जा रहा है? आइए जानें क्यों युवाओं को स्पिरिचुअल टूरिज्म पसंद आ रहा है।

मानसिक शांति की तलाश- आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, करियर का प्रेशर और सोशल मीडिया की कभी न खत्म होने वाली दौड़ ने युवाओं में तनाव और बर्नआउट बढ़ा दिया है। ऐसे में आध्यात्मिक स्थल उन्हें शांति का एहसास करवाते हैं। स्मार्टफोन की स्क्रीन से दूर, प्रकृति की गोद में और मंत्रों की गूंज के बीच बिताया गया समय उनके लिए एक डिजिटल डिटॉक्स की तरह काम करता है, जिससे उन्हें मानसिक सुकून मिलता है।

खुद की खोज- आज का युवा केवल दुनिया नहीं देखना चाहता, बल्कि वह खुद को भी समझना चाहता है। स्पिरिचुअल टूरिज्म उन्हें आत्म-चिंतन का मौका देती हैं। योग, ध्यान और प्राचीन मंदिरों की वास्तुकला उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ती है। यह सिर्फ भगवान के दर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि खुद को तलाशने का भी एक जरिया बन रहा है।

ऑफ-बीट और एडवेंचर का मेल- आजकल के युवाओं के लिए स्पिरिचुअल टूरिज्म सिर्फ मंदिर जाने जैसा नहीं है; इसमें एडवेंचर का तड़का भी शामिल है। केदारनाथ, तुंगनाथ या अमरनाथ जैसी जगहों की यात्रा में मुश्किल ट्रेकिंग और प्राकृतिक सुंदरता का मेल होता है। मुश्किल रास्तों को पार कर जब वे मंजिल पर पहुंचते हैं, तो वह अनोखा एहसास होता है। थ्रिल और फेथ का यही कॉम्बिनेशन युवाओं को खूब आकर्षित कर रहा है।

सोशल मीडिया और विजुअल अपील- इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स ने भी इस ट्रेंड को बढ़ावा दिया है। जब हम सुंदर पहाड़ों के बीच स्थित प्राचीन मंदिरों या भव्य आरती के वीडियो देखते हैं, तो वैसा ही अनुभव करने की इच्छा जगती है। साथ ही, धार्मिक स्थलों की पॉजिटिविटी भी युवाओं को खूब भा रही है।

नदी में गिरी बस, 18 की मौत

काठमांडू। नेपाल के धादिंग जिले में सोमवार देर रात एक बस हाईवे से नदी में गिर गई। नेपाली मीडिया के मुताबिक हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 घायल हैं। मृतकों में एक पुरुष और एक महिला विदेशी नागरिक शामिल हैं। हालांकि, यह किस देश से थे और इनके नाम अभी सामने नहीं आए हैं। आर्म्ड पुलिस फोर्स के मुताबिक, अब तक 17 शव बरामद किए जा चुके हैं। बाद में एक अन्य यात्री की मौत की पुष्टि हुई, जिससे मृतकों का आंकड़ा 18 हो गया। हादसे में घायल लोगों को रेस्क्यू कर अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अब तक मृतकों और घायलों की पहचान नहीं हो सकी है। बस पोखरा से काठमांडू की ओर जा रही थी। हादसा देर रात करीब रात 1.30 बजे धादिंग जिले के बेनिघाट रोरांग इलाके में हुआ। फिलहाल पुलिस हादसे की अन्य वजहों की भी जांच कर रही है।

पुलिस हमें गिरफ्तार करेगी तो हम विरोध नहीं करेंगे : अविमुक्तेश्वरानंद

वाराणसी

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के खिलाफ प्रयागराज में दर्ज मुकदमे के बाद अब चर्चा है कि प्रयागराज पुलिस कार्रवाई के लिए वाराणसी पहुंच सकती है। इस संदर्भ में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान अपनी स्थिति स्पष्ट की। इस बाबत उन्होंने कहा, यदि पुलिस हमें गिरफ्तार करने की कार्रवाई करती है, तो हम उनका विरोध नहीं करेंगे। हम सहयोग करेंगे। जनता सब कुछ देख रही है... झूठ का पर्दाफाश अंततः हो ही जाता है। प्रयागराज में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ताकि यदि कुछ भी होता है, तो वे वॉर रूम से उस पर नजर रख सकें और सब कुछ रिकॉर्ड हो जाए। स्वामी ने यह भी कहा कि उनकी बस उनके कैंप के अंदर खड़ी नहीं थी, क्योंकि पुलिस की बर्बरता के बाद वे कैंप में नहीं गए थे। उन्होंने कहा, स्थिति को सीसीटीवी में देखा जा सकता है। हमने कभी गुरुकुल में पढ़ाई नहीं की और हमारा उनसे कोई लेना-देना नहीं है। मुकदमे में प्रस्तुत मार्कशीट से यह स्पष्ट होता है कि वे हरदोई के एक स्कूल के छात्र हैं। स्वामी ने सवाल उठाया कि जब वे कभी यहाँ आते ही नहीं और इस स्थान से उनका कोई संबंध नहीं है, तो कोई उनके खिलाफ कैसे कुछ कर सकता है? स्वामी ने यह भी कहा कि कुछ लोग सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए धर्म का चोला ओढ़कर आए हैं। उन्होंने कहा, वे स्वयं हिंदू हैं, लेकिन वे भ्रम फैला रहे हैं कि एक सीडी है, तो इसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? जनता को यह समझना चाहिए कि ऐसे लोग समाज में भ्रम पैदा कर रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने अनुयायियों से अपील की कि वे धैर्य रखें और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि सत्य की जीत होगी और जो लोग झूठ बोल रहे हैं, उनका पर्दाफाश होगा। उन्होंने यह भी कहा कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार की हिंसा या अव्यवस्था में शामिल नहीं होंगे। प्रयागराज पुलिस की कार्रवाई को लेकर स्वामी ने कहा कि वे पूरी प्रक्रिया का सम्मान करेंगे और कानून का पालन करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे अपने अनुयायियों को सही जानकारी देंगे ताकि कोई भी गलतफहमी न हो। स्वामी ने अंत में कहा कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए वे हमेशा तत्पर रहेंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने स्पष्ट किया कि वे किसी भी प्रकार की पुलिस कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हैं और सत्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं दूसरी ओर वाराणसी और श्रीविद्यामठ क्षेत्र में चर्चा बनी हुई है कि कभी भी प्रयागराज की पुलिस वाराणसी पहुंच सकती है। हालांकि कार्रवाई को लेकर टीम के आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

पाकिस्तान का दावा: अफगानिस्तान पर एयरस्ट्राइक कर 80 लड़ाके मारे

इस्लामाबाद

पाकिस्तान के उप गृह मंत्री तलाल चौधरी ने सोमवार को बताया कि अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों पर कार्रवाई की गई। उनके मुताबिक कम से कम 70 लड़ाके मारे गए। बाद में पाकिस्तानी मीडिया डॉन ने दावा किया कि मरने वालों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है। हालांकि सरकार ने इस दावे के समर्थन में कोई सबूत सार्वजनिक नहीं किया। दरअसल, पाकिस्तान की सेना ने रविवार तड़के अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में एयरस्ट्राइक की।

सेना ने कहा कि टीटीपी और इस्लामिक स्टेट से जुड़े 7 कैंपों को निशाना बनाया गया।

पाकिस्तान सरकार ने इसे हालिया आत्मघाती हमलों के बाद जवाबी अटैक बताया। पाकिस्तान ने कहा, 'हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि हमले अफगानिस्तान की जमीन से चल रहे नेटवर्क ने कराए।' वहीं अफगानिस्तान सरकार ने कहा कि हमले में मासूम नागरिकों को निशाना बनाया गया। मीडिया चैनल टोलो न्यूज के मुताबिक हमले में नांगरहार के एक घर को निशाना बनाया, जिससे एक ही परिवार के 23 लोग मलबे के नीचे दब गए। अमेरिकी मानवाधिकार संगठन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के मुताबिक इसमें 16 लोगों की मौत हो गई। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वह 2020 में दोहा में अमेरिका के साथ हुए समझौते के तहत तालिबान पर दबाव डाले, ताकि अफगान जमीन का इस्तेमाल दूसरे देशों के खिलाफ न हो। 2020 का दोहा समझौता जिसे अफगानिस्तान में शांति प्रयास भी कहा जाता है। यह अमेरिका और तालिबान के बीच 29 फरवरी 2020 को कतर की राजधानी दोहा में हस्ताक्षरित हुआ था। यह समझौता अफगानिस्तान में 2001 से चल रहे युद्ध को समाप्त करने और अमेरिकी बलों की वापसी का रास्ता बनाने के लिए किया गया था। तालिबान ने प्रतिबद्धता जताई कि वह अफगानिस्तान की जमीन को अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले किसी भी समूह या व्यक्ति को इस्तेमाल नहीं करने देगा। इसमें विशेष रूप से अल-कायदा और अन्य अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों से संबंध तोड़ने और उन्हें अफगानिस्तान में भर्ती, प्रशिक्षण, फंडिंग या हमले की अनुमति न देने का वादा शामिल था। समझौते के बाद अमेरिका ने 2021 में अपनी सेना वापस बुला ली, जिसके बाद तालिबान ने तेजी से काबुल पर कब्जा कर लिया अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने सही समय पर पाकिस्तान को जवाब देने की चेतावनी दी है।

पश्चिम बंगाल की जनता के लिए पीएम ने लिखी चिट्ठी

नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नागरिकों के नाम हिंदी और बांग्ला भाषा में एक खुला पत्र लिखा है। इमसें उन्होंने सीएए का जिक्र करते हुए घुसपैठ पर लगाम, राज्य के विकास, कानून-व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं के मुद्दों पर अपनी बात रखी है। उन्होंने लिखा कि अब बस कुछ ही महीने में पश्चिम बंगाल का भाग्य सुनिश्चित हो जायेगा। आने वाली पीढ़ी का भविष्य किस दिशा में आगे बढ़ेगा, यह आपके सोचे-समझे फैसले पर निर्भर करता है। मेरे सोनार बंगाल के सपने देखने वाला हर एक जवान, बूढ़ा और महिलाएं आज बहुत पीड़ा में हैं। इसलिए, मैंने मन की गहराइयों से एक संकल्प लिया है, पश्चिम बंगाल को 'विकसित' और समृद्ध बनाने का संकल्प। उन्होंने आगे लिखा- पिछले 11 वर्षों में देशवासियों के आशीर्वाद को ताकत बनाकर मेरी सरकार ने जनकल्याण और समग्र विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। किसानों के कल्याण से लेकर युवाओं के सपनों को साकार करने तक, और मातृशक्ति के सशक्तिकरण से लेकर समाज के हर वर्ग तक, हमारी नीतियों और निरंतर प्रयासों के सकारात्मक परिणाम आज साफ दिखाई दे रहे हैं। राज्य सरकार के असहयोग और विरोध के बावजूद, आज पश्चिम बंगाल के करीब 5 करोड़ लोग 'जन-धन योजना' के माध्यम से बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े हैं। 'स्वच्छ भारत अभियान' के तहत राज्य में 85 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है। जब राज्य की सत्ताधारी पार्टी गरीबों का निवाला छीन रही है।

फिल्म/टीवी मनोरंजन

हीरो से ज्यादा फीस लेने वाला विलेन असल जिंदगी में डरते थे लोग

आजादी से पहले हिंदी सिनेमा में कई कलाकार ऐसे रहे, जिन्होंने बतौर हीरो पर्दे पर अपनी छाप छोड़ी। लेकिन एक नाम ऐसा भी रहा, जिसने लीग से हटकर खलनायक की भूमिका को निभाकर खूब नाम कमाया। दमदार अभिनय से वह विलेन कैरेक्टर को इतनी शिद्दत से पेश करते थे कि असल जिंदगी में भी लोग उनसे डरने लगे थे। कमाल की बात ये थी कि वह फिल्म के लीड एक्टर से ज्यादा फीस तो नेगेटिव रोल प्ले करने के लिए वसूलते थे। ऐसे में आइए जानते हैं कि वह कौन सा दिग्गज अभिनेता था, जिसे बॉलीवुड का शेर खान कहा जाता था। जिस एक्टर के बारे में इस लेख में बात की जा रही है, उसे अपनी पहली फिल्म का ब्रेक पान की दुकान पर मिला था। 6 दशक से अधिक लंबे फिल्मी करियर में इस अभिनेता ने 400 से अधिक मूवीज में काम किया और इंडस्ट्री में एक लंबी पारी खेली। 12 फरवरी को इस कलाकार की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है और वह दिग्गज अन्य कोई नहीं बल्कि प्राण कृष्ण सिकंद यानी प्राण थे। जी हां अभिनेता प्राण ने अपने सुनहरे फिल्मी करियर में कई शानदार मूवीज के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किरदार चाहें कोई भी हो प्राण अपनी एक्टिंग के दमदार हुनर से उसमें जान फूंक देते थे। प्राण हिंदी सिनेमा के इकलौते ऐसे कलाकार थे, जो नेगेटिव करने के लिए मूवी की लीड एक्टर से ज्यादा फीस चार्ज करते थे। आजाद भारत से पहले अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाले प्राण ने उस दौर में करीब दो दर्जन फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाई। वह उस दौर के सबसे लोकप्रिय विलेन भी बन गए। गौर किया जाए उनकी कुछ उन चुनिंदा फिल्मों की तरफ, जिनमें वह विलेन बने थे, तो उनके नाम इस प्रकार हैं- आजाद, मधुमति, देवदास, दिल दिया दर्द लिया, मुनीमजी, राम और श्याम, अमरदीप, हलाकू, डॉन, कालिया। प्राण के एक्टिंग करियर के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली फिल्म जंजीर रही। 1973 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली अमिताभ बच्चन की इस मूवी में प्राण ने शेर खान की भूमिका को निभाया था। जंजीर में बेहतरीन एक्टिंग का इनाम उनको कुछ इस कदर मिला कि उन्हें सिनेमा के शेर खान का टैग मिल गया।

कहां गायब हैं नदिया के पार की 'गुंजा'

अभिनेता सचिन पिलगांवकर के साथ फिल्म नदिया के पार में नजर आने वालीं अभिनेत्री साधना सिंह अपने समय में काफी लोकप्रिय रहीं। इस मूवी में गुंजा की भूमिका अदा कर उन्होंने देश के कोने-कोने तक अपनी पहचान बनाई। लेकिन अब चार दशक बाद वह कहां और क्या करती हैं, इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। बदलते वक्त के साथ-साथ अब उनका लुक भी काफी हद तक बदल गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि साधना सिंह एक्टिंग छोड़ अब क्या करती हैं और कैसी दिखती हैं। 1982 में रिलीज होने वाली नदिया के पार हिंदी सिनेमा की कल्ट क्लासिक फिल्म मानी जाती है। साधना सिंह ने बड़ी ही बेहतरीन तरीके से गुंजा के किरदार को अदा किया और अमर कर दिया। एक वक्त पर अपनी बेबाक खूबसूरती के लिए मशहूर होने वाली साधना का लुक काफी बहुत बदल गया है। साधना सिंह के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर मौजूद उनकी इन लेटेस्ट तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। बढ़ती उम्र के साथ उनकी काया पूरी तरह पलट गई है। एक्टिंग के अलावा अब साधना सिंह एक फैशन डिजाइनर के तौर पर मुंबई में बुटीक भी चलाती हैं।

बाफ्ता में इंडियन फिल्म का दबदबा

लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में 79वां ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवॉर्ड (बाफ्ता 2026) का आयोजन हुआ। यह खूबसूरत शाम भारतीयों के लिए भी गर्व से भरा रहा। प्रतिष्ठित अवॉर्ड समारोह में भारतीय फिल्म बोंग ने बाजी मारी। हालांकि, जिसने सबसे ज्यादा धमाल मचाया, वो वन बैटल आफ्टर अनअदर थी जिसने बाफ्ता में कुल 6 अवॉर्ड अपने नाम किए। सिर्फ वन बैटल आफ्टर अनअदर ही नहीं, बल्कि बाफ्ता में आई स्वियर और हैमनेट जैसी फिल्मों का भी दबदबा रहा।

बाफ्ता अवॉर्ड्स की विनर्स लिस्ट

बेस्ट फिल्म- वन बैटल आफ्टर अनअदर

आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म- हैमनेट

लीडिंग एक्ट्रेस- जेसी बकले (हैमनेट)

लीडिंग एक्टर- रॉबर्ट अरामायो (आई स्वियर)

सपोर्टिंग एक्ट्रेस- वुनमी मोसाकु (सिनर्स)

सपोर्टिंग एक्टर- सीन पेन (वन बैटल आफ्टर अनअदर)

बेस्ट डायरेक्टर- पॉल थोमस एंडर्सन (वन बैटल आफ्टर अनअदर)

आउटस्टैंडिंग डेब्यू बाय अ ब्रिटिश राइटर, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर- माय फादर्स शैडो

फिल्म नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज- सेंटिमेंटल वैल्यू

आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश कॉन्ट्रिब्यूशन टू सिनेमा- क्लेयर बिन्स

बेस्ट डॉक्युमेंट्री- मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन

बेस्ट एनिमेटेड फिल्म- जूट्रोपोलिस 2 (जोटोपिया सीक्वल)

बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म- बोंग

बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीनप्ले- सिनर्स

बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीनप्ले- वन बैटल आफ्टर अनअदर

बेस्ट ओरिजिनल स्कोर- लुडविग गोरान्सन

बेस्ट कास्टिंग- आई स्वियर

बेस्ट सिनेमैटोग्राफी- वन बैटल आफ्टर अनअदर

बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन- फ्रेंकस्टीन

बेस्ट एडिटिंग- वन बैटल आफ्टर अनअदर

प्रोडक्शन डिजाइन- फ्रेंकस्टीन

मेकअप एंड हेयर- फ्रेंकस्टीन

बेस्ट साउंड- एफ1

स्पेशल विजुअल अफेक्ट्स- अवतार: फायर एंड ऐश

बता दें कि इंडियन मणिपुर लैंग्वेज फिल्म बोंग ने बाफ्ता में बेस्ट चिल्ड्रन और फैमिली फिल्म का अवॉर्ड जीता। इसका निर्देशन और लेखन लक्ष्मीप्रिया देवी ने किया था, जबकि फिल्म का निर्माण फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी ने किया। फिल्म की कहानी मणिपुर के हालात को बयां करती है।

आईसना पत्रकार संगठन के समारोह में वरिष्ठ पत्रकार जाट, राठौर, कुशवाहा का हुआ सम्मान

नरसिंहपुर। स्वतंत्रमत।

आइसना पत्रकार संगठन द्वारा विगत नो वर्षों से बरमान में पत्रकार मिलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन सतत रूप से किया जा रहा है जिसमें वरिष्ठ पत्रकारो और सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों का सम्मान किया गया मां नर्मदा के तट सीढी घाट पर आयोजित कार्यक्रम में भोपाल एवं जबलपुर से पधारे वरिष्ठ पत्रकारो एवं प्रदेश संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विनय डेविड, प्रदेश महासचिव पंडित विनोद मिश्रा, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अमर नोरिया, प्रदेश संगठन महामंत्री मंत्री प्रशांत बैश्य, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रहलाद कोरव, सचिव कुणाल सिंह , कार्यक्रम के जिला संयोजक केशव स्थापक , कार्यक्रम प्रभारी और जिला अध्यक्ष राजेश लोधी संगठन को लेकर और पत्रकारिता क्षेत्र को लेकर अपने-अपने विचार रखें। उन्होंने कहा कि आज पत्रकारिता बहुत कठिन दौर से गुजर रही है धरातल की पत्रकारिता वही है जो हर छोटे बड़े मुद्दे जनता से जुड़े मुद्दे उठाये, घोटालो को जनता के सामने लाना ,अपनी कलम से उसे उजागर करना ,यही असली पत्रकारिता है पर आज ऐसे पत्रकारों को सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है जो घोटालो की परत खोल रहे है । इस सफल कार्यक्रम के लिए सभी ने संगठन के सदस्यों की एकता एकजुटता की भी प्रशंसा की और कहा कि संगठन,लगातार कार्य कर रहा है, तो संगठन के सदस्यों की एकजुटता से ऐसे आयोजन सतत रूप से होना संभव है । कार्यक्रम के प्रारंभ में स्वागत भाषण कार्यक्रम के सूत्रधार मंजीत छाबड़ा ने दिया। वरिष्ठ पत्रकार नीलेश जाट ,सौरव राठौर और गाडरवारा के वरिष्ठ पत्रकार परमेश्वर कुशवाहा (पंन्नू भैया)का नगद राशि और स्मृति चिन्ह भेट कर सम्मान किया गया । वहीं गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए करने के लिए संघर्ष करने वाले अनुराग भार्गव , सिख समाज से भी वरिष्ठजन शामिल हुये जिसमें जनरल सिंह और ळखवीर सिंह द्वारा भी अपने विचार रखे । बुद्ध प्रकाश विश्वकर्मा को नशे के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और सुरेश ठाकुर को समाज सेवा के लिए, संगठन के सहयोग के लिए बरमान के युवा पत्रकार सुभाष और वरिष्ठ पत्रकार चंद्रशेखर मालवीय को सम्मानित किया गया।

इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष द्वारा सभी पत्रकार बंधुओ को उनके लिए प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया। जिसमें गौरव रैकवार, धर्मपाल रजक, शिल्पी जैन ,सचिन जोशी, मालती गुर्जर ,अरुण शर्मा,दीपक अग्रवाल, रंजीत तोमर, डाक्टर बृजेश रजक, अंकित नेमा आशीष दुबे, लीलाधर लोधी यश वर्मा, दीपक मुदगल सहित अनेक पत्रकारों को सम्मान पत्र प्रदत्त किये गये । मंच संचालन मंजीत छाबड़ा और आभार कार्यक्रम के सयोजक केशव स्थापक ने किया।

चिया सीड से चमकी किस्मत, 13 एकड़ में उगी सफलता की फसल

जिले के कृषक भैयालाल पटेल ने दिखाई राह

नरसिंहपुर। स्वतंत्रमत। परंपरागत खेती से आगे बढ़ते हुए जिले के नरसिंहपुर तहसील के ग्राम धुबघट के प्रगतिशील कृषक श्री भैयालाल पटेल ने अपनी 13 एकड़ कृषि क्षेत्र की भूमि में सुपरफूड चिया सीड की खेती कर कृषि नवाचार की नई दिशा प्रस्तुत की है। कम लागत, कम पानी और अधिक लाभ देने वाली इस फसल ने जिले के किसानों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल दिए हैं। उपसंचालक कृषि श्री मोरिस नाथ, परियोजना संचालक आत्मा श्री आरपी झारिया एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र नरसिंहपुर डॉ. विशाल मेश्राम ने खेत का भ्रमण कर फसल की स्थिति का निरीक्षण किया तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन एवं सामयिक सलाह दी। अधिकारियों ने कृषक के इस प्रयास की सराहना करते हुए इसे जिले के अन्य किसानों के लिए प्रेरणादायी बताया। कृषक श्री पटेल ने बताया कि चिया सीड की फसल लगभग 100 से 120 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी बुवाई माह अक्टूबर-नवंबर (रबी सीजन) में की जाती है तथा प्रति एकड़ लगभग 2.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। यह फसल कम उर्वरक एवं सीमित सिंचाई में तैयार हो जाती है और पशुओं से भी सुरक्षित रहती है। प्रति एकड़ 4 से 6 क्विंटल तक उत्पादन प्राप्त होता है। वर्तमान में इसका थोक बाजार मूल्य 21 से 23 हजार रुपये प्रति क्विंटल तक है, जिससे प्रति एकड़ एक लाख रुपये से अधिक की आय संभावित है। चिया सीड को चिकित्सकीय दृष्टि से सुपरफूड माना जाता है। इसमें ओमेगा- 3 फैटी एसिड, फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम एवं एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हृदय स्वास्थ्य, पाचन तंत्र, वजन नियंत्रण एवं ब्लड शुगर प्रबंधन में सहायक हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग निरंतर बढ़ रही है। इसका प्रमुख विपणन क्षेत्र नीमच, जबलपुर एवं राजस्थान है।कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले में इस प्रकार के नवाचार को बढ़ावा दिया जाए तथा अन्य किसानों को फील्ड भ्रमण के माध्यम से चिया सीड की खेती के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि उनकी आय में वृद्धि हो और कृषि को अधिक लाभकारी बनाया जा सके।

कलेक्टर की पहल पर सीडब्ल्यूएसएन छात्रावास के दिव्यांग बच्चों का कराया शैक्षणिक भ्रमण

हरी झंडी दिखाकर बस को झोतेश्वर के लिए किया रवाना

नरसिंहपुर। स्वतंत्रमत। कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह की विशेष पहल के अंतर्गत सीडब्ल्यूएसएन छात्रावास नरसिंहपुर के दिव्यांग बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए झोतेश्वर रवाना किया गया। डाइट प्राचार्य श्री राजीव श्रीवास्तव ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में डीपीसी श्री मनीष चौकसे, एपीसी श्रीमती अंजू शर्मा, एपीसी श्री समीर त्यागी, श्री आनंद शर्मा, श्री संतोष वैष्णव एवं श्री दीपक श्रीवास्तव मौजूद थे। भ्रमण के लिए डॉ. मंजू सिसोदिया एवं डॉ. मनीष सिसोदिया द्वारा स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में छात्रावास के वार्डन प्रमोद विश्वकर्मा, समस्त छात्रावास स्टाफ, एमआरसी रश्मि पटवा, स्वतंत्र खरे, ब्रजेश राय एवं कल्पना राय का योगदान रहा। यह शैक्षणिक भ्रमण दिव्यांग बच्चों के लिए सीखने, आत्मविश्वास बढ़ाने एवं आनंददायक अनुभव प्राप्त करने का सशक्त माध्यम सिद्ध हुआ। ऐसे प्रयास समावेशी शिक्षा की भावना को सुदृढ़ करते हुए बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

होलिका दहन के दौरान गौकाष्ट से निर्मित लकड़ी का ही उपयोग हो : कलेक्टर

जिला शांति समिति की बैठक सम्पन्न

नरसिंहपुर। स्वतंत्रमत।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती रजनी सिंह की अध्यक्षता में जिले में आगामी त्यौहारों को शांतिपूर्वक मनाए जाने के लिए जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। यह बैठक जिले में आगामी 2 मार्च को होली (धुरेड़ी), 8 मार्च को रंगपंचमी, 19 मार्च को चैत्र नवरात्र प्रारंभ और 21 मार्च को ईद-उल-फितर का त्यौहार शांतिपूर्वक मनाये जाने के संबंध में उक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषीकेश मीणा, नगर पालिका अध्यक्ष श्री नीरज दुबे, महंत प्रीतमपुरी गोस्वामी, पं. मैथिलीशरण तिवारी, डॉ. हरगोविंद सिंह पटेल, श्री लाल साहब जाट, श्री नरेन्द्र राजपूत, श्री विनय जैन, श्री किशन गुप्ता, श्री मनमोहन सिंह सलूजा, श्री तरवर सिंह पटेल, गुड्डू मालगुजार, श्री बलवीर सिंह, श्री दिनेश दुबे, श्री प्रताप सिंह गुमास्ता, श्री शिवकुमार सिंह राजपूत सहित अन्य सदस्यगण और अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर श्रीमती सिंह ने कहा कि जिले में बोर्ड परीक्षाएं संचालित हो रही हैं, इसे दृष्टिगत रखते हुए होली के अवसर पर लाउड स्पीकर निर्धारित स्तर पर ही बजाया जावे। होलिका दहन के दौरान स्वास्थ्य और पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए गौकाष्ट से निर्मित लकड़ी का ही उपयोग किया जाये। इसके लिए वन विभाग के डिपो में भी गौकाष्ट से निर्मित लकड़ी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने नगर पालिका के अधिकारियों को निर्देशित किया कि त्यौहारों के समय साफ-सफाई और पानी की आपूर्ति पर विशेष ध्यान दिया जाये। सिविल सर्जन को निर्देशित किया गया कि वे जिला अस्पताल में आकस्मिक चिकित्सा दल की ड्यूटी मय दवाओं सहित लगाना सुनिश्चित करें। साथ ही एम्बुलेंस भी तैयार रखें। रमजान का त्यौहार शांतिपूर्वक मनाया जा रहा है, इसी तरह की परंपरा जिले में बनी रहे। बैठक में नागरिकों से अपील की गई है वे सभी त्यौहार आपसी सौहार्द और शांति पूर्वक मनाएं। बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीणा ने कहा कि लाउड स्पीकर का उपयोग निर्धारित सीमा में ही किया जावे। होलिका दहन बिजली के तारों के नीचे न करें। साथ ही किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ, टायर आदि का उपयोग होलिका दहन में नहीं किया जावे। जिले में शांति और सद्भाव के साथ त्यौहार मनाया जावे। पुलिस हर चौराहे पर तैनात रहेगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि रमजान त्यौहार के दौरान वातावरण दूषित न हो। सभी त्यौहार आपसी सौहार्द के साथ मनाया जावे। यदि कोई व्यक्ति वातावरण को दूषित करता है तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। नवरात्रि के दौरान जवारा जुलूस पूर्व में जिस तरह शांतिपूर्वक निकाले जाते हैं, इसी तरह शांति पूर्वक निकाला जाए। नवरात्रि के दौरान यदि दुर्गा जी की मूर्ति की स्थापना की जाती है, तो यातायात प्रभावित न हो सहित अन्य व्यवस्थाओं का ध्यान रखें। बैठक में कहा गया कि परंपरागत स्थल पर ही होलिका दहन किया जावे। होलिका दहन के दौरान आवागमन और विद्युत तार प्रभावित न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे।

रात्रि 11 बजे तक होलिका दहन कर लिया जावे। लोगों से जबरन चंदा नहीं वसूला जावे। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग अनुविभागीय दंडाधिकारी की अनुमति के बगैर न किया जावे। जिला शांति समिति की बैठक में व्यापारियों से अपील की गई है कि वे बाजार में अच्छी किस्म के हर्बल रंगगुलालों की ही बिक्री करें। बैठक में निर्देश दिए कि नगर पालिका/ नगर परिषद फायर बिग्रेड मय चालक दल के साथ पुलिस कंट्रोल रूम में उपलब्ध कराये। शासन के निर्देशानुसार जिले में शराब की दुकानें निर्धारित समय पर बंद कराई जावे। बैठक में बताया गया कि 21 मार्च को ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाएगा, जिसमें ईदगाह/ मस्जिदों में नमाज अदा की जाएगी। सभी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए जिले में दुर्गा मंदिरों व नमाज स्थलों पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रखा जावेगा।

त्यौहारों के दौरान समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार कार्यपालिक दंडाधिकारियों की ड्यूटी लगाएंगे। बैठक के अंत में शांति समिति के सदस्यों ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे जिले में होली एवं अन्य सभी त्यौहारों को शांति पूर्वक मनाएंगे।

सनातन ब्राह्मण महासभा के स्नेह-मिलन में उमड़ा समाज ज्ञापन के जरिए मुख्यमंत्री तक पहुंचाई 15 सूत्रीय मांगें

नरसिंहपुर। स्वतंत्रमत। सनातन ब्राह्मण महासभा नरसिंहपुर द्वारा आयोजित वार्षिक स्नेह-मिलन समारोह एवं सहभोज के अवसर पर समाज की एकजुटता देखने को मिली। इस गरिमामय आयोजन के दौरान महासभा ने सामाजिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विकास को लेकर एक व्यापक 15 सूत्रीय मांग पत्र स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम सौंपा। ज्ञापन में गौ, गीता, नर्मदा और संस्कृत के संरक्षण को सर्वोपरि रखते हुए गौ माता को राज्य माता घोषित करने और हर निकाय व ग्राम स्तर पर गौ-सेवकों की नियुक्ति के साथ रिक्त शासकीय भूमि गौशालाओं को सौंपने की मांग की गई है। साथ ही मां नर्मदा की निर्मलता बनाए रखने, मंदिरों को अतिक्रमण मुक्त कर उनके जीर्णोद्धार और श्रीमद् भागवत गीता को शिक्षण पाठ्यक्रमों में शामिल करने की वकालत की गई है। महासभा ने सामान्य वर्ग के हितों पर जोर देते हुए आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण (ईडब्ल्यूएस) परिवारों के लिए स्थाई प्रमाण पत्र जारी करने, आयु सीमा व शिक्षण शुल्क में छूट देने और स्थानीय निकायों में अन्य आरक्षित वर्गों की भांति स्थान आरक्षित करने की मांग उठाई है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नरसिंहपुर की आवश्यकताओं को देखते हुए जिले में संस्कृत, योग, आयुर्वेद, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और कृषि महाविद्यालय खोलने का आग्रह किया गया है। साथ ही संस्कृत पाठशालाओं के आधुनिकीकरण और आचार्यों की नियमित भर्ती की बात भी कही गई है।

ज्ञापन में एट्रोसिटी एक्ट के दुरुपयोग को रोकने के लिए बिना जांच के गिरफ्तारी न करने, पुजारियों व कर्मकांडी ब्राह्मण परिवारों को असंगठित क्षेत्र के श्रमिक लाभ देने और शासकीय सेवकों को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति देने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल किए गए हैं। इस दौरान महासभा के पदाधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों से इन मांगों पर शासन स्तर पर त्वरित संज्ञान लेने की अपील की है।

जनगणना का कार्य सभी अधिकारी रूचि लेकर समय सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें: कलेक्टर

नरसिंहपुर। स्वतंत्रमत। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी नरसिंहपुर श्रीमती रजनी सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनगणना 2027 के प्रथम चरण अंतर्गत मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना के कार्य के लिए दो दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण के प्रथम दिवस का प्रशिक्षण सोमवार को आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी चार्ज अधिकारी एवं अनुभाग चार्ज अधिकारी जनगणना के इस कार्य को रूचि लेकर समय सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। जनगणना दो चरणों में होगी, जिसमें पहला चरण एक मई से 30 मई 2026 तक होगी, जिसमें मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना और द्वितीय चरण फरवरी 2027 में जनसंख्या की गणना की जाएगी। जनगणना का कार्य निर्धारित समय सीमा में किया जाएगा। अतः समय सीमा में किसी भी प्रकार का विस्तार व परिवर्तन संभव नहीं है। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि जनगणना किसी देश में एक निश्चित समय पर प्रत्येक परिवार एवं प्रत्येक व्यक्ति की आधिकारिक पूर्ण गणना है, जिसमें उनके जनसांख्यिकीय, आर्थिक एवं सामाजिक आंकड़े शामिल होते हैं। अतः इसमें सावधानी से कार्य करना बहुत आवश्यक है। जनगणना में पहली बार लोग स्वगणना पोर्टल के माध्यम से अपने परिवार की जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं और यह कार्य 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होगा। उन्होंने डाटा कलेक्शन व जांच की प्रक्रिया सुपरवाईजर और प्रगणक, नगरीय व ग्रामीण क्षेत्र में अलग- अलग चार्ज अधिकारी के संबंध में जानकारी दी। यह प्रशिक्षण जनगणना निदेशालय के प्रशिक्षक मनोज नाथानी व सुश्री श्रुति पाटीदार ने दिया। उन्होंने प्रशिक्षण में मौजूद अधिकारी- कर्मचारियों की शंकाओं का समाधान किया। प्रशिक्षण में जिला जनगणना अधिकारी व डिप्टी कलेक्टर श्रीमती देवंती परते, अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी श्रीमती लता वान, अनुविभागीय जनगणना अधिकारी, चार्ज अधिकारी तहसीलदार, सीएमओ चार्ज अधिकारी सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे।

अपाक्स की बैठक आयोजित

नरसिंहपुर। स्वतंत्रमत। अपाक्स जिला अध्यक्ष विधि झारिया के निवास स्थान पर अपाकस की बैठक आयोजित की गई। जिसमें प्रमुख रूप से अपाक्स के संरक्षक काला पहाड़ ने संगठन को सुदृढ़ बनाने हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए ,बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनील चौहान प्रचार सचिव सुनीता चौहान कार्यकारिणी सदस्य रीता यादव, रोहित कहार एवं गोटेगांव ब्लॉक अध्यक्ष केदारनाथ कोरी उपस्थिति में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए ।अंत में विधि झारिया अपाक्स जिला अध्यक्ष द्वारा आभार प्रदर्शन किया गया।

मंदिर ट्रस्ट के खाते से 40 लाख बिना अनुमति निकले, जांच की मांग तेज

संपत्ति के दुरुपयोग को लेकर विवाद गहराया

गाडरवारा (स्वतंत्र मत)।

गाडरवारा स्थित लोकन्यास क्रमांक 449/55 श्री देव रामजानकी जगदीश मंदिर के ट्रस्ट खाते से कथित अनियमित आहरण और संपत्ति के दुरुपयोग को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। उक्त मामले में भाजपा नेता पवन पटेल ने क्षेत्रीय विधायक एवं परिवहन,शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह से सेवा सदन में मुलाकात कर एवं संबंधित लोकन्यास अधिकारी एसडीएम को लिखित शिकायत देकर जांच एवं कार्रवाई की मांग की गई है। भाजपा नेता पवन पटेल ने आरोप लगाया है कि मंदिर ट्रस्ट के बैंक खाते से महंत गोविंद दास ने बिना विधिवत प्रस्ताव और स्वीकृति के बड़ी राशि निकाली गई है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि मंदिर के खाते में लगभग 80ङ्क90 लाख रुपये की राशि जमा थी, जिसका उपयोग मंदिर की संपत्ति, जनहित एवं धार्मिक कार्यों के लिए होना था। आरोप है कि दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच लगभग 40 लाख रुपये निकाले गए, जिनके उपयोग का स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं है।

शिकायत में यह भी कहा गया है कि कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर राशि आहरित की गई तथा इस संबंध में सक्षम अधिकारियों को जानकारी दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बैंक खाते पर रोक लगाने, निकाली गई राशि की जांच/ऑडिट कराने और मंदिर की चल-अचल संपत्तियों के सत्यापन की मांग की गई है। कलेक्टर द्वारा पूर्व मे दिए गए डमरू घाटी के पीछे स्थित मंदिर की जमीन के सीमांकन के आदेश का भी पालन नहीं हुआ है। मंदिर की जमीन पर आसपास के किसानों का अवैध कब्जा भी है।

शिकायत की प्रतिलिपि संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को भी प्रेषित की गई है। शिकायतकर्ता ने निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि धार्मिक संस्थान की संपत्ति और आमजन की आस्था सुरक्षित रह सके।

समय-सीमा बैठक में सीएम हेल्पलाइन एवं विभागीय योजनाओं की समीक्षा

नरसिंहपुर।

कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने सोमवार को आयोजित समय सीमा की बैठक में सीएम हेल्पलाइन, टीएल पत्रों एवं विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री गजेन्द्र सिंह नागेश सहित अन्य जिला अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर ने लंबित टीएल पत्रकों की समीक्षा की कर समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण एवं त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने जिला पंचायत, वन विभाग, विद्युत विभाग, पशुपालन विभाग से संबंधित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में रूपांतरण की प्रक्रिया की भी विभागवार समीक्षा करते हुए आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। बैठक में समग्र आईडी से संबंधित प्रकरणों एवं ऋण वितरण योजनाओं की स्थिति की भी समीक्षा कर पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभान्वित करने के निर्देश प्रदान किए गए। कलेक्टर श्रीमती सिंह ने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाना अधिकारियों की सर्वोच्च जिम्मेदारी है।

समय-सीमा बैठक में शासकीय योजनाओं विकास कार्यों सहित लंबित पत्रों की हुई समीक्षा

निगमायुक्त परिहार ने अधिकारियों को लंबित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करानें दिए निर्देश

कटनी (स्वतंत्रमत)

नगर निगम आयुक्त तपस्या परिहार ने सोमवार को आयोजित समीक्षा बैठक में सीएम हेल्पलाइन की ग्रेडिंग, नगर निगम के माध्यम से संचालित योजनाओं एवं विकास कार्यों सहित समय सीमा में दर्ज लंबित पत्रों एवं प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में उपायुक्त शैलेष गुप्ता, प्रभारी कार्यपालन यंत्री सुधीर मिश्रा, अंशुमान सिंह, असित खरे, राजस्व अधिकारी जागेश्वर प्रसाद पाठक सहित अन्य शाखाओं के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में आयुक्त ने वरिष्ठ कार्यालयों से प्राप्त पत्रों, समय-सीमा में दर्ज लंबित पत्रों की विभागवार समीक्षा की तथा विभागीय अधिकारियों को लंबित पत्रों का समयबद्ध निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागवार सीएम हेल्पलाइन की ग्रेडिंग की समीक्षा कर अधिकारियों को रोजाना प्राप्त शिकायतों को अटेंड कर गुणवत्ता युक्त निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान आयोग से प्राप्त पत्रों एवं न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा कर निगमायुक्त ने त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रतिवेदन दर्ज कराने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। निगमायुक्त द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रेमनगर बस्ती मल्टी में कराये जा रहे विद्युतीकरण के शेष कार्य तथा कार्य को पूर्ण करने की समय-सीमा की जानकारी लेते हुए समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने पर संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी करते हुए कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश विद्युत विभाग को दिए गए। आईएचएसडीपी योजना के अंतर्गत प्राप्त 690 आवेदनों पर भवन आवंटन की कार्यवाही हेतु स्थल निरीक्षण कर वर्तमान में आवासों में निवासरत हितग्राहियों की पात्रता जांच के संबंध में उपयंत्रियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा कर जांच प्रतिवेदन शीध्र प्रस्तुत कर नियमानुसार आवेदनों का निराकरण करने के निर्देश उपयंत्रियों को दिए। बैठक के दौरान नागरिकों को निगम के बकाया कर को जमा करने एवं निगम की सेवाओं का आसानी से लाभ प्राप्त करने हेतु आयोजित हो रहे राजस्व वसूली शिविरों में ई-नगर पालिका ऐप का भी प्रचार-प्रसार कराते हुएए क्यूआर कोड के माध्यम से नागरिकों को ऐप डाउनलोड करने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश निगम अधिकारियों को दिए। निगमायुक्त ने बैठक के दौरान अवैध निर्माण, कंपाउंडिंग तथा अवैध कॉलोनी के प्रकरणों पर की गई कार्यवाही की समीक्षा करते हुए गंभीरता से कार्यवाही करने के निर्देश कार्यपालन यंत्री अंशुमान सिंह को दिए। इस दौरान उन्होंने उपयंत्रियों को सतत रूप से वार्डो का निरीक्षण कर अवैध कालोनी निर्माण के प्रकरणों पर गंभीरता से रोक लगाने हेतु निर्देशित किया।

महापौर ने 41 लाख के डामरीकरण कार्यों का किया निरीक्षण

सुदृढ़ सड़कों से सशक्त शहर की ओर कदम

कटनी (स्वतंत्रमत)

शहर में आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में नगर निगम द्वारा निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को महापौर प्रीति संजीव सूरी ने क्षेत्रीय पार्षद सुरेंद्र गुप्ता एवं अन्य एमआईसी सदस्यों के साथ विवेकानंद वार्ड अंतर्गत लगभग 41 लाख रुपये की लागत से किए जा रहे डामरीकरण कार्यों का विस्तृत स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान मेयर इन काउंसिल सदस्य सुभाष साहू, डॉ रमेश सोनी, उमेंद्र अहिरवार, बीना बैनर्जी, पार्षद शकुंतला सोनी समाजसेवी संजय तिवारी सहित अन्य जनों की मौजूदगी रही। महापौर ने विक्रम स्कूल गली, साउथ स्टेशन रोड तथा त्रिलोकीनाथ मंदिर के आसपास विभिन्न स्थानों पर बन रही सड़कों का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता, डामर की मोटाई, सड़क की चौड़ाई, समतलीकरण, जल निकासी व्यवस्था एवं किनारों की मजबूती की अधिकारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान महापौर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्य पूर्णत: निर्धारित मानकों, स्वीकृत एस्टीमेट एवं तकनीकी प्रावधानों के अनुरूप ही किया जाए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। महापौर ने कहा कि नगर के नागरिकों को बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध कराना निगम की प्राथमिकता है। अच्छी सड़कों से न केवल आवागमन सुगम होता है, बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास को भी गति मिलती है। निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय नागरिकों ने महापौर से भेंट कर चल रहे निर्माण कार्यों पर संतोष व्यक्त किया। रहवासियों ने कहा कि लंबे समय से सड़क की समस्या बनी हुई थी, जिसके कारण आवागमन में कठिनाई होती थी। अब डामरीकरण कार्य से क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। नागरिकों ने विकास कार्यों के लिए नगर निगम एवं महापौर का आभार व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि भविष्य में भी इसी प्रकार क्षेत्र में निरंतर विकास कार्य होते रहेंगे।

मिड डे मील में अनियमितताओं की शिकायत, छात्रों की सेहत पर सवाल

कटनी (स्वतंत्रमत)

शासकीय माध्यमिक शाला पहरूआ एवं प्राथमिक शाला कुठला (शहरी क्षेत्र) में मध्यान्ह भोजन योजना के तहत गंभीर अनियमितता सामने आई है। छात्रों को परोसे गए कढ़ी-चावल से जली हुई गंध आने की शिकायत दर्ज की गई, जिससे बच्चों की सेहत और भोजन की गुणवत्ता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। आकस्मिक निरीक्षण के दौरान जन शिक्षक मनीष दीक्षित एवं अजय चतुर्वेदी ने पाया कि छात्रों को दिए गए कढ़ी-चावल में जली हुई गंध आ रही थी। निरीक्षण के बाद तत्काल शहरी क्षेत्र में भोजन वितरण की प्रभारी सुमित साकेत को फोन पर सूचना दी गई। प्रभारी द्वारा आधे घंटे के भीतर छात्रों को दूसरा भोजन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया, लेकिन शाम 4 बजे तक बच्चों को वैकल्पिक भोजन उपलब्ध नहीं कराया गया। घटना की जानकारी जन शिक्षकों द्वारा बीआरसीसी मनोज गौतम को भी दी गई है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की अपेक्षा जताई जा रही है।

आज निगम कार्यालय में प्रातः 11 बजे से आयोजित होगी महापौर जनसुनवाई

नागरिकों की शिकायतों एवं समस्याओं पर सुनवाई कर निराकरण की दिशा में महापौर सूरी की अभिनव पहल निरंतर जारी

कटनी (स्वतंत्रमत)

आम नागरिकों की नगर निगम कार्यालय से संबंधित समस्याओं एवं शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण हेतु विगत 17 जनवरी से प्रारंभ की गई महापौर प्रीति संजीव सूरी की अभिनव पहल के तहत आज 24 फरवरी को नगर निगम के मेयर इन काउंसिल सभागार में प्रात: 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक महापौर जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। शहर के आम नागरिक जनसुनवाई में समस्याओं एवं शिकायतों से संबंधित आवेदन लेकर महापौर के समक्ष स्वयं प्रस्तुत कर सकते है। महापौर प्रीति संजीव सूरी ने कहा कि यह पहल सुशासन, जवाबदेही से कार्य करनें की दिशा में एक मजबूत कदम है, जिससे प्रशासन और नागरिकों के बीच विश्वास बढ़ रहा है। नगर निगम प्रशासन का उद्देश्य केवल समस्याएं सुनना ही नहीं, बल्कि उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित कराना है। ताकि नागरिकों को बार-बार निगम कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होने नागरिकों से जनसुनवाई कार्यक्रम का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने का आग्रह किया है। उल्लेखनीय है कि महापौर प्रीति संजीव सूरी की अभिनव पहल के तहत प्रत्येक मंगलवार को निगम कार्यालय में आयोजित होनें वाली महापौर जनसुनवाई के दौरान नागरिकों द्वारा निगम कार्यालय से संबंधित शासकीय योजनाओं एवं सेवाओं से संबंधित समस्याएं, जैसे स्वच्छता, जलापूर्ति, सड़क, प्रकाश व्यवस्था, अतिक्रमण, संबंधी शिकायतें एवं अन्य नगर निगम से जुड़ी समस्याएं सीधे प्रस्तुत किये जाते है जिनपर गंभरतापूर्वक सुनवाई उपरांत महापौर द्वारा संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवेदों एवं शिकायतो पर समयबद्ध तरीके से कार्यवाही के निर्देश प्रदान किये जाकर शिकायतों के निराकरण की स्थित की सतत समीक्षा भी की जा रही है।

नागरिकों की जल संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु वार्ड स्तरीय जल सुनवाई का आयोजन आज

आवेदन पर सुनवाई के साथ ही पेयजल नमूनों का किया जायेगा परीक्षण

कटनी (स्वतंत्रमत)

शासन निर्देशों के अनुपालन में निगम प्रशासन द्वारा शहर वासियों को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल आपूर्ति हेतु मुस्तैदी से प्रयासों के साथ ही नगर निगम के माध्यम से नागरिकों को की जाने वाली पेयजल आपूर्ति से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या अथवा शिकायत के त्वरित निराकरण सहित आवश्यक सुझाव प्राप्त हेतु मंगलवार 24 फरवरी को वार्ड स्तरीय जल सुनवाई का आयोजन किया गया है। महापौर प्रीति संजीव सूरी एवं निगमायुक्त तपस्या परिहार ने जल प्रदाय शाखा के अधिकारियों को वार्ड स्तरीय जल सुनवाई के दौरान नागरिकों से जलापूर्ति से संबंधित प्राप्त होने वाली समस्याओं एवं आवेदनों पर सुनवाई करते हुए उन पर शीघ्रता से आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। उपयंत्री मृदुल श्रीवास्तव ने बताया कि जल सुनवाई के तहत वार्ड क्रमांक 1 से 15 तक के लिए प्रात: 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सुनवाई की जायेगी। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 16 से 30 तक के लिए 12:30 बजे से 2:30 बजे तक तथा वार्ड क्रमांक 31 से 45 तक के लिए जल सुनवाई का आयोजन दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। जल सुनवाई में नगर निगम कटनी की जल प्रदाय शाखा के अधिकारी, प्रशिक्षित कर्मचारी एवं फील्ड स्टाफ मौजूद रहेंगे, जो प्राप्त शिकायतों पर गंभीरतापूर्वक सुनवाई करते हुए त्वरित निराकरण सुनिश्चित करेंगे। जल सुनवाई के दौरान नागरिकगण पेयजल की गुणवत्ता, पाइप लाइन लीकेज अथा जल आपूर्ति से संबंधित समस्याओं का आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। इसके अलावा नागरिकगण जल सुनवाई के दौरान घरों में सप्लाई किये जाने वाले पेयजल का नमूना भी साथ में लाकर पेयजल की गुणवत्ता का परीक्षण जल सुनवाई के दौरान करके उसकी गुणवत्ता रिपोर्ट से अवगत हो सकेंगे। नागरिकों से वार्डवार आयोजित होने वाले जल सुनवाई का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने की अपील निगम प्रशासन ने की है।

अभाविप का आंदोलन एक्टिव मोड मे प्रशासन

कटनी (स्वतंत्रमत)। विगत 18 फरवरी को कैमूर के एक शासकीय विद्यालय की दीवार गिरने से हुई मासूम छात्र की मौत पर विद्यार्थी परषद ने दिनांक 19 तारीख को एसडीएम कार्यालय में उग्र आंदोलन करते हुए पीड़ित परिवार के लिए सहायता राशि, विजयराघवगढ़ क्षेत्र के सभी शैक्षिक परिसरों का सर्वेक्षण जैसी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 3 दिन में कार्यवाही की मांग की थी। तत्पश्चात प्रशासन एक्टिव मोड में दिखा एवं प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित परिवार को 200000 रुपए की राशि संबल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी एवं 50000 रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है एवं कुछ अन्य सहयोग भी प्रदान किए गए हैं घटना की निष्पक्ष जांच हो जिसके लिए प्रशासन द्वारा अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं एवं क्षेत्र में सभी जर्जर स्कूलों, भवनों की जांच और मरम्मत हो और बम्हनंगवा में छात्र की मौत के लिए दोषियों पर कार्यवाही करने की मांगे शामिल थीं जिन पर प्रशासन एक्टिव मोड में है।

होली पर रेलवे ने दी स्पेशल ट्रेनों की सौगात

कटनी होकर चलेंगी कई स्पेशल ट्रेनें

कटनी (स्वतंत्रमत)

होली को मद्देनजर रखते हुए रेलवे ने पांच जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। एक ट्रेन डॉ आंबेडकर नगर से पटना के बीच कटनी जंक्शन होकर चलाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक ट्रेन नंबर 09343 डॉ अंबेडकर नगर पटना साप्ताहिक स्पेशल हर गुरुवार को शाम 6 बजे डॉ आंबेडकर नगर से चलकर रतलाम मंडल के इंदौर, फतेहाबाद चंद्रावतीगंज, उज्जैन एवं मक्सी होते हुए अगले दिन शाम 06:30 बजे पटना पहुंचेगी। ये ट्रेन डॉ आंबेडकर नगर से 26 फरवरी से 26 मार्च तक चलाई जाएगी। इसी तरह ट्रेन नंबर 09344 पटना डॉ आंबेडकर नगर स्पेशल हर शुक्रवार को रात 09:30 बजे पटना से चलकर रतलाम मंडल के मक्सी, उज्जैन, फतेहाबाद चंद्रावतीगंज एवं इंदौर होते हुए अगली रात 11:55 बजे डॉ. आंबेडकर नगर पहुंचेगी। ये ट्रेन पटना से 27 फरवरी से 27 मार्च के बीच चलाई जाएगी। ये स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में इंदौर, फतेहाबाद चंद्रावतीगंज, उज्जैन, मक्सी, संत हिरदाराम नगर, विदिशा, बीना, सागर, दमोह, कटनी मुड़वारा, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा एवं दानापुर स्टेशनों पर रुकेगी। होली पर्व के मद्देनजर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पश्चिम मध्य रेल द्वारा वलसाड-दानापुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन कटनी स्टेशन पर दोनों दिशाओं में ठहरेगी, जिससे क्षेत्र के यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। गाड़ी संख्या 09025 वलसाड-दानापुर स्पेशल 23 फरवरी से प्रत्येक सोमवार को रात 1:05 बजे कटनी पहुंचेगी। वहीं गाड़ी संख्या 09026 दानापुर वलसाड स्पेशल 24 फरवरी से प्रत्येक मंगलवार को सुबह 4:20 बजे कटनी आएगी। ट्रेन में एसी, स्लीपर व सामान्य श्रेणी सहित कुल 20 कोच रहेंगे। यात्रियों को होली यात्रा में सीधा लाभ मिलेगा।

अतिक्रमण हटाओ अभियान से मुख्य मार्गों एवं बाजार क्षेत्रों का आवागमन हो रहा सुगम एवं व्यवस्थित

नियमों का उल्लंघन करने पर विगत सप्ताह 27 हजार से अधिक की लगाया स्पॉट फाइन

कटनी (स्वतंत्रमत)

शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारु रख नागरिकों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन मुहैया करानें के उद्धेश्य से निगमायुक्त तपस्या परिहार के निर्देश पर निगम की अतिक्रमण शाखा की पृथक-पृथक टीमों द्वारा रोजाना नगरीय एवं उरपनगरीय क्षेत्रों में अभियान चलाकर सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करानें की कार्यवाही की जा रही है। वहीं नियमों का उल्लंघन करनें वालों की सामग्री जब्ती एवं स्पॉट फाईन की कार्यवाही के साथ ही बिना अनुमति अनाधिकृत निर्माण कार्यो सहित अवैध कॉलोनी के प्रकरणों पर भी कार्यवाही का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। अतिक्रमण प्रभारी मानेन्द्र सिंह ने बताया कि अतिक्रमण दल द्वारा अभियान के तहत नगर के मुख्य मार्गो थाना तिराहा से एसबीआई तिराहा होते हुए महारानी लक्ष्मी बाई तिरहा, सुभाष चौक, स्टेशन रोड पहुंच मार्ग, बरही रोड, सिल्वर टॉकीज रोड गर्ग चैराहा, मिशन चौक से जगन्नाथ चैक होते हुए बस स्टैंड एवं बस स्टैंड परिसर सहित बाजार क्षेत्रों झंडा बाजार, कपड़ा बाजार, गोल बाजार में अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान मुख्य मार्ग के किनारे अनाधिकृत रूप से बैठकर व्यवसाय करनें वाले सब्जी विक्रेताओं तथा ठेला संचालकों को मुनादी के माध्यम से सार्वजनिक मार्ग से हटाकर जिला चिकित्सालय के सामने निर्मित हाकर्स जोन भेजकर तथा व्यवस्थित कर आवागमन व्यवस्था व्यवस्था को सुगम किया जा रहा है। सुचारू आवागमन व्यवस्था के मद्देनजर बाजार क्षेत्रों के अंदरूनी मार्गो की सुचारू व्यवसायियों के बोर्ड एवं दुकान सामग्री आदि को सार्वजनिक मार्गो से पृथक कराने के साथ ही सुभाष चैक एवं देश भंडार के सामने मार्ग पर फूल माला विक्रय करने वाले व्यवसायियों को सार्वजनिक मार्ग से अलग करते हुए निर्धारित स्थल चौपाटी के बाहर स्थित फूल मंडी भेजने के प्रयास किये जा रहे है। इसके अलावा नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों को हटानें के साथ ही अव्यवस्थित वाहनों पर चालानी कार्यवाही जारी रखी जाकर नागरिको को सुगम आवागमन व्यवस्था मुहैया करानें के प्रयास निरंतर जारी है। अतिक्रमण प्रभारी मानेन्द्र सिंह ने बताया कि सुगम आवागमन व्यवस्था के मद्देनजर चलाये जा रहे अभियान के तहत विगत एक सप्ताह में लगभग 30 प्रकरणों पर जब्ती की कार्यवाही की जाकर लगभग 27 हजार 300 रुपये का स्पॉट फाईन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त अवैध प्लाटिंग के एक प्रकरण सहित बिना अनुमति निर्माण के 6 प्रकरणों तथा सार्वजनिक मार्गो में कबाड़ सामग्री रखने के तीन प्रकरणों में सामग्री जब्जी एवं जुर्मानें की कार्यवाही की गई है।

दबदबे की विरासत जारी रखने उतरेगा कर्नाटक

रणजी ट्रॉफी के फाइनल में जम्मू-कश्मीर से मुकाबला आज

हुबली (वार्ता)

हुबली क्रिकेट मैदान पर मंगलवार को रणजी ट्रॉफी 2025-26 के फाइनल में मेजबान कर्नाटक अपने दबदबे की विरासत को जारी रखने, जबकि जम्मू-कश्मीर ऐतिहासिक प्रदर्शन कर पहली चैंपियन बनने उतरेगा। एक ओर जहां घरेलू कर्नाटक क्रिकेट टीम है। जो अनुभव, स्वभाव और बड़े मैचों की जानकारी के बल पर आठ बार चैंपियन बनी है। वहीं दूसरी ओर 67 साल के इतिहास में पहली बार फाइनल में पहुंची जम्मू-कश्मीर की टीम के संघर्ष और जूनून की कहानी है। कर्नाटक की बल्लेबाजी लाइनअप में जबरदस्त दम और अंतरराष्ट्रीय पहचान है। केएल राहुल जैसे खिलाड़ियों की क्लास और संयम टॉप पर स्थिरता देते हैं, जबकि मयंक अग्रवाल और करुण नायर जैसे अनुभवी घरेलू चैंपियन रेड-बॉल में अपना दबदबा साबित करते हैं। कर्नाटक के इस सीजन में घरेलू सनसनी स्मरण रविचंद्रन का भी जलवा रहा है, जिन्होंने जबरदस्त औसत से रन बनाए हैं, जिससे वह टूर्नामेंट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजो में से एक बन गए हैं। श्रेयस गोपाल के ऑलराउंड असर के साथ, कर्नाटक का फॉर्मूला आसान है। टोटल बनाना, सेशन को कंट्रोल करना और गेम को बेरहमी से खत्म करना। लेकिन क्रिकेट, खासकर लंबे प्रारुप के फाइनल में, शायद ही कभी यह सबसे बड़े नामों से तय होता है। यह उन खिलाड़ियों से

तय होता है जो जब मोमेंटम बदलने लगता है तो चुपचाप मैच को एक साथ रखते हैं। वहीं जम्मू और कश्मीर क्रिकेट टीम के लिए, यह फाइनल केवल एक चैंपियनशिप मुकाबला नहीं है, यह इतिहास है। उनका पहली बार रणजी ट्रॉफी फाइनल में पहुंचना पहले ही सीजन की सबसे इंस्पायरिंग कहानियों में से एक बन गया है। उनका अभियान किसी एक सुपरस्टार पर निर्भर रहने के बजाय मिलकर लड़ने की भावना के आस-पास बना है। इस कहानी के शांत हीरो ऑलराउंडर आकिब नबी रहे हैं। टूर्नामेंट में 50 से अधिक विकेट और बल्ले से निचले क्रम में अहम योगदान के साथ, उन्होंने टीम के प्रेशर-ब्रेक स्पेशलिस्ट की तरह काम किया है। जब साझेदारी बढ़ने लगीं, तो उन्होंने ब्रेकथ्रू दिलाए। जब बल्लेबाजी के गिरने का खतरा था, तो उन्होंने पारी को संभाला।

जम्मू-कश्मीर की बल्लेबाजी

जम्मू-कश्मीर की बल्लेबाजी को पारस डोगरा जैसे अनुभवी कप्तान ने भी संभाला है, जिनकी दबाव वाली स्थिति में शांत मौजूदगी ने युवा खिलाड़ियों को गाइड किया है। शुभम खजूरिया और कमरन इकबाल के टॉप-ऑर्डर सपोर्ट ने शुरुआती मोमेंटम दिया है, जबकि अब्दुल समद और आबिद मुश्ताक की मध्यमक्रम स्टेबिलिटी ने दबाव बनने पर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया है।

कर्नाटक अपने ब्लूप्रिंट पर निर्भर

कर्नाटक अपने पारंपरिक चैंपियनशिप ब्लूप्रिंट पर निर्भर रहेगा। प्रसिद्ध कृष्णा, विद्वाथ कवरप्पा जैसे तेज गेंदबाजी विकल्प की लीडरशिप में गेंदबाजी आक्रमण और अनुभवी कैंपेनर्स का सपोर्ट यह पक्का करता है कि वे लहरों में अटैक कर सकें। श्रेयस गोपाल का स्पिन कंट्रोल अक्सर पिच के टूटने पर अहम हो जाता है।

गेम को कंट्रोल करेंगे स्पिनर

हुबली की पिच के असली टेस्ट मैच जैसा बनने की उम्मीद है। शुरुआती दिनों में बाउंस और मूवमेंट वाले तेज गेंदबाजों को फायदा होगा, जबकि धैर्य दिखाने वाले बल्लेबाज स्कोरिंग फेज में हावी रहेंगे। तीसरे और चौथे दिन तक, जैसे ही सतह पर दरारें दिखेंगी, स्पिनर गेम को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे।

दोनों टीमें इस प्रकार हैं

कर्नाटकः- केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, देवदत्त पडिक्कल, करुण नायर, स्मरण रविचंद्रन, कृतिक कृष्णा, श्रेयस गोपाल, विद्याधर पाटिल, विद्वाथ कवरप्पा, व्यशाक विजयकुमार, प्रसिद्ध कृष्णा, शुभांग हेगड़े, निकिन जोस और मनीष पांडे।

जम्मू और कश्मीरः- शुभम खजूरिया, कमरन इक़बाल, शुभम पुंडीर, पारस डोगरा, अब्दुल समद, आबिद मुश्ताक, औकिब नबी, युदवीर सिंह, सुनील कुमार, वंशज शर्मा, कन्हैया वधावन, अब्दुल समद और विवरंत शर्मा।

किदांबी श्रीकांत जर्मन ओपन में भारतीय चुनौती की करेंगे अगुवाई

जर्मनी (वार्ता)

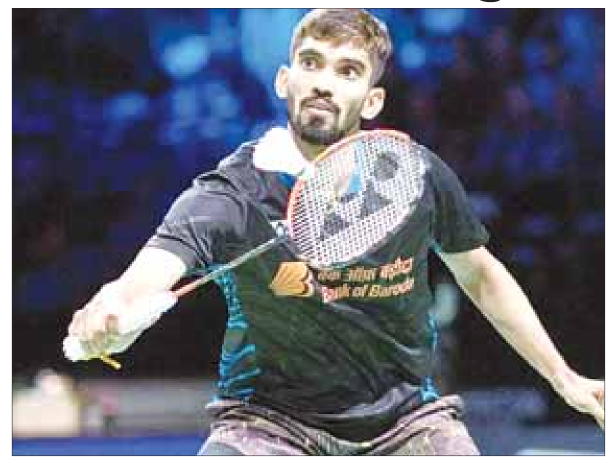

दुनिया के पूर्व नंबर वन किदांबी श्रीकांत मंगलवार से मुलहेम एन डेर रूर के वेस्टएनर्जी स्पोर्टहॉल में शुरू होने वाले जर्मन ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती अगुवाई करेंगे। पुरुषों की एकल बैडमिंटन रैंकिंग में 32वें स्थान पर काबिज किदांबी श्रीकांत, इस साल की शुरुआत में इंडिया ओपन और इंडोनेशिया मास्टर्स में दो क्वार्टर-फाइनल से बाहर होने के बाद जर्मन ओपन में उतरेंगे। उन्हें आखिरी बार इस महीने की शुरुआत में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में खेलते हुए देखा गया था, जहां उन्होंने भारत के लिए अपने दोनों एकल रबर जीते थे। पुरुषों के एकल मुख्य ड्रॉ में किदांबी श्रीकांत के साथ उनके हमवतन किरण जॉर्ज और थारुन मन्नेपल्ली भी होंगे। ओलंपियन और दुनिया के नंबर 5 खिलाड़ी फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव पुरुष एकल में टॉप सीड हैं और पहले राउंड में किरण जॉर्ज से भिड़ेंगे। दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु की गैरमौजूदगी में दुनिया की नंबर 40 तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स में भारत की कमान संभालेंगी। तन्वी शर्मा, जो पिछले साल बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप और यूएस ओपन में उप विजेता रही थीं, उनके साथ महिला एकल के मुख्य ड्रॉ में तस्नीम मीर, मालविका बंसोड़, रक्षिता रामराज और इशारानी बरुआ होंगी। महिला युगल के मुख्य ड्रॉ में भारत की अकेली जोड़ी अश्विनी भट और शिखा गौतम हैं।

72वीं कबड्डी चैंपियनशिप वडोदरा में आज से

वडोदरा (वार्ता)

72वीं सीनियर नेशनल्स पुरुषों की कबड्डी चैंपियनशिप 2026, 24 से 27 फरवरी तक यहां समा इनडोर कॉम्प्लेक्स में खेली जायेगी। इस चैंपियनशिप में देश भर से 31 टीमें हिस्सा लेंगी और लगभग 400 खिलाड़ी खिताब जीतने के लिए एक-दूसरे को कड़ी टक्कर देंगे। अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत होने वाले इस टूर्नामेंट में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ-साथ उभरते सितारे भी भाग लेंगे। प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी भी इस चैंपियनशिप के दौरान एक्शन में दिखेंगे।

हम अगले मैच में मजबूत वापसी करेंगेः सूर्यकुमार

अहमदाबाद (वार्ता)। भारतीय टी-20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि हम सुपर आठ के अगले मैच में मजबूती के साथ वापसी करेंगे। दक्षिण अफ्रीका से 76 रनों की हार के बाद सूर्यकुमार ने कहा,

उम्मीद है कि अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी और अच्छा क्षेत्ररक्षण करेंगे। बस इतना ही। हम इसे सरल रखने का प्रयास करेंगे। हम जैसा क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वैसा ही क्रिकेट खेलेंगे, और कुछ नहीं बदलेगा और मुझे लगता है कि हम मजबूती से वापसी करेंगे। दक्षिण अफ्रीका से भारत की 76 रन की हार ने टूर्नामेंट में उसकी 12 मैचों की जीत का सिलसिला खत्म कर दिया और डिफेंडिंग चैंपियन को सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए मुश्किल रास्ते पर छोड़ दिया। अब उन्हें मुकाबले में बने रहने के लिए अपने शेष सुपर आठ मैचों में जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी। भारत का अगला मुकाबला गुरुवार को चेन्नई में जिम्बाब्वे से होगा। सूर्यकुमार ने कहा कि टीम अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी और टूर्नामेंट के नॉकआउट चरण के लिए भी क्वालीफाई करेगी। हार को लेकर उन्होंने कहा, कभी-कभी आपको सोचना पड़ता है, अगर आप 180-185 रन का पीछा कर रहे हैं, तो आप पावरप्ले में गेम नहीं जीत सकते, लेकिन आप पावरप्ले में गेम हार सकते हैं।

राष्ट्रीय खेल उत्सव का केंद्र बना गुलमर्ग

खेलो इंडिया विंटर गेम्स का शुभारंभ

श्रीनगर (वार्ता)

केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को गुलमर्ग में 6वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का विधिवत उद्घाटन किया। देश के प्रमुख शीतकालीन खेल केंद्र गुलमर्ग में आयोजित चार दिवसीय इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 1,000 खिलाड़ी और अधिकारी भाग ले रहे हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स एक साधारण खेल आयोजन से आगे बढ़कर राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप ले चुका है। यह आयोजन शांति, समानता और सौहार्द के मूल्यों को पुनर्जीवित करता है तथा विविध भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं वाले देश में एक साझा विरासत के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा,

विंटर गेम्स जीवन की चुनौतियों का प्रतिबिंब हैं, जो खिलाड़ियों में दृढ़ता और आत्मविश्वास का निर्माण करते हैं। गिरना, गलतियों का विश्लेषण करना और बेहतर बनकर उठना-यही खेल की असली सीख है, जिसे स्कीयर यहां आत्मसात करेंगे। उपराज्यपाल ने इस आयोजन के व्यापक उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स राष्ट्रीय एकता को सशक्त बनाने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और आपसी सम्मान साथ-साथ चल सकते हैं और आज समाज को इसी भावना की आवश्यकता है। अल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और स्की माउंटेनियरिंग जैसी स्पर्धाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में खिलाड़ी अपनी तकनीकी दक्षता, वर्षों की मेहनत और अदम्य साहस का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने प्रतिभागियों से खेल भावना के उच्चतम मानकों को बनाए रखने और पूरे टूर्नामेंट में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का आह्वान किया। उपराज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर में खेल क्षेत्र में हुए बदलावों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) के तहत अत्याधुनिक खेल अवसंरचना की स्थापना और 100 खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना से खेल परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि सच्चा खिलाड़ी जीत में विनम्र और हार में गरिमामय रहता है। उन्होंने कहा, 26 फरवरी को समापन समारोह में इस आयोजन की सफलता का आकलन केवल पदकों से नहीं, बल्कि एकता, आपसी सम्मान और उत्कृष्टता की निरंतर खोज की भावना से किया जाएगा।

इंडियन गोल्फ में 830 करोड़ रुपये निवेश करेगा आईजीपीएल

नई दिल्ली (वार्ता)

इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग (आईजीपीएल) ने देशभर के 10 सहयोगियों से सोमवार को इंडियन गोल्फ में 100 मिलियन यूएस डॉलर (लगभग 830 करोड़ रूपये से अधिक) के निजी निवेश की घोषणा की। यह इंडियन गोल्फ में अब तक का सबसे बड़ा निजी निवेश है। इस घोषणा के तहत हर फ्रेंचाइजी ने 10 साल के समय में लगभग 10 मिलियन यूएस डॉलर देने का वादा किया है, जो बड़े मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स और उभरते मार्केट्स में रिप्रेजेंटेशन के साथ एक प्रोफेशनल गोल्फ लीग बनाने और उसे बढ़ाने के लंबे समय के प्लान को दिखाता है। ये फ्रेंचाइजी हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, विशाखापत्तनम, गोवा, बेंगलुरु, पंजाब और गुरुग्राम हैं, जिससे लीग के पहले संस्करण में देश भर में मौजूदगी पक्की हो गई है। निवेश के अलावा, सहयोगियों ने गोल्फ के विस्तार और इस तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से ढांचागत विकास के लिए 250 मिलियन यूएस डॉलर देने का भी वादा किया है। इस प्लान में टियर 2 और टियर 3 शहरों और ग्रामीण इलाकों में छोटी गोल्फ फैसिलिटी बनाना शामिल है ताकि भागीदारी बढ़ाई जा सके और खेल को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जा सके। इस अवसर पर आईजीपीएल के मुख्य कार्यकारी उत्तम सिंह मुंडी ने कहा कि यह निवेश लीग के लॉन्ग-टर्म विजन में भरोसे को दिखाता है। मुंडी ने कहा, यह कोई पारंपरिक स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट नहीं है। हमारे फ्रेंचाइज पार्टनर आईजीपीएल को अपने मुख्य बिजनेस के लिए प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए स्पोर्ट्स कल्चर बनाने के एक लॉन्ग-टर्म मौके के तौर पर देखते हैं। 100 मिलियन यूएस डॉलर का वादा हमारे विजन में उनके भरोसे को दिखाता है।

भारत अभी नंबर-1 नहीं बनेगा तो कब बनेगा

नई दिल्ली (वार्ता)। वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने सोमवार को कहा कि परोपकारी सोच वाली उद्यमिता के साथ सरकार का प्रोत्साहन देश को दुनिया में नंबर-1 बना सकता है, और इसके लिए यह बिल्कुल सही समय है। श्री अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में यह बात कही। उन्होंने हिस्ट्री चैनल की एक श्रृंखला का जिक्र करते हुए अपनी बात शुरू की जिसमें अमेरिका के निर्माण के कर्णधारों के रूप में सिर्फ उद्यमियों को चुना गया है। उन्होंने अपने पोस्ट

में लिखा, अमेरिका को किसने बनाया? आपको जानकर आश्चर्य होगा- न कोई राजनेता, न वैज्ञानिक और न ही कोई बुद्धिजीवी। इस विषय पर हिस्ट्री चैनल की एक शानदार श्रृंखला है, जिसमें उन्होंने केवल उद्यमियों को चुना है। हिस्ट्री चैनल ने कॉर्नेलियस वेंडरबिल्ट, एंड्रयू कार्नेगी, जॉन रॉकफेलर, जे.पी. मॉर्गन और हेनरी फोर्ड को चुना है जिन्होंने क्रमशः अवसंरचना, इस्पात, तेल, बैंकिंग और ऑटोमोबाइल जैसे बुनियादी और प्रमुख उद्योगों की नींव रखी।

एमबीडी-रेडिसन समूह 10 साल में 50 नये होटल खोलेंगे

नोएडा (वार्ता)। एमबीडी समूह और रेडिसन समूह ने अपनी साझेदारी को और आगे बढ़ाते हुए सोमवार को नये ब्रांड बनाने के साथ देश में अगले 10 साल में 50 नये होटल खोलने की घोषणा की। एमबीडी समूह की संयुक्त प्रबंध निदेशक सोनिका मल्होत्रा कंधारी ने बताया कि नये ब्रांड रेडिसन कलेक्शन एमबीडी और रेडिसन रेड एमबीडी के नाम से जाने जाएंगे। रेडिसन कलेक्शन एमबीडी लग्जरी होटल होंगे जबकि रेडिसन रेड एमबीडी लाइफस्टाइल श्रेणी के होटल होंगे। उन्होंने बताया कि अधिकांश होटल एसेट-लाइट मॉडल के माध्यम से विकसित होंगे। एमबीडी की संपत्ति हिस्सेदारी लगभग 25 प्रतिशत रहेगी। लाइफस्टाइल सेगमेंट में अधिक आक्रामक विस्तार का लक्ष्य है। प्रस्तावित पोर्टफोलियो में लगभग 80 प्रतिशत प्रबंधित और फ्रेंचाइजी होटल तथा 20 प्रतिशत स्वामित्व वाले होटल शामिल होंगे। बेंगलुरु, उदयपुर और रणथंभौर में जमीन खरीदने का काम हो चुका है।

चावल, चीनी, दाल में मजबूती

नई दिल्ली (वार्ता)। घरेलू थोक जिंस बाजारों में सोमवार को चावल के औसत भाव बढ़ गये। वहीं, गेहूं के दाम में गिरावट देखी गयी। दालों और चीनी की कीमत बढ़ गयी जबकि खाद्य तेलों में उतार-चढ़ाव का रुख रहा। औसत दर्जे के चावल की औसत कीमत 81 रुपये बढ़कर 3,846 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गयी। गेहूं का भाव 32 रुपये घटकर 2,847 रुपये प्रति क्विंटल रह गया। आटा भी 38 रुपये सस्ता हुआ। दाल-दलहनों में तेजी रही। चना दाल औसतन 141 रुपये प्रति क्विंटल महंगी हुई। तुअर दाल की कीमत 120 रुपये और मसूर

दाल की 116 रुपये बढ़ गयी। मूंग दाल 59 रुपये प्रति क्विंटल मजबूत हुई। उड़द दाल की कीमत लगभग स्थिर रही। विदेशों में मलेशिया के बुरसा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में पाम ऑयल का मई वायदा आठ रिंगिट टूटकर 4,084 रिंगिट प्रति क्विंटल पर रहा। मई का अमेरिकी सोया तेल वायदा भी 0.40 प्रतिशत की गिरावट में 59.54 सेंट प्रति पौंड बोला गया। स्थानीय बाजारों में पाम ऑयल की औसत कीमत 148 रुपये और सोया तेल की 115 रुपये प्रति क्विंटल उतर गयी। सूरजमुखी तेल में 25 रुपये और सरसों तेल में 17 रुपये की गिरावट रही। मूंगफली तेल 38 रुपये और वनस्पति 29 रुपये प्रति क्विंटल महंगा हुआ। मीठे के बाजार में आज गुड़ के औसत भाव 82 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गये। चीनी भी 15 रुपये महंगी हुई।

सप्ताह के पहले ही दिन भागा शेयर बाजार

मुंबई (वार्ता)

अमेरिका में आयात शुल्क में कमी से सोमवार को घरेलू शेयर बाजारों में लगातार दूसरे दिन तेजी रही। बीएसई का सेंसेक्स 479.95 अंक (0.58 अंक) की बढ़त में 83,294.66 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक 141.75 अंक यानी 0.55 प्रतिशत ऊपर 25,713 अंक पर बंद हुआ। सार्वजनिक बैंकों, वित्तीय कंपनियों और एफएमसीजी सेक्टर की कंपनियों में ज्यादा लिवाली रही। आईटी, रसायन, धातु, टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद और रियलटी समूहों के सूचकांक टूट गये। मझौली कंपनियों में बिकावाली और छोटी कंपनियों में लिवाली ज्यादा रही। निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.83 प्रतिशत फिसल गया जबकि स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.29

प्रतिशत ऊपर बंद हुआ। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पिछले साल विभिन्न देशों पर लगाये गये आयात शुल्क की ऊंची दरों को अवैध बताते हुए उसे रद्द कर दिया था। इसके बाद श्री ट्रंप ने 20 फरवरी को 150 दिन के लिए सभी देशों पर 10 प्रतिशत का समान आयात शुल्क लगाने की घोषणा की थी जिसके बारे में व्हाइट हाउस ने आदेश भी जारी कर दिया है जिसमें कहा गया है कि नयी दर 24 फरवरी से लागू होनी है। हालांकि राष्ट्रपति ने 21 फरवरी को आयात शुल्क 15 प्रतिशत करने की घोषणा की थी, लेकिन इसके बारे में अबतक कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। अमेरिका में आयात शुल्क में कमी की घोषणा से भारतीय शेयर बाजारों में भी निवेशकों का विश्वास मजबूत हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में अडानी पोर्ट्स का शेयर लगभग तीन प्रतिशत और कोटक महिंद्रा बैंक का 2.25 प्रतिशत ऊपर बंद हुआ। अल्ट्राटेक सीमेंट, पावरग्रिड, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयरों में एक से दो प्रतिशत के बीच बढ़त रही। भारती एयरटेल, भारतीय स्टेट बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाइटन, एलएंडटी, एनटीपीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सनफार्मा और मारुति सुजुकी के शेयर भी हरे निशान में रहे। इंफोसिस में दो प्रतिशत के करीब गिरावट रही। टेक महिंद्रा का शेयर एक प्रतिशत से ज्यादा लुढ़क गया। ट्रेंट, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, बजाज फिनसर्व, आईटीसी, टीसीएस, बीईएल और इटरनल के शेयर भी लाल निशान में बंद हुए।

केंद्रीय बैंकों की खरीद के चलते बढ़ी सोने की कीमतः सीतारमण

नई दिल्ली (वार्ता)

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सोने की कीमतों में इस समय चल रही तेजी मुख्य रूप से दुनिया के केंद्रीय बैंकों की ओर से सोने-चांदी की खरीद बढ़ाये जाने के कारण है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि देश में सोने के निवेश और उपभोग मांग को देख कर ऐसा नहीं लगता कि स्थिति चिंता के स्तर पर है फिर भी भारतीय रिजर्व बैंक की बाजार पर निगाह बनी हुई है। श्रीमती सीतारमण आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की बजट पश्चात बैठक में भाग लेने के बाद संवाददाताओं को संबोधित कर रही थी। वित्त मंत्री ने कहा, आजकल अधिकांश देश, विशेष रूप से उनके केंद्रीय बैंक, सोना और चांदी खरीदकर भंडारित कर रहे हैं। जब आप भारतीय उपभोक्ता बाजार की बात करते हैं, तो यह एक प्रवृत्ति के रूप में दिखता है। हर केंद्रीय बैंक के

पास कुछ न कुछ भंडार होता है, लेकिन हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि कई अन्य देशों के केंद्रीय बैंक भी सोना खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा, कीमतों में जो उछाल आया है, वह मुख्य रूप से केंद्रीय बैंकों द्वारा सोना खरीदने और उसे संग्रहित करने के कारण है। श्रीमती सीतारमण ने घरेलू उपभोग के बारे में कहा कि यह हर मौसम और हर त्योहार के साथ जुड़ी एक सामान्य स्थिति रहती है। लेकिन सोनेऔर चांदी की वैश्विक कीमतों में जो असामान्य और सामान्य उतार-चढ़ाव से कहीं अधिक वृद्धि हुई है, उसका प्रभाव हर घरेलू खरीद पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा, कीमती धातुओं के मामले में हमारी निर्भरता लगभग पूरी तरह बाहरी स्रोतों पर है। हमारे पास सोने की खोज और उसके खनन का पर्याप्त घरेलू स्रोत नहीं है। इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन वे हमारी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में सोना हमेशा से परिवारों के लिए एक पसंदीदा निवेश रहा है। घरेलू उपभोग की उच्च मांग में त्योहारों के मौसम के दौरान मौसमी उछाल भी देखने को मिलता है। उन्होंने कहा, हम इस स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह किसी चिंताजनक स्तर तक पहुंचा है। मेरा मानना है कि यह एक निश्चित सीमा से आगे नहीं गया है। हालांकि, भारतीय रिज़र्व बैंक भी इस पर निगरानी रखे हुए है।

किसानों को लाभान्वित करने खेत से बाजार तक तैयार कर रहे श्रृंखलाः डॉ. मोहन यादव

मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कृषि वैज्ञानिकों को दिया संदेश

भोपाल (स्वतंत्र मत)

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसान हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ हैं। इनके अथक परिश्रम से ही हमारे बाजार गुलजार है। हम वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। यह वर्ष प्रदेश के इतिहास में किसानों के हित और समग्र कल्याण के मामले में मील का पत्थर साबित होगा।उन्होंने कहा कि यह वर्ष खेत से लेकर कारखाने तक और बाग से लेकर बाजार तक की पूरी मूल्य संवर्धन श्रृंखला को एक सूत्र में जोड़ेगा। इस वर्ष हम कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और इनमें वैल्यू एडिशन के लिए अधिकाधिक रोजगार आधारित उद्योगों के विकास, उन्नत किस्म के बीजोत्पादन, पशुपालन, दुग्धोत्पादन, मत्स्योत्पादन में वृद्धि सहित हर वो कदम उठाएंगे, जिनसे खेती और अन्नदाताओं का विकास हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास से कृषि विश्वविद्यालय परिसर, ग्वालियर में हो रहे कृषि मंथन एवं

कृषि प्रौद्योगिकी मेला 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना संबंधी कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में तेज़ी से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। हमारी सरकार प्रदेश में औषधीय और मसाला फसलों का उत्पादन बढ़ाने के सभी प्रयास कर रही है। हम जल्द ही कृषि उत्पादन निर्यात नीति लाने वाले हैं। हम कृषि में शोध कार्य भी बढ़ायेंगे। उन्होंने कहा कि हम खेती-किसानी और फल-फूलों की खेती को लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए कोई कसर नहीं रखेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस कृषि मंथन से जो अमृत निकलेगा, वह हमें किसानो के कल्याण के लिये प्रभावी और कारगर कदम उठाने में सहायक होगा। कृषि मंथन राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) नई दिल्ली और कृषि विभाग, म.प्र. शासन के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है।

विकास की राह प्रशस्त करेंगे- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश की थीम पर हो रहा कृषि मंथन निश्चित ही किसानों को खेती में जरूरी सुधार और बदलाव लाने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आधुनिक कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्रों में मूल्य-श्रृंखला विकास, प्रोसेसिंग, तकनीक अपनाने और ग्रामीण युवाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देकर व्यापक रोजगार सृजन करने पर फोकस कर रही है। तकनीकी नवाचार, विविधीकरण और नीतिगत समर्थन से इन क्षेत्रों में न केवल उत्पादकता बढ़ाई जा सकेगी, बल्कि विपणन एवं प्रसंस्करण के क्षेत्र में बाजार अनुरूप लाभकारी व्यवस्था कृषकों के लिए निर्मित होगी। हम कृषि के अलावा उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं सहकारिता क्षेत्र में भी नई सोच से आगे बढ़ रहे है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज कृषि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते जोखिमों का सामना कर रही है। इस मंथन में देश के विभिन्न कृषि संस्थानों के वरिष्ठ वैज्ञानिक विचार मंथन कर नई तकनीकों के विकास की राह प्रशस्त करेंगे।

इनकी रही उपस्थिति- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सचिव कृषि एवं किसान कल्याण विभाग निशांत वरवड़े, सचिव परिवहन एवं आयुक्त जनसम्पर्क मनीष सिंह ने भोपाल से सहभागिता की। यूनिवर्सिटी परिसर में हो रहे इस कृषि मंथन में कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के कुलगुरू प्रो. (डॉ.) अरविंद कुमार शुक्ला, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अयोध्या के कुलपति डा. ब्रजेन्द्र सिंह, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, धारवाड़, कर्नाटक के कुलपति डॉ. पी.एल पाटिल, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, मोदीपुरम, मेरठ के निदेशक डॉ. सुनील कुमार, देश के विभिन्न कृषि संस्थानों से आये वैज्ञानिक, आईसीएआर के पदाधिकारी सहित कृषि अधिकारी भी उपस्थित थे।

बंदियों की सोच सकारात्मक बनाने के प्रयास हों: राज्यपाल

राज्यपाल ने जेल गृह विभाग के अधिकारियों से की चर्चा

भोपाल (स्वतंत्र मत)

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि बंदी पुनर्वास प्रयासों को समग्रता और बहुआयामी स्वरूप में किया जाना चाहिए। कार्य का दृष्टिकोण मानवतावादी हो। भाव संवेदनशील और विचारशील होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पुनर्वास प्रयासों में सकारात्मक सोच के निर्माण पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री का 'मन की बात' कार्यक्रम बंदियों की सोच को रचनात्मक दिशा देने। भविष्य के प्रति विश्वास और आत्मबल को मजबूत करने में बहुत सहयोगी होगा। राज्यपाल श्री पटेल सोमवार को लोकभवन में गृह एवं जेल विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव गृह शिव शेखर शुक्ला, राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, विशेष महानिदेशक जेल अखितो सेमा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

राज्यपाल श्री पटेल ने अधिकारियों से कहा कि बंदी उत्पादक गतिविधियों के द्वारा बंदियों के परिवारों के जीवन निर्वाह में आर्थिक सहयोग के उद्देश्य से नियोजन गतिविधियों का संयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि जेलों में बंद मामूली अपराधों के विचाराधीन कैदियों को केवल दंड देना ही नहीं, बल्कि उन्हें सकारात्मक सुधार के जरिए समाज की मुख्य धारा में वापस भेजना पुनर्वास प्रयासों का मूलाधार होना चाहिए। भाव उनको अपराधी की पहचान से मुक्त होकर बेहतर नागरिक के रूप में स्थापित होने में मदद का होना चाहिए। समाज के नव-निर्माण में वे अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकें। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि 'मन की बात' कार्यक्रम को सुनकर जेल की दीवारों के पीछे एकाकी जीवन जी रहे बंदियों को देश की प्रगति और प्रेरक कहानियों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। उनके जीवन में आशावाद और नव-निर्माण का संचार होगा। बंदियों के भीतर छिपी नकारात्मकता में कमी आएगी। सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्म-सुधार की भावना जागृत होगी। उन्होंने जेलों में लंबित दया याचिकाओं, महिला बंदियों के बच्चों के उचित लालन-पालन की व्यवस्थाओं, महिला बंदियों के पुनर्वास, दिव्यांग एवं बुजुर्ग बंदियों के लिए आवश्यक कृत्रिम उपकरणों की उपलब्धता और श्रम शक्ति के उत्पादक गतिविधियों में नियोजन के संबंध चर्चा की।

1 मार्च से केवल ऑनलाइन लिए जायेंगे शस्त्र लाइसेंस हेतु आवेदन

दमोह (स्वतंत्र मत)

कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया कि जिले में 1 मार्च से शस्त्र लाइसेंस संबंधी नई व्यवस्था लागू की जा रही है। इस नई प्रणाली के तहत अब शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को नया शस्त्रए बंदूक अथवा अन्य हथियार लेना है और इसके लिए आवेदन करना है तो उसे भारत सरकार द्वारा निर्धारित आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। संबंधित पोर्टल की लिंक जिला प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा की जा रही है जिससे आवेदकों को सुविधा मिल सके। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने के पश्चात आवेदक को एक यूनिक फाइल नंबर प्राप्त होगा। उसी फाइल नंबर के साथ आवेदन का प्रिंटआउट निकालकर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार मैनुअली जमा किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी आवेदक द्वारा पहले ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया है तो उसका ऑफलाइन फॉर्म किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। 1 मार्च तथा उसके बाद प्राप्त होने वाले सभी आवेदन केवल ऑनलाइन पद्धति से ही मान्य होंगे।

गैसाबाद-सिमरिया पुल विवाद पहुंचा उच्च न्यायालय

6 माह से यात्री परेशान नया पुल तैयार अप्रोच रोड अधूरी

हटा (स्वतंत्र मत)

हटा से पन्ना जिले को जोड़ने वाली व्यारमा नदी पर गैसाबाद-सिमरिया के बीच स्थित पुल का मामला अब गंभीर रूप लेता हुआ उच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। करीब छह माह से पुराने पुल पर आवागमन बंद होने के कारण क्षेत्रीय यात्रियों, ग्रामीणों और बस संचालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद नया पुल तैयार होने के बाद भी अप्रोच रोड का निर्माण न होने से जिम्मेदार विभागों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तकनीकी रिपोर्ट में पुराने पुल को जर्जर और असुरक्षित बताए जाने के बाद प्रशासन ने एहतियातन आवागमन रोक दिया था। इसके विकल्प के रूप में मड़ियादो, वर्धा, नकटी, रनेह और मोहिंद्रा होकर

वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए जो मुख्य मार्ग की तुलना में 30 से 40 किलोमीटर लंबा पड़ता है। अतिरिक्त दूरी के कारण यात्रियों का समय और किराया दोनों बढ़ गया हैए वहीं आपातकालीन परिस्थितियों में भी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। भारी वाहनों के लिए पूर्ण प्रतिबंध लागू है जबकि दोपहिया और हल्के चारपहिया वाहनों के लिए सीमित स्थान छोड़ा गया है। स्थिति यह है कि कई बस संचालकों को पुल के दोनों ओर अलग-अलग बसें खड़ी कर यात्रियों की अदला.बदली करनी पड़ रही हैए जिससे अव्यवस्था और जोखिम की स्थिति बनी हुई है। विवाद का सबसे अहम पहलू यह है कि पुराने पुल के समानांतर करोड़ों रुपये की लागत से नया पुल बनकर तैयार है लेकिन दोनों ओर अप्रोच रोड का निर्माण शुरू नहीं हो सका। जानकारी के अनुसार पुल निर्माण के दौरान भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाईए जिसके कारण सीमांत किसानों की जमीन संबंधी अड़चनें सामने आईं और अप्रोच रोड का कार्य अटक गया। दूसरी ओर अधिकारियों ने पुराने पुल को खतरनाक बताते हुए आवागमन बंद करा दियाए परंतु नए पुल को चालू करने के लिए आवश्यक समन्वय और वैकल्पिक व्यवस्था समय पर नहीं की जा सकी। इससे क्षेत्र में लोगों की नाराजगी लगातार बढ़ रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्रीय सांसद द्वारा भी अधिकारियों के साथ चर्चा कर पुल को शीघ्र चालू कराने की समयसीमा बताई गई थी लेकिन जमीनी स्तर पर अप्रोच निर्माण कार्य प्रारंभ न होने से वह आश्वासन भी अधूरा नजर आ रहा है।

पटवारी ने शादीशुदा होने की बात छिपाकर मंदिर में किया विवाह

पीड़िता ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार

हटा (स्वतंत्र मत)

थाना क्षेत्र की एक युवती ने अपने पति पर शादी के बाद बंधक बनाकर शोषण करने, मारपीट करने और दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने आरोपी पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए हटा थाना पुलिस को आवेदन सौंपा है। पीड़िता के मुताबिक सागर निवासी पटवारी देशराज ने अपनी पूर्व शादी की जानकारी छिपाकर 4 जुलाई 2025 को मंदिर में उससे विवाह किया। शादी के बाद आरोपी पति द्वारा उसे लगभग छह माह तक घर में बंधक बनाकर रखा गया तथा परिजनों से संपर्क करने से रोका गया। युवती ने बताया कि किसी तरह उसने अपने माता-पिता को सूचना दी। लेकिन जब वे उसे लेने पहुंचे तो आरोपी द्वारा उनके साथ मारपीट कर भगा दिया गया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी पति ने पांच लाख रुपये नकद और एक चार पहिया वाहन दहेज में देने का दबाव बनाया। पीड़िता ने यह भी बताया कि विवाह के समय मंदिर में एक लाख रुपये पहले ही दिए गए थे। बाद में उसे जानकारी मिली कि आरोपी पहले से शादीशुदा है और यह तथ्य छिपाकर दूसरी शादी की गई। मामले में युवती ने पुलिस से धोखाधड़ी, दहेज प्रताड़ना, मारपीट और बंधक बनाकर रखने के आरोपों में कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में हटा एसडीओपी प्रिया सिंधी ने बताया कि पीड़िता का आवेदन प्राप्त हुआ है। मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

एनएसएस के सात दिवसीय शिविर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन

दमोह (स्वतंत्र मत)

माधवराव सप्रे शासकीय महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के तीसरे दिन गोद ग्राम टीला, पथरिया में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रात:काल योग सत्र से हुई, जिसका संचालन ज्योति पटेल द्वारा किया गया। योगाभ्यास के माध्यम से स्वयंसेवकों को शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य एवं अष्टांग योग और प्राणायाम के महत्व की जानकारी दी गई। इसके पश्चात छात्र एवं छात्रा यूनिट के स्वयंसेवकों द्वारा ग्राम एवं परिसर की साफ सफाई की गई। छात्रा यूनिट की कार्यक्रम अधिकारी डॉ.

संध्या शर्मा के मार्गदर्शन में सभी गतिविधियां संपन्न हुईं। इसके पश्चात् बौद्धिक चर्चा सत्र का आयोजन किया गया। बौद्धिक सत्र में विशेषज्ञ डॉ. देवेश सर ने स्वरोजगार विषय पर, डॉ. सुधीर सर ने विद्यार्थियों के जीवन की समस्याओं पर तथा श्री राहुल कुर्मी सर ने संचार कौशल पर अपने विचार व्यक्त किए। संचालन श्रीमती प्रियंका राजपूत मैम, श्रीमती रविता सिंह, डॉ सरिका अग्रवाल मैम का सहयोग रहा। शिविर के तीसरे दिन आयोजित इन कार्यक्रमों से स्वयंसेवकों में जागरूकता, अनुशासन एवं व्यक्तित्व विकास की भावना का विकास हुआ।

पाइपलाइन कार्य पूर्ण कराने में प्रशासन का सहयोग करें: कलेक्टर

सीतानगर, पंचमनगर, साजली, सतधरू परियोजनाओं के अंतर्गत कार्य प्रगति पर

दमोह (स्वतंत्र मत)

कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने जिले के किसान भाइयों एवं बहनों से विशेष अपील करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री, पशुपालन एवं डेयरी विभाग राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार लखन पटेल, संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेन्द्र सिंह लोधी तथा दमोह विधायक जयंत मलैयाए हटा विधायक उमा देवी खटीक एवं जनप्रतिनिधियों का एकमात्र लक्ष्य है कि किसान के खेत के अंतिम छोर तक सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित की जाए। इसी उद्देश्य से जिले में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर श्री कोचर ने बताया कि विशेष रूप से सीतानगर, पंचमनगर, साजली, सतधरू परियोजनाओं के अंतर्गत कार्य प्रगति पर है, इन परियोजनाओं के माध्यम से जिले के अनेक गांवों में भूमिगत पाइपलाइन बिछाकर सिंचाई सुविधा का विस्तार किया जा रहा हैए जिससे भविष्य में किसानों को पर्याप्त जल उपलब्ध हो सके। उन्होने बताया कि पाइपलाइन बिछाने के दौरान एक प्रमुख समस्या सामने आती है। वर्तमान समय में रबी फसलों की कटाई का समय निकट है तथा कई किसान मूंग की बुवाई की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि चिन्हित स्थानों पर बुवाई कर दी जाती है, जहां से पाइपलाइन प्रस्तावित हैए तो पाइपलाइन बिछाने का कार्य बाधित हो जाता है और समय.सीमा प्रभावित होती है। कलेक्टर ने सभी किसान संगठनों एवं कृषकों से अनुरोध किया है कि जिन खेतों से पाइपलाइन गुजरनी है, वहां चिन्हित स्थानों पर कार्य में सहयोग करें तथा पाइपलाइन बिछाने दें। उन्होंने कहा कि यह कार्य किसानों के ही हित में है। यदि निर्धारित समय में पाइपलाइन नहीं बिछ पाई तो जिले में अंतिम खेत तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्रभावित हो सकता है। कलेक्टर श्री कोचर ने बताया कि संबंधित गांवों की सूची, कार्य की तिथियां एवं स्थानों का विवरण सोशल मीडिया के माध्यम से साझा कर दिया गया है ताकि किसान पूर्व सूचना के आधार पर सहयोग कर सकें। उन्होने कहा कि यह पहल किसानों के उज्ज्वल भविष्य और बेहतर सिंचाई व्यवस्था के लिए है। उन्होंने सभी कृषकों से अपील की कि वर्तमान सीज़न में पाइपलाइन कार्य पूर्ण कराने में प्रशासन का सहयोग करेंए ताकि आगामी सीज़नों में अंतिम छोर तक सिंचाई सुविधा सुनिश्चित की जा सके।

सात साल की खुदाई... फिर भी प्यासा हटा

अधूरी पाइपलाइन और जवाबदेही का अभाव, जल संकट से जूझते 15 वार्ड

हटा (स्वतंत्र मत)

नगर की पेयजल व्यवस्था को आधुनिक और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया उदय प्रोजेक्ट अब सवालों के घेरे में है। करोड़ों रुपये की लागत से संचालित इस योजना को सात वर्ष बीत चुके हैं लेकिन नगर के 15 वार्डों तक पाइपलाइन का जाल अब भी अधूरा है। हालात यह हैं कि नगर की सड़कों

और गलियों में लगातार खुदाई हो रही है जबकि बड़ी आबादी आज भी नियमित पेयजल आपूर्ति से वंचित है। जल प्रदाय व्यवस्था सुधारने की उम्मीद में शुरू हुआ प्रोजेक्ट अब नागरिकों के लिए असुविधा, धूल और अव्यवस्था का कारण बनता जा रहा है। लोगों का कहना है कि श्पानी नहींए सिर्फ खुदाई मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक परियोजना की मॉनिटरिंग स्थानीय स्तर के बजाय बाहरी कार्यालय से की जा रही थी जिससे रोजाना निरीक्षण नहीं हो पाया। पाइपलाइन बिछाने, जोड़ने और परीक्षण में तकनीकी खामियां सामने आईं। कई वार्डों में पाइपलाइन अधूरी है जबकि कुछ स्थानों पर पाइपलाइन बिछने का रिकॉर्ड है लेकिन जमीन पर उसका अस्तित्व ही नहीं मिल रहा। नगर में यह धारणा बन चुकी है कि फाइलों में कार्य पूर्ण दिखाया गया, पर जमीनी हकीकत अलग है।

बंद हुई पुरानी सप्लाई, बढ़ा संकट- जल गुणवत्ता को लेकर हुई प्रशासनिक समीक्षा में पुरानी पानी टंकी और फिल्टर प्लांट की स्थिति खराब पाई गई। इसके बाद पुरानी लाइन से जल आपूर्ति बंद कर दी गई और पूरा भरोसा उदय प्रोजेक्ट पर कर लिया गया। लेकिन अधूरी पाइपलाइन के कारण कई मोहल्लों में पानी की आपूर्ति ठप हो गई और जल संकट गहरा गया।

जहां खुदाई, वहां पाइपलाइन गायब- हाल ही में सोसायटी रोड से राय चौराहा तक हुई खुदाई के दौरान कई स्थानों पर पाइपलाइन का कोई संकेत नहीं मिला। कहीं लाइन चोक पाई गई कहीं लीकेज मिला और कई जगह पाइपलाइन का रिकॉर्ड ही नहीं मिला। इससे तकनीकी मैपिंग और सुपरविजन की गंभीर कमी उजागर हुई है।

पुरानी लाइन बनी जीवनरेखा- जलसंकट बढ़ने पर बड़ा बाजार और तीन बत्ती क्षेत्र में पुरानी पाइपलाइन से अस्थायी जोड़कर जल आपूर्ति बहाल करनी पड़ी। यह स्थिति दर्शाती है कि जिसे अप्रचलित बताकर बंद किया गया। वहीं व्यवस्था अब राहत दे रही है।

जिम्मेदारों की चुप्पी, बढ़ता जनाक्रोश- परियोजना की प्रगति और कमियों को लेकर जिम्मेदार अधिकारी स्पष्ट जानकारी देने से बचते नजर आ रहे हैं। नगर पालिका स्तर पर भी पाइपलाइन की वास्तविक स्थिति और मैपिंग को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। लगातार खुदाईए खराब सड़कों और पानी की किल्लत ने लोगों में नाराजगी बढ़ा दी है। उदय प्रोजेक्ट की धीमी प्रगति का असर केवल जल आपूर्ति तक सीमित नहीं है।

सड़कों की खुदाई से यातायात प्रभावित- धूल और गड्ढों से दुर्घटना का खतरा व्यापार और दैनिक गतिविधियों में बाधा स्कूल जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों को परेशानी यानी यह समस्या अब शहरी सुविधा से बढ़कर जनजीवन की समस्या बन गई है। जनता के सीधे सवाल है कि सात वर्षों में परियोजना पूर्ण क्यों नहीं हो सकी। जमीनी सत्यापन के बिना पुरानी सप्लाई बंद करने का निर्णय क्यों लिया गया।

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल
भेड़ाघाट रोड, धनवंतरी नगर, जबलपुर म.प्र. पिन-482003

भवन नामांतरण हेतु सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसरंचना विकास मण्डल द्वारा निर्मित पुरवा कालोनी जबलपुर स्थित भवन क्रमांक एलआईजी-1017 का आवंटन श्री देवीदास सरबटे पिता स्व. श्री विशस्वर सरबटे को आवंटित है । श्री देवीदास सरबटे का निधन दिनांक 28/07/2011 की होने के पश्चात उनके नामिनी श्रीमति संगीता सोनी पति स्व. श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी एवं श्रीमती सत्यभामा सोनी पति श्री इन्द्रलाल सोनी द्वारा यह भवन उनके पक्ष में नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है । यदि किसी व्यक्ति को नामातंरण वाबत् आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने से 15 दिवस के अंदर लिखित में वैद्य आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं । निर्धारित अवधि के पश्चात नामांतरण की कार्यवाही कर दी जावेगी ।

संपदा अधिकारी म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, जबलपुर

ग्राम रोजगार सहायक के ट्रांसफर और टर्मिनेशन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

मप्र सरकार से चार सप्ताह में मांगा जवाब

जबलपुर (स्वतंत्र मत)

मप्र हाई कोर्ट ने सोमवार को ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्शिका 2025 पर भी रोक लगा दी है। मप्र हाईकोर्ट ने सरकार आदेश दिया है कि आगामी आदेश तक किसी भी रोजगार सहायक का ट्रांसफर और टर्मिनेशन नहीं होगा। मप्र हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। इस मामले में अधिवक्ता गोपेश तिवारी ने बताया कि हाईकोर्ट ने सरकार की मार्गदर्शिका के क्रियान्वयन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यह आदेश मनरेगा कमिश्नर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वल्लभ भवन और हर जिले के कलेक्टर को भेजा जा रहा है, ताकि कहीं भी रोजगार सहायक का ट्रांसफर ना हो सके। अधिवक्ता के मुताबिक राज्य सरकार ने एक नई मार्गदर्शिका जारी कर रोजगार सहायकों के टर्मिनेशन और ट्रांसफर नीति निर्धारित की थी। हालांकि, इस नीति का क्रियान्वयन अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। इसी बीच रोजगार सहायकों ने हाईकोर्ट में स्थानांतरण नीति और सेवा समाप्ति से संबंधित शर्तों को चुनौती दी थी। मप्र हाई कोर्ट ने याचिका में सुनवाई की और मार्गदर्शिका 2025 पर रोक लगा दी।

रोजगार गारंटी योजना लागू, फिर भी सहायकों की भर्ती

दरअसल देश में रोजगार गारंटी योजना लागू होने के बाद ग्रामीण स्तर पर कार्यों की मॉनिटरिंग और मजदूरों का रिकॉर्ड रखने के लिए रोजगार सहायकों की भर्ती की गई। मध्य प्रदेश में उस वक्त शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी। राज्य में लगभग 25 हजार पदों पर भर्ती की गई। प्रारंभिक चरण में रोजगार सहायकों को प्रतिमाह 9 हजार रुपए मानदेय निर्धारित किया गया था। बाद में सरकार ने यह महसूस किया कि निर्धारित मानदेय कार्य की तुलना में कम है। इसके बाद दो अन्य मदों के माध्यम से अतिरिक्त 9 हजार रुपए जोड़ दिए गए।

पैतृक निवास में की गई नियुक्ति

इस तरह रोजगार सहायकों का मासिक मानदेय बढ़ाकर 18 हजार रुपए प्रतिमाह कर दिया गया। अधिकांश रोजगार सहायकों की नियुक्ति उनके पैतृक या निवास ग्राम में ही की गई थी। भर्ती प्रक्रिया में कंप्यूटर संबंधी योग्यता को प्राथमिकता दी गई थी। चयन के लिए 12वीं कक्षा के प्राप्तांक और पीजीडीसीए जैसी कंप्यूटर डिग्री को आधार बनाया गया था। वर्तमान में भी अधिकांश रोजगार सहायक उसी ग्राम पंचायत में कार्यरत हैं, जहां उनकी नियुक्ति हुई थी। ग्रामीण स्तर पर कई ग्राम सचिवों को कंप्यूटर संचालन का अनुभव सीमित होने के कारण पंचायतों में डिजिटल कार्यों और ऑनलाइन प्रविष्टियों की जिम्मेदारी रोजगार सहायक ही निभा रहे हैं ।

एमपी ट्रांसको में निरीक्षण करने पहुंची जापान से आई जायका टीम

ट्रांसमिशन लाइन, सबस्टेशन का बारीकी से किया अवलोकन

जबलपुर (स्वतंत्र मत)

जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जायका) द्वारा मध्यप्रदेश के ट्रांसमिशन नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण हेतु मप्र पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) में संचालित जायका-2 वित्त पोषित विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत किए गए कार्यों का विस्तृत निरीक्षण किया गया। जायका जापान की इवैल्यूएटर सुश्री हिसाए ताकाहाशी एवं जायका के भारतीय प्रतिनिधि कुनाल गुप्ता ने निर्माण कार्यों, उनकी गुणवत्ता, उपयोगिता तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप क्रियान्वयन की बारीकी से जांच-पड़ताल की। निरीक्षण के दौरान टीम ने सर्वप्रथम 132 केवी सबस्टेशन ढीमरखेड़ा तथा इसके लिए निर्मित 132 केवी पनागर-ढीमरखेड़ा ट्रांसमिशन लाइन का अवलोकन किया। इवैल्यूएटर सुश्री ताकाहाशी ने लोन स्वीकृति के समय प्रस्तुत प्रारंभिक योजना, परियोजना के क्रियान्वयन, स्थापित उपकरणों की गुणवत्ता, लागत एवं रखरखाव से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण उपरांत उन्होंने सबस्टेशन एवं ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पाए जाने पर संतोष व्यक्त किया।

स्थानीय नागरिकों से की चर्चा- जायका द्वारा वित्त पोषित फंड से निर्मित सबस्टेशन की उपयोगिता के संबंध में अधिकारियों से जानकारी लेने के साथ-साथ जायका टीम ने स्थानीय महिलाओं को बुलाकर उनका प्रत्यक्ष फीडबैक भी लिया। महिलाओं ने बताया कि सबस्टेशन के निर्माण से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अब उन्हें पर्याप्त एवं निर्बाध बिजली मिल रही है, जिससे सिंचाई के लिए भी पर्याप्त विद्युत उपलब्ध हो रही है। इससे उनके आर्थिक एवं सामाजिक स्तर में सकारात्मक बदलाव आया है।

लुहारी कांटी बनी गिल्ली डंडा प्रतियोगिता की विजेता

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। जिला पंचायत जबलपुर के तत्वाधान में गिल्ली डंडा का खेलों का आयोजन पाटन स्टेडियम में जनपद पंचायत पाटन के द्वारा क्लस्टर स्तरीय गिल्ली डंडा खेले का आयोजन किया गया। इस आयोजन में क्लस्टर सकरा, बोरिया, सरोंद, लुहारी कांटी, कटरा बेलखेडा, उजरोड, सहसन धनेटा और कैमोरी के प्रतिभागियों ने भाग लिया। फाइनल मैच में लुहारी कांटी विजेता घोषित की गई। कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष ज्योति ठाकुर, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता एवं सम्मानित सदस्य ठाकुर उदयभान विधायक प्रतिनिधि आनंद मोहन पल्हा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी अखिल सहाय श्रीवास्तव उपस्थित रहे।

गाय के अंतिम संस्कार के रूपयों पर भ्रष्टाचार के आरोप

बजरंग दल के सदस्यों ने गाय का शव रखकर ननि के सामने किया प्रदर्शन

जबलपुर (स्वतंत्र मत)

नगर निगम पर मृत गायों के अंतिम संस्कार में लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सोमवार को बजरंग दल के सदस्यों ने मृत गाए के शव को नगर निगम के सामने रखकर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि निगम कर्मचारी अंतिम संस्कार के लिए तीन हजार रुपए लेने के बावजूद गायों का विधिवत अंतिम संस्कार करने के बजाय उनके शव नालों में फेंक रहे है। ताकि मिलने वाली राशि को वे खुद आपस में बांट सकें। प्रदर्शन के दौरान पहुंचे नगर निगम डिप्टी कमिश्नर संभव अयाची का कहना है कि नगर निगम की तरफ से कठुंदा में गाय और अन्य पशुओं के लिए अंतिम संस्कार की व्यवस्था करोंदा स्थित केंद्र में की गई है, यदि इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो इसकी जांच की जाएगी और संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाएगी।

आग का गोला बनी चलती हुई कार

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर गोसलपुर टोल नाके के पास चलती कार में अचानक आग लग गई। टोल नाका पार करते ही कार में धुआं उठने लगा और देखते ही देखते आग भड़क गई। दरअसल सोमवार दोपहर जबलपुर से सिहोरा की ओर जा रही इस कार में 2 लोग सवार थे। आग लगते ही चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए वाहन को सड़क किनारे रोका और साथी के साथ तुरंत बाहर निकल गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम और गोसलपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार काफी हद तक जल चुकी थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक, वाहन किसका है इसकी जानकारी फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। राहत की बात यह रही कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

पुलिस की गिरफ्त में शातिर नकबजन

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। मझौली थाने में विष्णु शरण अग्रवाल उम्र 37 वर्ष निवासी सिहोरा रोड पेट्रोल पंप के बाजू में काकरदेही मझौली ने रिपोर्ट दर्ज कर बताया था कि वह मझौली में पान की दुकान, एवं मोबाइल की दुकान चलाता है। 5 फरवरी को अपनी दोनो दुकान के करीब 18 हजार रूपये लेकर अपने घर वापस गया था। जिसे उसने घर के कमरे में काउंटर की ड्राज में रख दिये थे। काउंटर में पहले से 12 हजार रूपये रखे थे। इसी बीच सब खाना खाकर सो गए। सुबह उसके मंझले भाई राजेन्द्र कुमार अग्रवाल ने उठाया और बताये की घर की गैलरी के दरवाजे का ताला टूटा है। जाकर देखे तो 2 मोबाइल गायब थे। वहीं ड्राज में रखे 30 हजार रूपये भी गायब थे। पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए 23 वर्षीय आरोपी अनुराग दुबे 23 वर्ष निवासी मझोली को गिरफ्तार किया। जिसने पूछताछ में काकरदेही स्थित घर से मोबाईल एवं नगदी रूपये चुराना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सामान बरामद करते हुए आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की।

2 मार्च से थमेंगे बसों के पहिए

सुगम लोक परिवहन सेवा योजना के विरोध में होगा प्रदर्शन

जबलपुर (स्वतंत्र मत)

प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम लोक परिवहन सेवा योजना के लागू होने से पहले ही प्रदेश के निजी बस संचालकों ने इसका पुरजोर विरोध शुरू कर दिया है। रविवार को सागर के कर्रापुर स्थित एक निजी होटल में प्रदेश भर के बस ऑपरेटरों का सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें अलग-अलग जिलों के बस संचालक शामिल हुए। इधर जबलपुर जिले से बैठक में शामिल हुए जबलपुर आईएसबीटी बस आपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल किशोर तिवारी ने बताया कि मध्यप्रदेश बस ऑपरेटर ऑनर्स एसोसिएशन के आव्हान पर हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि यदि सरकार हमारी मांगें नहीं मानती है तो प्रदेश यूनियन के आव्हान पर जबलपुर संभाग में 2 मार्च से बसों की अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दी जाएगी। बैठक में जिन दो मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें पहली यह कि सरकार नई परिवहन नीति को तत्काल वापस ले व दूसरा यह कि बारात परमिट का बढ़ा हुआ टैक्स वापस लिया जाए। बताया जा रहा है कि इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके बाद यदि मांगे नहीं मानी जाती हैं तो फिर 2 मार्च से पूरे प्रदेश में अनिश्चित कालीन हड़ताल की जाएगी।

नहाते वक्त नहर में डूबा युवक

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। चरगवां थाने में नीतेश मेहरा उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम सेमरा ने रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि उसके बडे भाई सचिन मेहरा उम्र 30 वर्ष की शादी हो चुकी है। सोमवार को उसका भाई मोटरसाइकिल से गांव के पास बरखेडा तरफ नहर मे नहाने एवं कपडे धोने के लिये गया था। जब भाई घर नहीं आया तो दोपहर के समय उसने नहर पर जाकर देखा। सीढी के उपर मेढ पर उसके भाई सचिन के कपडे एवं एटीएम कार्ड रखे थे। पास में मोटर साइकिल खडी थी, आसपास तलाश करने पर भाई सचिन का पता नहीं चला। रास्ते में श्याम लाल भूमिया ने बताया कि जब वह नहर से नहाकर आरहा था तभी वहां सचिन एवं कमलेश ठाकुर भी नहा रहे थे। उसने भाई सचिन की तलाश की जो नहीं मिला। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू कर दी है।

सड़क दुर्घटना में घायल वृद्ध की मौत

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। बरेला थाना चौकी गौर में एक निजी हॉस्पिटल से सूचना मिली कि 14 फरवरी को गौर नदी पुल के पास सड़क दुर्घटना में घायल होने से नेमचंद सेन उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम खुक्खम थाना कुण्डम को उपचार हेतु भर्ती कराया गया था। जहां पर उपचार के दौरान नेमचंद सेन की मृत्यु हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को जांच में लिया है।

अत्याधिक शराब के सेवन से युवक की मौत

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। कोतवाली थाने में रूबी सेन उम्र 27 वर्ष निवासी नटबाबा की गली दीक्षितपुरा ने सूचना देकर बताया कि वह पहले किराये के मकान में पंजाब बैंक कालोनी में रहती थी। उसे पता चला कि उसका पति सूरज सेन पंजाब बैंक कालोनी में किराये के मकान में अत्याधिक शराब पीने से खत्म हो गये हैं। जिसपर वह जाकर देखी पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसके पति सूरज सेन उम्र 35 वर्ष की मृत्यु अत्याधिक शराब के सेवन करने से मृत्यु हुई है, पति की मृत्यु पर कोई संदेह नही है। पुलिस ने मामले को जांच में लिया है।

मोबाइल हैक कर निकाले एक लाख

जबलपुर। रांझी थाने में दिनेश चंद्र मीना उम्र 37 वर्ष निवासी तुलसीनगर मानेगांव रांझी ने रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि वह आनलाईन 1 लाख रूपये की वित्तीय धोखाधडी का शिकार हुआ है। यह वित्तीय धोखाधड़ी मप्र राज्य क्षेत्र में हुई है। किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसका मोबाइल फोन हक कर उसके साथ धोखाधड़ी कर छल पूर्वक उसके साथ एक लाख रूपये की धोखाधड़ी की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

जिनसार के विद्यार्थियों ने जानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नर्सिंग में करियर बनाने की प्रक्रिया

जबलपुर (स्वतंत्र मत)

जबलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज एंड रिसर्च (जिनसार) द्वारा 23 फरवरी को वीसी के माध्यम से टैलेंटश्योर के सहयोग से एक कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय नर्सिंग करियर अवसरों, विशेष रूप से जर्मनी के संबंध में व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करना था। सत्र में पात्रता मानदंड, भाषा आवश्यकताएँ, लाइसेंस एवं पंजीकरण प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया तथा जर्मनी में रजिस्टर्ड नर्स के रूप में कार्य करने के लिए उपलब्ध रोजगार अवसरों पर विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में टैलेंटश्योर से विशेष अतिथि माइक वाइल्ड, सीओओ, टैलेंटश्योर, सोम्प्रिता बिस्वास, रिक्रूटमेंट प्रोग्राम मैनेजर (एचआर), टैलेंटश्योर विशेष अतिथियों ने अपने विशेषज्ञ अनुभवों के माध्यम से विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय करियर मार्ग, आवश्यक प्रमाणपत्रों, दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया तथा विदेश में रोजगार की संभावनाओं के बारे में स्पष्ट जानकारी प्रदान की। उन्होंने विद्यार्थियों के प्रश्नों का समाधान भी किया तथा विदेश में नियुक्ति प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया समझाई। यह कार्यक्रम डॉ. प्रिंसे शाजी, प्राचार्य प्रभारी एवं आयोजन अध्यक्ष के नेतृत्व में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की संयोजक अराधना धन्याबाद, विभागाध्यक्ष एवं प्रोफेसर, तथा सह-समन्वयक डॉ. रीना मैथ्यू, सहायक प्राध्यापक रहीं। इस कायक्रम में कुल 40 प्रतिभागियों (विद्यार्थियों एवं संकाय सदस्यों सहित) ने सहभागिता की। कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी और उत्साहपूर्ण संवाद देखने को मिला, जिससे यह सभी के लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक सिद्ध हुआ। कार्यक्रम का समापन अतिथियों एवं आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सफलतापूर्वक किया गया।

क्षतिग्रस्त पुल देखने पहुंचे कलेक्टर-एसपी

जबलपुर (स्वतंत्र मत)

कलेक्ट्र राघवेन्द्र सिंह और पुलिस कप्तान संपत उपाध्यानय ने सोमवार को शहपुरा के पास नेशनल हाईवे में क्षतिग्रस्तद पुल का निरीक्षण किया। उन्होंने वाहनों के आवागमन के लिए पाटन होते हुए मार्ग डायवर्ट किया गया है। इसके साथ ही शहपुरा में कैथरा रेल्वे फाटक से आवागमन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है किए वे तात्काटलिक रूप से वैकल्पिक मार्ग सुनिश्चित करायें। निरीक्षण के दौरान उन्होंने शहपुरा बाइपास तिराहा में ब्लैरक स्पॉकट हटाने के संदर्भ में आवश्यक निर्देश दिये। वहीं अंधमूक बाईपास में भी एनएचआई के अधिकारियों से कहा कि चौराहे पर लाइट ब्लिं कर्सए रेडियम, रेलिंगस, ब्रेकर आदि लगाने के साथ समुचित यातायात व्यकवस्थार सुनिश्चित करें ताकि अंधमूक बाईपास पर होने वाली दुर्घटनाओं को दूर किया जा सके।

हितकारिणी प्रकाशन प्रायवेट लिमिटेड के लिए **प्रकाशक एवं मुद्रक- राम असरानी** द्वारा प्रेस काम्पलेक्स सिविक सेंटर जबलपुर से प्रकाशित एवं हितकारिणी प्रिंटिंग प्रेस, सिविक सेंटर जबलपुर से मुद्रित. **प्रबंध सम्पादक- सुबोध दुबे, सम्पादक- राजेन्द्र मिश्रा,** *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयनार्थ उत्तरदायी।
ई-मेल-**smatjbp1@ gmail.com,** फोन- 0761-2411414, 4032436 समस्त विवाद जबलपुर न्यायालयाधीन. पोस्टल रजि. नं. एसएसपी जबलपुर/13/2026-28, **RNI No. 64561/96.**